हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 15 मार्च, 2018 को अध्यक्ष, डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

15.03.2018/1100/SLS-YK-1

प्रश्न संख्या : 100

श्री पवन नैय्यर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, चम्बा में रावी नदी के ऊपर परेल और सरौल को जोड़ने वाले पुल का निर्माण वर्ष 2002 में शुरू हुआ था और यह पुल वर्ष 2005 में बन कर तैयार हुआ था। परंतु किसी कारणवश 19 अक्तूबर, 2017 को यह पुल गिर गया। इसका निर्माण मै० एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। इस पुल के गिरने से मेरे हिसाब से चम्बा और चुराह की लगभग 100 पंचायतों को परेशानी झेलनी पड़ रही है क्योंकि इससे चम्बा पहुंचने में लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी बढ़ रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी, इससे चम्बा में ट्रैफिक का भी जाम लग रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्योंकि अब तो ये कंपनी वाले भी इसका काम करने के लिए मान गए हैं इसलिए इसका निर्माण जल्दी-से-जल्दी किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह परेल पुल जिसका निर्माण मै० एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से हुआ था, 07.09.2002 को इस पुल का काम शुरू किया गया था और लगभग 1.90 करोड़ रुपये की लागत से इस पुल को बनाकर तैयार किया गया था। अध्यक्ष महोदय, यह पुल वर्ष 2005 में बनकर तैयार हुआ। उसके बाद 19.10.2017 को अचानक सुबह के समय यह पुल गिर गया। इस प्रकार से लगभग 12 साल के बाद यह पुल टूट गया और इसके टूटने से, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि चम्बा जिले के बहुत बड़े क्षेत्र को यह पुल जोड़ता था, उस क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इसका जो कंट्रैक्टर था, उस कंट्रैक्टर से बातचीत करने के पश्चात उसने अपनी ओर से औफर किया है, फिलहाल उसने अपनी तरफ से औफर किया है कि मैं इस पुल का निर्माण करना चाहता हूं। लेकिन

उसके बावजूद भी विभाग उस प्रस्ताव को अग्जामिन कर रहा है कि कंट्रैक्टर किन कंडिशंज पर इस काम को करने के लिए हामी भर रहा है; यह सारी बातें अग्जामिन

15.03.2018/1100/SLS-YK-2

करने और चर्चा करने के बाद ही पता चलेंगी। इसके बावजूद भी एन.आई.टी. हमीरपुर को इस पुल के गिरने के कारणों की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जब यह रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम इस बात को लेकर निर्णय करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राथमिकता यह है कि हम इस पुल को जल्दी-से-जल्दी बनाएं। कंट्रैक्टर अगर बनाना चाहता है और सारी बातों को लेकर सहमति बन जाती है, तो उस स्थिति में भी हम कहेंगे कि कंट्रैक्टर यह काम जल्दी शुरू करे और पुल को जल्दी बनाकर तैयार करे ताकि इस क्षेत्र के लोगों को जो भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उस कठिनाई से उनको राहत दी जाए। अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी, अगर वह परिस्थिति नहीं बनती है तो विभाग खुले मन से इस पुल के निर्माण के लिए अपने स्तर पर भी विचार करेगा।

15/03/2018/1105/RG/YK/1

प्रश्न सं. 101

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'बी' पार्ट में जो उत्तर दिया है उसमें लिखा है कि 'Process of engagement of Consultant for planning work is being undertaken.' So, by planning I think he means design and drawing. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक यह कन्सलटेंट इंगेज हो जाएगा और जो यह ड्राइंग या प्लानिंग का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रामपुर में पहले ही एक यार्ड काम कर रहा है जिस पर 70,00,000/रुपये खर्च हो चुके हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि एक अन्य सब्जी मण्डी यार्ड का शिलान्यास भी किया गया है और इसका अभी फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी अभी नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भविष्य में सब्जी मण्डी वहां खुलना

चाहिए जहां जरूरत हो। मैं सभी माननीय सदस्यों को भी यही कहना चाहूंगा कि पूर्व में शिलान्यास किए गए और लगभग 30 सब्जी मण्डी खोली गईं, जहां पर उनका काम शुरू किया गया जबकि वहां इनकी जरूरत थी ही नहीं। सब्जी मण्डी ऐसे नेशनल हाइवे पर खुले जहां ट्रक की सुविधा उपलब्ध हो और इस सब्जी मण्डी का दिनांक 15 अगस्त, 2017 को शिलान्यास किया गया है। इसके साथ सब्जी मण्डी यार्ड पहले ही वहां है और वहां 70,00,000/-रुपये खर्च हो चुका है। यह 70,00,000/-रुपये रामपुर में ही ए.पी.एम.सी. का है जिसमें तीन चौकीदार रूम हैं, किसान भवन पहले ही वहां है और इसकी सालाना आय सिर्फ 6,00,000/-रुपये है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सब्जी मण्डी नहीं बनाएंगे। सब्जी मण्डी जरूर बनाएंगे। इसका तो अभी फॉरेस्ट क्लीयरेंस होगी। उसके बाद इसका प्राक्कलन तैयार होगा और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब फण्ड्ज उपलब्ध होंगे तब हम निश्चित तौर पर इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कौन सी सब्जी मण्डी की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी पहले तो ये बताएं कि सब्जी मण्डी रामपुर में कहां बनी हुई है? दूसरा जैसा मैंने पहले पूछा कि कंसलटेंट कब तक इंगेज हो जाएगा?

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, रामपुर में सब्जी मण्डी सब-मार्केट यार्ड है और वहां कलैक्शन सेन्टर खुला है, सब्जी मण्डी नहीं है, वहां पर जरूरत ही इसकी थी। वहां पर जरूरत ही इसकी थी। सब-मार्केटिंग यार्ड रामपुर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता

15/03/2018/1105/RG/YK/2

है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। जहां तक इन्होंने कंसलटेंट की बात की है। जैसे ही हमें फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल जाएगी, तो धन की उपलब्धता पर हम कंसलटेंट नियुक्त करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि यार्ड कहां है?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं यार्ड का विजिट नहीं किया है। जो मुझे विभाग के अधिकारियों ने लिखकर दिया है, मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। माननीय सदस्य चाहें, तो मैं वहां जाकर देख लूंगा कि वहां लिखा है कि वहां सब्जी मण्डी है, प्लेटफॉर्म वहां बना है, चौकीदार रूम वहां है, किसान भवन वहां बना है और

70,00000/-रुपये का खर्चा इसमें हो चुका है। नई सब्जी मण्डी डकोलर में हमने प्रपोज किया है। यह डकोलड में है, आलरेडी वहां है, मैं सब-मार्केटिंग यार्ड की बात कर रहा हूं। विभाग ने जो रिपोर्ट दी है, तो वहां पर यह एग्जिस्ट करती है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा है। यदि आप उचित समझेंगे, तो आप माननीय मंत्री जी को ले जाइए।

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस यार्ड की बात कर रहे हैं, there is no yard at Rampur. जिसकी माननीय मंत्री जी बात कर रहे हैं कि उस पर 70,00000/-रुपये खर्चा हुआ है और 6,00,000/-रुपये की आमदनी है। तो रामपुर-बुशहैर में तो कम-से-कम इस तरह का कोई सब्जी मण्डी यार्ड नहीं है। तो नई सब्जी मण्डी बनाने के लिए अभी जो शिलान्यास हुआ है, there is no Sabji Mandi in Rampur.
तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कौन सी सब्जी मण्डी है, रामपुर में कोई सब्जी मण्डी नहीं है। अभी जो नई सब्जी मण्डी का शिलान्यास हुआ है उसके लिए जो कन्सलटेंट इंगेज करना है और इसका काम कब तक शुरू हो पाएगा? माननीय मंत्री जी, मुझे सिर्फ इतना बता दें।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि डकोलर में सब-मार्केटिंग यार्ड है। डकोलड, रामपुर से शिमला की ओर तीन किलोमीटर की दूरी पर है। वहां ऑलरेडी सब-मार्केट यार्ड एग्जिस्ट कर रहा है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि वहां शिलान्यास किया है कि वहां सब्जी मण्डी बने।

15/03/2018/1105/RG/YK/3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह चाहा कि आप ऐग्जामिन कर लें और जो भी यथासंभव हो, करें।

15/03/2018/1110/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 101 क्रमागत----

कृषि मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं एग्जामिन कर चुका हूं और यह विभाग में एग्जिस्ट करता है। डैकॉलर में ऑलरेडी है और यह नया नहीं बल्कि पुराना है। हम उस पर 70 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं और उससे 6 लाख रुपये सालाना इन्कम भी हो रही है। मैंने माननीय सदस्य को कहा है कि बस फॉरेस्ट क्लीयरेंस हो जाए। वहां पर किसान भवन और प्लेटफॉर्म है।

15/03/2018/1110/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 103

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वन विभाग आग लगने के सही कारणों को जानता है? दूसरे, आग लगने से प्रतिवर्ष हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? तीसरे, जो चीड़ की पत्तियां गिरती हैं उनकी वजह से जंगलों में आग लगती है तो उन चीड़ की पत्तियों को जंगलों से इकट्ठा करने हेतु लेबर के लोगों को क्या विभाग कोई पारितोषिक देने की इच्छा रखता है?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। माननीय सदस्य ने जानकारी चाही थी कि गत तीन वर्षों में आग की कितनी घटनाएं प्रदेश में हुई और उससे कितनी हैक्टेयर जमीन को नुकसान हुआ तथा उससे राज्य को कितना वित्तीय नुकसान हुआ। इसके अलावा, इन्होंने यह भी जानना चाहा है कि आग लगने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आग लगने के कारण कुछ तो प्राकृतिक होते हैं और कुछ जान-बूझकर भी आग लगाई जाती है। इसी तरह से कुछ मामलों में गलती से भी आग लग जाती है। इन्होंने यह भी बताया कि चीड़ की पत्तियों के कारण आग का बहुत अधिक खतरा रहता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उस विषय में वन विभाग ने एक प्रपोजल कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज को भेजी है ताकि अपनी सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के अंतर्गत जिन-जिन जिलों में सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वहां से भी कुछ धन प्राप्त हो। चीड़ की पत्तियों को जंगल से इकट्ठा करने के लिए मनरेगा के माध्यम से भी धनराशि उपलब्ध हो और ट्रांसपोर्टेशन का

काम वे सीमेंट फैक्ट्रीज करें तो वह भी एक अनुदान है। अध्यक्ष जी, लिखित प्रश्न में पूछा गया है कि इस सबके लिए वन विभाग कौन से प्रिवेंटिव मैयर्ज अपना रहा है। अध्यक्ष जी, मैं इस मान्य सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा हूं कि जय राम ठाकुर जी की सरकार बनने के बाद इन्होंने हम सबको एक दिशा और प्रेरणा दी कि हर काम की दिशा में यह सरकार कुछ नया करके दिखाएगी। मैं इस मान्य सदन को बधाई देता हूं कि

15/03/2018/1110/MS/AG/3

इनकी प्रेरणा से आग लगने की घटनाओं का पूरे प्रदेश में तुरन्त पता चले, इसके लिए एक टोल फ्री नम्बर पिछले कल 14 मार्च को शुरू हो गया है। वह टोल फ्री नम्बर-1800188097 है। इस टोल फ्री नम्बर पर कोई भी फोन करेगा तो सबको अग्नि की सूचना तुरन्त प्राप्त होगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि यह प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई है। अभी हम मान्य सदन के सभी सदस्यों को एक पुस्तिका भी उपलब्ध करवाएंगे जोकि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों वर्शन में होगी तो पहली बार इस सरकार ने मेनुअल ऑफ फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल मार्च, 2018 तैयार किया है।

15.03.2018/1115/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 103ः----जारी------

वन मंत्रीः------जारी----------

आज प्रातःकाल ही विधान सभा का जो हमारा परिसर है इसके गेट पर माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा इस मैनुअल का विमोचन किया गया जिसमें इसके सम्बन्ध में जानकारी बचाव के सम्बन्ध में दी है। उसके बावजूद भी यदि कोई सुधार की गुंजाइश रहेगी तो उसको हम आगे भी सुधार कर सकते हैं, माननीय सदस्यों के सुझाव यदि आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ एक और कैम्पेन इस सरकार ने प्रारम्भ की है। पहले छोटे जागरुकता अभियान चलते थे लेकिन इस सरकार ने मास स्केल पर आज प्रातःकाल

7.00 बजे रिज मैदान से फोरैस्ट डिपार्टमैंट के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूलों के बच्चे, कुछ चुने हुए पार्षदों द्वारा साढ़े तीन किलोमीटर और एक पांच किलोमीटर की रेस द्वारा जागरुकता अभियान प्रारम्भ किया है। इसके पश्चात जागरुकता द्वारा अग्नि से कैसे बचें, इसके लिए बच्चों को ईनाम भी दिए हैं । इसके साथ दो गाड़ियां पूरे प्रदेश में सारे महिला मण्डल, युवक मण्डल,ग्राम पंचायय, एन0जी0ओज़0 आदि की दो गाड़ियां लगातार दो सप्ताह तक पूरे प्रदेश में घूमेंगी। पूरे प्रदेश को नाटक इत्यादि के माध्यम से भी जागरुक किया जाएगा। माननीय सदस्यों को लग रहा है कि लम्बा उत्तर हो गया है लेकिन प्रिवैंटिव मैटर के बारे में यदि जानना है तो मैं यह कहूंगा कि हमने यह सब किया है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप इस पर स्टेटमैंट दे सकते हैं और वह स्टेटमैंट आप किसी भी समय दे सकते हैं।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ठीक है। जो भी अध्यक्ष महोदय का आदेश है उसमें जो भी स्टेटमैंट होगी उसको देंगे। हम बहुत सी नई चीजें करने जा रहे हैं। माननीय सदस्यों को यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से हम ज़वाब देंगे, लेकिन इसमें हम बहुत अच्छे से रोक-थाम के उपाए करने वाले हैं।

15.03.2018/1115/जेके/एजी/2

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ज्यादा विस्तार से बात को रखा है। मैं केवल स्पैसिफिकली प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो आग लगती है 80 प्रतिशत केस में हमारे लोग खुद आग लगाते हैं। आप असली बात को एड्रैस करने का प्रयास करें। जब हम आग खुद लगा रहे हैं तो क्या आप ऐसा कोई कानून या एक्ट लाना चाह रहे हैं जिसके तहत इसको एक अफैंस डिक्लेयर किया जाए? दूसरे, क्या इस अफैंस को आप ग्रामीण स्तर पर, जहां पर कोई विजिलैंस की प्रोब या कोई ऐसे लोगों को आइडैंटिफाई करने जा रहे हैं जो इस बात की रिपोर्ट करें कि फलां जगह में फलां आदमी ने आग लगाई है? यदि आप जड़ के ऊपर जाएंगे तो हम इस समस्या को हल कर सकते हैं क्योंकि 90

प्रतिशत आग हम लोग खुद लगाते हैं। क्या सरकार कोई ऐसा विचार रखती है कि जहां पर आग लगती है, उसको कैसे रोका जाए और उनको आइडैंटिफाई कैसे किया जाए और उनके अंगेस्ट कोई एक्ट बनाया जाए?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय वन विभाग ने एक Rapid Forest Fire Fighting Force बनाई है। (व्यवधान) माननीय सदस्य मैं आपका ही ज़वाब दे रहा हूं, आपने कहा कि कोई जानकारी यदि देना चाहे।.....(व्यवधान).....

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी के लिए Rapid Forest Fire Fighting Force गठन किया गया है, जिसमें 1900 मेम्बर्ज यानि वॉलंटियर्ज़ बना रखे हैं। आज हमने यह प्रारम्भ किया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी वॉलंटियर के नाते आज प्रदेश में पहल करेंगे और बाकी माननीय सदस्य भी करेंगें। दूसरे, आपका यह कहना कि बहुत से लोग इस आग को लगाते हैं। निश्चित् रूप से कानून के मुताबिक कार्रवाई होना और उसमें यदि कोई संशोधन की आवश्यकता लगती है तो चर्चा के बाद हम इस पर

15.03.2018/1115/जेके/एजी/3

विचार कर सकते हैं क्योंकि यह अत्यन्त आवश्यक है। यह जो हमारी फोर्स है यह भी सब काम करेगी। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

अध्यक्षः लास्ट सप्लिमेंटरी श्री बलबीर सिंह जी।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि चीड़ की पत्तियों के लिए हम प्रदेश के उद्योगों विशेष करके सीमेंट उद्योग से बात करेंगे कि इनको ईंधन के लिए खरीदें। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश से बाहर भी पहले चीड़ की पत्तियां होशियारपुर में जे0सी0टी0 मिल में जाती रही है और लाखों करोड़ों रूपया गरीबों ने कमाया है।

प्रश्न संख्याः 103 क्रमागतः

श्री बलबीर सिंह क्रमागतः

तो क्या दोबारा परमिशन देंगे या प्रदेश से बाहर चल रहे उद्योगों से भी बात करेंगे कि प्रदेश से चीड़ की पत्तियों को बेरोजगार लोग ले जाकर वहां बेचें?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है और इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है कि क्या चीड़ की पत्तियों को यहां के बेरोजगार नौजवान बाहर भी ले जा सकते हैं। यह बहुत अच्छा सुझाव है विभाग इस पर विचार करेगा।

दूसरा, जो माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने पूछा था मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत आग लगाना दंडनीय अपराध है और वन विभाग इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सूचना मिलने पर भारतीय वन अधिनियम के इस प्रावधान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ऐसे लोगों के लिए सबक हो कि वे भविष्य में आग न लगाएं।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, वैसे इन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी परन्तु ये असली मुद्दे पर नहीं आए। जब भी जंगलों में आग लगती है, जितना आप प्रचार-प्रसार कर रहे हैं या जो आप महिला मंडल, युवक मंडल या न जाने कितने मंडलों को जोड़ रहे हैं, इन रैलियों पर करोड़ों रुपये तो खर्च हो जायेंगे परन्तु जंगल की आग नहीं बुझेगी। जब भी जंगल में आग लगती है, जितने भी आपने टास्क फोर्स बनाए हैं या जितना भी आपने प्रचार-प्रसार किया है एक आदमी भी आग बुझाने नहीं आता है। आग हमेशा हाइट से शुरू होती है। हाइट पर जाने के लिए न तो आपके पास कोई साधन है, न ही आपके पास इस किस्म के कोई यंत्र हैं जिससे उसे बुझाया जा सके। सबसे ज्यादा आग बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है। क्या मंत्री महोदय जो करोड़ों रुपया प्रचार-प्रसार में खर्च कर रहे हैं उसके बजाय हैलीकॉप्टर के द्वारा जैसे ही कहीं धुआं निकलता है या आग लगती है वहां पानी पहुंचाकर उसे बुझाने के लिए कोई स्कीम बनायेंगे?

15.03.2018/1120/SS-DC/2

साथ में वन विभाग में जो सभी डी0एफ0ओ0 ऑफिसिज़ या दूसरे बी0ओ0 ऑफिसिज़ हैं वहां पर पानी को पम्प करने के लिए पम्पों का प्रावधान करेंगे?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न पूछा है, अभी हमको सत्ता में आए हुए दो महीने हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बड़े महत्वपूर्ण सवाल पिछले पांच साल में दे नहीं पाए।

दूसरा यह है कि जो आग लगती है निश्चित रूप से पहाड़ों पर लगती है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी लगती है। अध्यक्ष महोदय, इस साल आग लगने का ज्यादा खतरा है क्योंकि इस बार तापमान हमारा ज्यादा है। जो आपने कहा है, देखिये जागरूकता अभियान का मतलब यह है कि लोगों को अंदर से प्रेरणा मिले कि यह सब नहीं होना चाहिए। यह प्रयास हम छोड़ नहीं सकते।

दूसरा यह है कि अभी हमने एक और विचार किया है कि जहां-जहां पर भी हमारे फॉरैस्ट गार्डस, ब्लॉक इंजीनियर, रेंज ऑफिसर्ज़ हैं, जब भी कहीं ऐसी घटना होती है तो तुरन्त चाहे उनको कहीं जाने के लिए गाड़ी हायर करनी पड़े तो उस खर्चे को हम रिइम्ब्रस करेंगे। एक आपने जो सुझाव दिया, वह बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि क्या पहाड़ों पर हैलीकॉप्टर से हम कहीं आग बुझा सकते हैं। अब हम इस विषय पर थोड़ा विचार करेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि पहाड़ों पर कभी-कभी आग की लौ हैलीकॉप्टर को छू जाती है। चर्चा के उपरांत हम इन सारी बातों को देखेंगे। अध्ययन करने के बाद जो उचित लगेगा, वह करेंगे। इस माननीय सदन के सदस्य जो भी बहूमूल्य सुझाव देंगे और ऐसे विचार आयेंगे तो हम निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे। उपयुक्त होगा तो उसे इम्प्लीमैंट करेंगे, अगर यह लगेगा कि नहीं हो सकता तो उसे लागू नहीं करेंगे। लेकिन हर बात का स्वागत है।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। लेकिन उसके बावजूद माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ने जो बात कही

है और उसके साथ में माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी ने अपनी बात कही है उसके बारे में एक तो माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अगर जंगल में कोई भी आग लगाता है तो वह कानून के अन्तर्गत

15.03.2018/1120/SS-DC/3

दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि आग लगाने के बाद उस आदमी को पकड़े कैसे क्योंकि कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता। किसी पर शक होता है तो वह मानने के लिए तैयार नहीं होता।

15.03.2018/1125/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या- 103 **जारी...**

मुख्य मंत्री जारी---

यह परिस्थिति रहती है। लेकिन उसके बावजूद यदि कोई आदमी इस प्रकार से जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो भी हमारी कानूनी व्यवस्था है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, यह मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि हम इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च कर देंगें । मुझे लगता है कि हमारे समाज में दायित्व बोध की भावना होनी चाहिए और समाज के प्रति हमारा भी दायित्व है और जितनी भी हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, उस पर धन लगाना, उस अवेयरनैस कैम्पेन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ राशि खर्च करना आवश्यक है। ट्यूबर क्लोसिस, एच.आई.वी. पर अवेयरनैस कैम्पेन को चाहे हम देश, दुनिया या राज्य के लैवल पर देखें, बजट प्रोविज़न इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले समाज को इस सारी बात की जानकारी होनी चाहिए कि इनसे नुकसान क्या है? आज इस कैम्पेन के लिए मैं वन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। ये ऊर्जावान मंत्री हैं और नए कन्सैप्ट के साथ, नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करने की क्षमता रखते हैं। इन्होंने इस दिशा में प्रयास किया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जहां घने जंगल है, जो हमारी सम्पत्ति है उसकी रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि क्योंकि लोगों को अभी तक व्यवहारिक रूप से कुछ चीजों की

जानकारी नहीं है। लोग जंगलों में जा कर आग लगा देते हैं क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि इससे अच्छा घास उगेगा इस कारण क्या उनको यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप घास चाहते हैं तो उसके लिए जंगल में आग लगाने की जरूरत नहीं है, जंगल हरा-भरा रहना चाहिए। और घास ज्यादा आएगा इसलिए आग लगा दो इसका नुक्सान उनकी जानकारी में रहना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि

15.03.2018/1125/केएस/डीसी/2

कैम्पेन जो पूरे प्रदेश में आज के दिन से शुरू की जा रही है, यह 12 दिन की कैम्पेन है और पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जा कर यह बताना कि जंगलों को बचाना हमारा और पूरे समाज का दायित्व है, इस दृष्टि से यह बहुत अदभुत प्रयास है। मैं इनको बधाई देता हूं।जहां तक नेगी जी ने हैलिकॉप्टर की बात की, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम चीजें व्यवहारिक भी सोचें। हम देखते हैं कि अमेरिका जैसे बहुत ऐसे देश है जो विकास की तुलना में हमसे बहुत आगे हैं लेकिन वहां भी हर जगह यह सम्भव नहीं हो पाता लेकिन उसके बावजूद आपने सुझाव दिया, इसका हम स्वागत करते हैं। जब हम उस स्थिति में कभी पहुंचेंगें तो वह भी कोशिश करेंगें जो आपने सुझाव दिया। इतना मैं कहना चाहता हूं।

15.03.2018/1125/केएस/डीसी/13

प्रश्न संख्या -102

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से इस विषय में कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो हमारी डीसैंट्रल प्लैनिंग है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें तीन पहलू है। एक शैल्फ को बनाना, उसके बाद उसको अमल करना और उसकी मोनिटरिंग करना। मैं समझता हूं कि 14वें वित्तायोग ने भी एक जिम्मेवारी सबसे निचले स्तर पर प्लैनिंग के लिए और कार्यों को करने के लिए दी है लेकिन हमारे सबसे निचले स्तर पर उस शैल्फ को बनाने के लिए जो कम्पीटैंट ऑफिसर है,

कम्पिटैंट इंजीनियर हैं, चाहे पंचायत का असिस्टैंट है, जूनियर इंजीनियर है वह आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है।

15.3.2018/1130/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 102----- क्रमागत

श्री राकेश सिंघा------- जारी

इसी कारण आपकी भी पुरानी सरकार से शिकायत रही है कि जो नेशनल हाई-वे आए हैं उनकी डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट नहीं बनी। इसी तरीके से इस विषय में भी अगर हमें ग्रास रूट प्लानिंग को सफल बनाना है तो उसके लिए क्या हम निचले स्तर पर स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं या नहीं? दूसरा, जब हम इसको योजना बना रहे हैं तो यह अगर साल के शुरू में होगी तब सम्भव है कि इसमें कुछ कार्य होगा। अगर हम बीस सूत्रीय समीक्षा की बैठक या जिला की प्लानिंग की मीटिंग को साल के अंत में करेंगे तो यह कार्य सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जिला शिमला में पिछले वित्तीय वर्ष में बीस सूत्रीय समीक्षा और जिला की प्लानिंग की मीटिंग कब हुई है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत व्यावहारिक प्रश्न किया है। इन्होंने इसकी शैल्फ की प्रैपेरेशन के बारे में बात की है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से यह सारी चीजें होनी चाहिए उस दृष्टि से वह अभी हो नहीं पा रही है। हालांकि इसके लिए हमारे 14वें वित्तायोग द्वारा बजट का अलग से प्रावधान भी किया गया है। लेकिन इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में हमारे इंजीनियरिंग विंग को स्ट्रैन्थन करने की आवश्यकता है। उसमें कमी है और इस बात को हम आज भी महसूस करते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने जिला स्तरीय योजना विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम की अनुश्रवण समिति की बात की है उस समिति के माध्यम से हमारा जो डीसैंट्रेलाईज प्लानिंग का पैसा है उसका निर्धारण किया जाता है। उसकी प्रतिशतता का तयशुदा कार्यक्रम है इसमें 60% on the basis of population and 40% on the basis of geographical area. यह उसका आधार है लेकिन उसके बावजूद जो बात कही गई है

तो यह एक व्यावहारिक पक्ष है जिसको हमें समझना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने District Planning Development and 20 Point Programme Review Committee का जिक्र किया उसमें सारे विषयों पर चर्चा करने के बाद जो निर्णय करना होता है कि कौन सी स्कीम कितने बजट

15.3.2018/1130/av/hk/2

प्रावधान के साथ स्वीकृत होनी चाहिए, लेकिन यह उस तरह से नहीं हो पा रहा है। आम तौर पर यह हो रहा है कि जो भी स्कीम हम लेकर जाते हैं उसको डी0सी0 के माध्यम से स्वीकृत करवाकर लाते हैं, उसमें यह एक कमी है। जहां तक आपने जिला शिमला की बैठक के बारे में पूछा है तो इसके बारे में अभी इग्जैक्ट डेट नहीं है, अगर आपको डेट चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अतिरिक्त डी0सी0पी0 के तहत जो विधायक क्षेत्र विकास निधि, मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना, विकास में जन सहयोग इत्यादि कम्पोनैंट हैं जिसके अंतर्गत हम काम करते हैं। अगर हम शिमला जिला की बात करें जिसमें आपने पूछा है कि कितना पैसा खर्च किया गया है तो उसमें कुल मिलाकर पिछले तीन वर्षों में 51.79 करोड रुपये खर्च किए गए हैं।

15.3.2018/1135/TCV/HK-1

प्रश्न संख्या : 102----- क्रमागत

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मूल मंशा यह है कि जैसे हम साल के शुरू में ये बजट पेश कर रहे हैं और उसके बाद पूरे साल कार्य होगा। इसका सारा अप्रूव्ल एक कमेटी में होना है। अगर उस कमेटी की बैठक हम साल के शुरू में नहीं करेंगे और उसको लॉ के प्रावधान में कंप्लसरी नहीं करेंगे, तो ये सम्भव नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार एक स्टैच्यूटरी कानून लाएगी और कमेटी जिसने ये पारित करना है, चाहे बीस सूत्रीय रिव्यू हो या जिला प्लानिंग की हो, वह साल के शुरू में, इस बजट के समाप्त होने के साथ ही उसकी मीटिंग शुरू करें। जिससे पूरे साल के लिए वह कार्य अप्रूव्ड हो जाये और फिर उस पर काम चलेगा। तब तो ये संभव हैं, नहीं तो यह स्टॉप-गैप में

चलता रहेगा। कुछ काम जिलाधीश के पास आएगा, उसे यदि शक्ल पसंद आई तो 'यस' हो जायेगा और यदि शक्ल पसंद नहीं आई तो 'नो' हो जायेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस राशि को किसी फ्रेमवर्क के अंदर बांधना होगा और वह तब संभव है, जब हम इसको स्टैच्यूटरी लॉ से मज़बूत करेंगे। क्या आपकी सरकार इस कार्य को करेंगी?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वर्ष में हमारा बजट प्रस्तुत होता है। माननीय विधायक ने अच्छा सुझाव दिया है। इसके साथ ही हमने जो बजट प्रावधान किया है, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए, नीचे के स्तर पर सम्पूर्ण योजना बनाने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम समय रहते इन सारी चीजों के लिए योजनायें बनाएंगे तो हम सारे साल भर सारे काम को टाईमफ्रेम और प्रोपर प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। **इस हिसाब से this is good suggestion for action, ऐसा मैं मानता हूं। इन्होंने सुझाव दिया है कि इसमें स्टैच्यूटरी प्रोविज़न किया जाये, हम इसको एग्ज़ामिन करेंगे।**

15.3.2018/1135/TCV/HK-2

प्रश्न संख्याः 104

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में जहां भी हाईडल प्रोजैक्ट्स लगें हैं, वहां पर जो बजट की लागत है, उसका डेढ़ प्रतिशत् उस इलाके के विकास कार्य के लिए, 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, सुनिश्चित किया गया था। उसी समय लोकल एरिया डेवैल्पमैंट फंड को इम्पलीमैंट करने के लिए लोकल एरिया डेवैल्पमैंट कमेटी का गठन किया गया और उसमें जिला किन्नौर, जो जन जातीय इलाका है, उसका जो चैयरमेन होता है, वह स्थानीय विधायक होता है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि विधायक यदि कांग्रेस का होगा तो रखा जायेगा और यदि भारतीय जनता पार्टी का होगा तो नहीं रखा जायेगा। इस प्रकार की बात नहीं है। वर्ष 2006 से लगातार लोकल एरिया डैवेल्पमैंट कमेटी का अध्यक्ष स्थानीय विधायक रहा है। परन्तु सरकार बदलने के बाद, आपने यहां पर इसका जवाब दिया है कि uniformity और कार्य को smooth चलाने के लिए ऐसा किया गया है। आप बतायें कि क्या अभी तक ये smooth नहीं चल रहा था। वर्ष 2006 से लगातार किन्नौर से चाहे कांग्रेस का विधायक चुनकर आया या भारतीय जनता

पार्टी का आया, वह उसका अध्यक्ष रहा है। आज की तारीख में सबसे बढ़िया लोकल एरिया डैवेल्पमैंट का कार्य जिला किन्नौर में हुआ है। आपने इसको राजनैतिक द्वेष से, किन्नौर के जनमत का अपमान करते हुए बदला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जरूरत पड़ी, पांगी, भरमौर और लाहौल स्पिति में भी स्थानीय विधान इसके चेयरमैन रहे हैं, तो फिर किन्नौर में क्यों इसका चेयरमैन बदला गया? ये आपने राजनैतिक द्वेष से किया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या 2006 से 2017 तक किन्नौर में जो बढ़िया कार्य हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए, विधायक को दोबारा इस समिति का अध्यक्ष बनाएंगे?

15-03-2018/1140/NS/YK/1

प्रश्न संख्याः 104 ------**क्रमागत**।

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जहां तक राजनीतिक रंग देने की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से विधायक महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह ठीक है, हाईड्रो पॉलिसी वर्ष 2006 में बनी। इस पॉलिसी के बनने के बाद जैसा आपने कहा कि 5 मेगावाट तक जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी टोटल कोस्ट का 1 प्रतिशत लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड में लगेगा और 5 मेगावाट से ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसका डेढ़ प्रतिशत लगेगा। आप यह गलत बोल रहे हैं। आपके ध्यान में यह नहीं हैं कि वर्ष 2006 से पॉलिसी थी। परन्तु वर्ष 2008 में जब पॉवर पॉलिसी आई और वर्ष 2009 में इस पॉवर पॉलिसी के अनुरूप जितने on going और आगे लगने वाले प्रोजेक्ट्स थे, उसमें एक प्रतिशत जो पॉवर जेनरेशन होगी, लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड के अंदर इसका प्रावधान रखा गया था। आप कह रहे हैं कि वर्ष 2006 से नहीं है। मेरे पास विभाग की पूरी रिपोर्ट है। आप इस बात को सुन लीजिये। वर्ष 2009 के बाद इसमें जो कमेटी बनाई गई थी तो इस कमेटी में जिले के अंदर जिलाधीश महोदय ही चेयरमैन हुआ करते थे। मैं पूर्व सरकार में मंत्री रहा हूं। मैं यह नहीं कह सकता हूं। मैं उस वक्त भी सरकार में था और अब भी हूं। वर्ष 2012 से पहले यह प्रथा शुरू हुई थी और उसमें किन्नौर के विधायक को चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद भी यह प्रथा चलती रही। वर्ष 2014 में भरमौर के विधायक/मंत्री महोदय को भी ख्याल आया तब उस समय इसको रिवाईज़ किया गया था और इसमें

भरमौर को भी शामिल किया गया। नेगी जी, आपने यहां एक बात कही कि हम ट्राईबल के लोगों के हित की बात नहीं करते हैं। मैं पूर्व में भी सरकार का मंत्री रहा हूं तो मैं पूछना चाहता हूं कि लाहौल और स्पिति के अंदर कौन चेयरमैन था? क्या यह ट्राईबल में नहीं था?

श्री जगत सिंह नेगीः यह आप हमसे पूछ रहे हैं।

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः नहीं-नहीं। मैं पूर्व सरकार में मंत्री था और मैं कह रहा हूं कि यदि आप उस सरकार की बात कर रहे हैं तो उस सरकार के अंदर भी गलती हुई है। क्योंकि उस समय लाहौल और स्पिति के विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन उनको कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया था। ---(व्यवधान)---

15-03-2018/1140/NS/YK/2

अध्यक्षः कृपया माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें।

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः इसलिए इस बात को कहना कि ट्राईबल क्षेत्र के लोगों के साथ अनदेखी हुई है, यह गलत है। क्योंकि लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड जो है उसको हर जिले के अंदर बांटने की प्रथा है। यह ट्राईबल क्षेत्र के लिए ही नहीं है बल्कि प्रदेश के हर ज़िले के लिए है। जितने प्रोजेक्ट्स जिस जिले के अंदर हैं, उस जिले के अंदर LADA का चेयरमैन डिपटी कमीश्नर को रखा गया है। हमने उसमें प्रावधान किया है कि कमेटी के अंदर विधायक नहीं है परन्तु स्पैशल इन्वाइटी है। माननीय सदस्य आपको पता है और आप इसमें कई सालों तक चेयरमैन रहे हैं। आपको ज्ञात है कि इसमें डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ फंड्ज़ कैसे होता है? मैं इस माननीय सदन के अंदर इस बात को नहीं रखूंगा कि किस तरीके से प्रावधान किया गया है और कितना पैसा कहां बांटना है? हालांकि, अब माननीय मारकण्डा जी सरकार में मंत्री हैं और अब यदि लाहौल और स्पिति की बात होती तो इनको चेयरमैन बना दिया जाता। इस प्रथा को खत्म करने के लिए और सुचारू रूप से पूरे प्रदेश के अंदर लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड को प्रोपर तरीके से बांटा जाये तो इसके लिए हमने डिप्टी कमीश्नर के माध्यम से ही पैसे का आबंटन करने का प्रयास किया है।

इसमें कोई अनदेखी नहीं हुई है। माननीय सदस्य, आपके पास यह सूचना गलत है कि वर्ष 2006 से किन्नौर को दिया गया था।

15.03.2018/1145/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः 104...जारी

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से यहां पर जवाब दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आपके विभाग ने आपको तथ्य बताए हैं, वे ठीक नहीं है। पहले आप उन तथ्यों को ठीक कीजिए अन्यथा आप सारे-का-सारा जवाब गलत दे रहे हैं। वर्ष 2006 में पहली बार लोकल एरिया डिवैलपमैंट फंड (LADA) का नोटिफिकेशन हुआ। वर्ष 2006 में किन्नौर के विधायक को नोटिफाइड करके चेयरमैन बनाया गया। वर्ष 2008-09 में जब आपकी सरकार थी तो यह पॉलिसी जे.पी. कम्पनी के कहने पर चेंज हुई। इसमें एक ऐसा क्लॉज़ डाल दिया कि लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड (LADA) के तहत जो कम्पनी ने अपनी मर्ज़ी से काम किया है, उसमें छूट देने की कोशिश की गई। जब दोबारा हमारी सरकार सत्ता में आई तो उस क्लॉज को हटा दिया गया । यह तो एक अलग बात है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप विधायक की संस्था को कमजोर करना चाहते हैं? क्या प्रोटोकोल में विधायक जो डी.सी. से ऊपर है, चीफ सैक्रेटरी से ऊपर है, उसको नीचे करना चाहते हैं? यहां पर भरमौर, निर्वाचन क्षेत्र के माननीय विधायक, लाहौल और स्पिति, निर्वाचन क्षेत्र के माननीय मंत्री जी बैठे हैं। क्या आप इनको नीचे करना चाहते हैं? क्या आप केवल जगत सिंह नेगी को बाहर करने के लिए, इन दोनों को भी बाहर करना चाहते हैं? लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड के चेयरमैन को न तो गाड़ी मिलती है, न कोई बंगला और न ही कोई तनख्वाह मिलती है। विधायक LADA के तहत जो पैसा आता है उस पैसे को अपने इलाके में सही रूप से खर्च करें और यह विधायक के लिए एक सम्मानजनक पद भी है। क्या आप इसकी अनुपालना करेंगे कि विधायक को दोबारा से चेयरमैन नियुक्त किया जाए?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की मंशा है, विधायक का स्तर बहुत ऊपर है। आप विधान सभा में बैठे हैं। अगर आपको यह लग रहा है कि फंड्स का डिस्ट्रिब्यूशन गलत हो रहा है तो आप विधान सभा के माध्यम से यहां पर प्रश्न पूछ सकते हैं। विधायक के बारे में जो आप

कह रहे हैं उसके लिए पॉलिसी बनी थी और उस पॉलिसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो जनरेशन होगी उसका 1% इस पॉलिसी के अंदर बनाया गया था। आप कह रहे हैं कि विधायक को चेयमैन नहीं बनाया गया। लाहौल और स्पिति के पूर्व विधायक को भी चेयरमैन नहीं बनाया गया था। वहां तो आपने पूर्व विधायक को साइड लाइन कर दिया, जबकि वे आपकी पार्टी के ही सदस्य थे। यह अनदेखी उस सरकार के अंदर हुई है। अब अनदेखी की कोई बात नहीं है। आप वहां के स्थानीय विधायक है। यदि आपको लगता है कि इसका आबंटन गलत हो रहा है तो इसकी जानकारी आप विधान सभा के अंदर ले सकते हैं। जो पैसे का आबंटन हो रहा है, वह गाइडलाइन्ज के माध्यम से हो रहा है। पंचायत ग्राम सभा में बताया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या-क्या काम होने हैं। उसके हिसाब से ही पैसे का आबंटन किया जाता है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने लाहौल और स्पिति के विधायक की बात की। माननीय मंत्री जी तो पिछली सरकार में भी मंत्री थे इसलिए मैं ज्याद विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह माननीय विधायकों के संस्थान का सवाल है। जो विधायकों को चेयरमैन्स बनाने की बात है, तो विधायक पहले भी बनते रहे हैं। अगर कहीं किसी रेजीम में ऊंच-नीच हो गई, कभी आपके भी हुई हेागी, हमारे भी हुई होगी। लेकिन एम.एल.एज. के इन्स्टिट्यूशन्ज को स्ट्रैंथन करना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज आप मंत्री बन गए और आपको एम.एल.एज. के इन्स्टिट्यूशन्ज की परवाह नहीं है। यह तमाम एम.एल.एज.

का मसला है और जैसा कहा भी गया है कि न तो आपने इसके लिए कोई कार देनी है , न कोठी, न बंगला और न ही कोई नौकर-चाकर देने हैं। आपने इसके लिए कुछ भी नहीं देना है। यह एक एम.एल.ए. के सम्मान का सवाल है। ऐसे छोटे-छोटे मसले हैं, जिनमें एम.एल.एज. को नीचे डाला गया है। जैसे की हैल्थ कमेटी में नीचे डाला गया है। एम.एल.एज. का सम्मान बना रहे। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए रिव्यू करेंगे?

15.03.2018/1145/RKS/YK-3

अध्यक्षः वैसे तो यह मेरा विषय नहीं है। (...व्यवधान...) एक मिनट।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष जी, हमें तो आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्षः 'रेणुका विकास बोर्ड' का अध्यक्ष, श्री रेणुकाजी, निर्वाचन क्षेत्र का विधायक है लेकिन 'माता बाला सुन्दरी ट्रस्ट' का सदस्य नाहन का विधायक नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया आप बोलिए।

15.03.2018/1150/बी0एस0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्याः 104...जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सचमुच पांच वर्ष हम इस तरफ थे, हम विनम्र आग्रह करते रहे कि यह एक जो विधायकों का संस्थान है, आप भी सभी माननीय सदस्यों के प्रति संवेदनाएं रखें जो संवेदनाएं आपको अभी याद आ रही है। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि जो हमारे माननीय सदस्य विधान सभा में चुन कर आए हैं, उनका एक स्थान है, एक सम्मान है। उनको ठेस पहुंचाने की कोई भी हमारी मंशा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उसके पर विचार करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति मात्र दो या अढ़ाई महीनों में पैदा नहीं हुई। विधायक पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक प्रोग्राम में एक बार नहीं अनेक बार जलील होते रहे। उस समय

माननीय मुख्य मंत्री व मंत्री भी वहां उपस्थित थे। उस वक्त हम कहते रहे, अध्यक्ष महोदय, हमने अपने विधान सभा क्षेत्र में इस बात को एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। पूर्व मुख्य मंत्री हमें बहुत प्यार करते हैं, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं लेकिन परिस्थियां ऐसी हो जाती थीं। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, चार बार का विधायक उस वक्त था, मैं कैबिने मंत्री रह चुका हूं लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बोलने के बाद भी जो हारे हुआ लोग थे उन्हें भाषण करने के लिए खड़ा कर दिया जाता था। ऐसा हुआ है। जो विधायक प्राथमिकता की योजना अपने हाथों से बनाई है, जिन्हें हम हराकर आए हैं जिनकी जमानत जब्त करके आए हैं उनका नाम बड़े-बड़े अक्षरों में उन योनाओं के पट्टप पर साथ में लिखा जाता था। जिस विधायक ने उस योजना को डाला उसका वहां नाम ही नहीं होता था। .....(व्यवधान)..... अध्यक्ष महोदय, यह लम्बा विषय है।

अध्यक्षः अग्निहोत्री जी कृपया बैठिए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है कि यह विषय को अलग दिशा में ले जा रहे हैं, यह हकीकत है और अगर ईमानदारी से बात करें तो यह सारी बाते रूकनी चाहिए। हमें शुरूआत करने की कोशिश तो करनी चाहिए । हम इस बात के लिए खुले मन से हैं कि यह सारी चीजे ठीक तरह से होना चाहिए। हमारे नाम के पत्थर कितनी जगह,
15.03.2018/1150/बी0एस0/ए0जी0-2

कितनी बार तोड़े गए? कितनी जगह मामले दर्ज पड़े हैं लेकिन उसके बावजूद टूटते गए और तौड़ते गए। अध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को ले करके सोचने की आवश्यकता है। आपने सुझाव दिया है हम खुले मन से सोचेंगे। विधायक हमारे लिए चाहे इस पक्ष का है, चाहे उस पक्ष का है, वह महत्वपूर्ण है। उसके प्रति सम्मन हमारे मन में रहेगा। यही में अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता कि इनकी भावना आहत हुई है, लेकिन इनकी भवना तब आहत नहीं हुई जब

लौहन-स्पिति के विधायक को आपकी ही पार्टी में आपकी ही सरकार में विधायक होते हुए भी लाडा का चेयरमैन नहीं बनाया। वहां पर डेप्टी कमीशनर चेयरमैन था। मुझे ऐसा लगता है कि यह भाव अभी-अभी, जल्दी-जल्दी आ गया। इसका बड़ा इतिहास है ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

15.3.2018/1155/DT/AG-1

प्रश्न संख्याः 105

श्री राजेश ठाकुर (गगरेट): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तहसील की घोषणा पूर्व सरकार ने 2016 को की थी और यह किराए की दुकान पर चल रही थी। इसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। चुनाव के मात्र दो महीने पहले बज़री की दो ट्राली फैंक कर इसका उद्घाटन करने की कोशिश की गई थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इसकी फिर से प्रक्रिया शुरू की है।

15.3.2018/1155/DT/AG-2

प्रश्न संख्याः106

श्री अरूण कुमारः क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि जो डी.पी.आर. केन्द्र सरकार को भेजी हैं, वह कब-कब भेजी गई, उसका वर्षवार बौरा दें? क्या कारण है कि इस योजना में विभाग ने बहुत कम राशि प्राप्त की है। क्या भविष्य में मंत्री माननीय विधायकों से विधायक प्राथमिकता लेने का आश्वासन देगें।

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पंचायतों की तरफ से निवेदन आता है। माननीय विधायकों से पूछा जाता है उसके बाद ही हम डी.पी.आर. तैयार करते हैं। डी.पी.आर. में हम देखते हैं कि क्या वह स्कीम फिजिबल है। उसके बाद ही हम स्कीम बनाते है। जहां तक एग्रीकल्चर विभाग का स्वाल है हम सीधे ही एग्रीकल्चर विभाग की डी.पी. आर. बनाते हैं। फिर भारत सरकार को जाती है। जहां तक एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर विभाग का सवाल है, एक एक्शन प्लान बनाते हैं। जैसे ही भारत सरकार से पैसे आते हम डी.पी.आर. तैयार

करते हैं। माननीय विधयक ने अपने क्षेत्र के बारे जाना चाहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि लधु सिंचाई व मध्यम सिचांई योजना के 54 लाख, उद्यान विभाग के लिए 2.22 लाख रुपये, कृषि विभाग के लिए 19.17 लाख रुपये तथा ग्रामीण विकास विभाग के लिए लगभग 29.81 हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं।

राकेश पठानियाः अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जाना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के तहत जिला कांगड़ा मैं कितना पैसा आया है? क्या इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा सकता? किस- किस कॉम्पोनेंट में क्या- क्या व्यवस्था की गई है?

15.3.2018/1155/DT/AG-3

कृषि मंत्री : महोदय, जहां तक कांगड़ा जिला का सवाल है जिला कांगड़ा में 15 चुनाव क्षेत्र हैं। इसमें 64.81 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं और माननीय सदस्य ने जाना चाहा है कि हम किन-किन सैक्टर पर पैसा खर्च करते हैं? अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं पर बल दिया जाता है। पी.एम.के.एस.वाई. के अन्तर्गत हर खेत को पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इसकी डी.पी.आर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर विभाग तैयार करते हैं। सुक्ष्म सिंचाई योजनाओं की डी.पी.आर. होर्टिकल्चर तैयार करता है।

प्रश्न काल समाप्त

15.03.2018/1200/SLS-DC-1

अध्यक्ष : मुझे माननीय सदन को सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है हालांकि मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो भी चुकी होगी लेकिन मैं, मान्य सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ई-विधान प्रणाली को दिनांक 27 फरवरी, 2018 को हैदराबाद में राष्ट्रीय ई-गवर्नैंस पुरस्कार डॉ० जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इससे पूर्व भी इस प्रणाली को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि CSI - Nihilent National

eGovernance award, SKOCH Silver National eGovernance Award and State Civil Services Award. इस उपलब्धि के लिए मैं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री बी.बी.एल. बुटेल जी व विधान सभा सचिवालय को बधाई देता हूं और प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ई-विधान प्रणाली को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।...(व्यवधान)...

मुकेश अग्निहोत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मौजूदा सरकार द्वारा जो संस्थान बंद किए जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम उस बात की ओर इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं।

अध्यक्ष : इसके लिए आप नियमानुसार नोटिस दें और नोटिस देकर चर्चा करें। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये संस्थान जनहित में खोले गए थे। (अख़बार दिखाते हुए) यह आज का अमर ऊजाला समाचार-पत्र है जिसमें समाचार प्रकाशित हुआ है कि करसोग और दलाश में बहु-तकनीकी संस्थान बंद किए गए। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप इस पर चर्चा के लिए नोटिस दे दें।...(व्यवधान)... नोटिस देकर चर्चा कर लें।

15.03.2018/1200/SLS-DC-2

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लगातार पूर्व सरकार के फ़ैसलों को पलटने का सिलसिला चल रहा है जबकि ये संस्थान प्रदेश के दूर-दराज़ इलाकों में खोले गए हैं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप जानते हैं कि इस तरह की चर्चा आप नोटिस देकर ही कर सकते हैं।...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, यह जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ का विषय है। हम इस तरह संस्थानों को बंद करने का विरोध करते हैं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप नोटिस देकर इसके लिए चर्चा मांगिए।...(व्यवधान)... मुकेश जी, यह ठीक नहीं है, पहले आप इसके लिए नोटिस दीजिए।...(व्यवधान)**...Not to be recorded.** ...(व्यवधान)... आप नोटिस दीजिए; इसके लिए आप आज ही नोटिस दीजिए। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठ जाइए।...(व्यवधान)...मुकेश जी, आप नोटिस दीजिए, हम इसमें चर्चा अलौ करेंगे। अभी पूरा महीना सदन चलेगा, आप नोटिस दीजिए। ...(व्यवधान)...माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप अपनी बात रखिए।

15/03/2018/1205/RG/DC/1

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिना किसी मुद्दे के खड़े हो रहे हैं।---(व्यवधान)----

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य शोर-शराबा एवं नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

अध्यक्ष महोदय, यह एक नई परम्परा शुरू हो गई, इन्होंने न कोई नोटिस दिया और न ही इनके पास कोई मुद्दा है और अभी तक सरकार ने किसी संस्थान के बारे में कोई बात नहीं की। जो यहां पर एक संस्थान के बारे में कहा गया है, तो संस्थान के बारे में बाकायदा मंत्री जी ने विधान सभा में स्टेटमेंट दी है। इनका न तो कोई नोटिस आया है कि कौन सा संस्थान बंद किया है और ये बार-बार अखबार दिखा रहे हैं और वह भी नीचे-नीचे ही दिखा रहे हैं, अखबार को ऊपर उठाकर नहीं दिखाते कि किस अखबार में निकला है कि इनका कोई संस्थान बंद हुआ है। समीक्षा करना किसी भी सरकार की जिम्मेवारी भी है और उसका हक़ भी है। संस्थान खोलने के बारे में पिछले 6 महीनों के निर्णय जो इन्होंने कागज़ों पर लिए हैं जिसमें न तो अभी तक कोई पद सृजित किए गए, न बजट का प्रावधान हुआ है और ही वित्तीय स्वीकृति है। इन्होंने जितने भी संस्थान खोले हैं, उनकी मात्र अधिसूचना जारी की है या मात्र शिलान्यास कर दिया या कहीं शिमला से फट्टा भेज दिया कि यहां यह

तख्ता लगा दो। इसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र में अमान्य है। मेरा विपक्ष से निवेदन है कि यदि इनके पास कोई निश्चित निर्णय सरकार की ओर से आता है जो जनहित में नहीं है, तो ये उसकी बात करें और उसके लिए प्रॉपर नोटिस दें। अगर इनके पास कोई इस प्रकार की सूचना है जिसको ये समझते हैं कि हम बिल्कुल लोकतंत्र की परम्पराओं के विरूद्ध कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप खड़े होकर मामला उठा सकते हैं। मामला भी इस चीज का उठा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जमीन पर भी नहीं करता, अखबारों में नहीं करता है और कहीं निर्णय में भी नहीं करता है। तो इन चीजों से सदन का समय नष्ट हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता के टैक्स का जो पैसा सदन के ऊपर या हम सब पर खर्च होता है, इस तरह तो उसका दुरूपयोग हो रहा है और उसका नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई इनको करनी चाहिए। क्योंकि यदि ये किसी मुद्दे के ऊपर बात करें, तो सदन से बहिर्गमन कर सकते हैं। यह

15/03/2018/1205/RG/DC/2

लोकतंत्र में मान्य है, लेकिन बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस या बिना किसी परम्परा के यह इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष करता रहेगा, तो यह हिमाचल प्रदेश की जनता का अपमान है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो मेनडैट दिया है, उसका अपमान ये कर रहे हैं। इस बात के लिए इनकी जितनी निन्दा की जाए, वह कम है। हम विपक्ष के इस प्रकार के व्यवहार की घोर निन्दा करते हैं एवं भर्त्सना करते हैं और ऐसा करना लोकतंत्र में अमान्य है।

15/03/2018/1205/RG/DC/3

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों की चिन्ता यह है कि इनकी कोई खबर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में नहीं बन पा रही थी, तो इन्होंने सोचा कि कुछ करो। इसलिए इन्होंने सदन से बहिर्गमन किया है और जिस मुद्दे पर इन्होंने सदन से बहिर्गमन किया या

क्या किया, मुझे पता नहीं, क्या रिकॉर्ड किया। लेकिन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं, कुछ कहते-कहते चले गए। अच्छा होता कि कुछ सुनते-सुनते भी जाते।

अध्यक्ष महोदय, बंद तो वह चीज होती है जो कहीं खुली हो। अन्तिम दौर में सिर्फ राजनीति मकसद से खोला गया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई संस्थान खोला गया जिसका विकास से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था। क्षेत्र का विकास करना है, तो शुरू में करते। संस्थान खोलते, उसको चलाते, तो वहां स्टाफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि देते, लेकिन अन्तिम कुछ दिन बच गए, तो आपको पॉलिटैकनिक कॉलेज दे दिया, डिग्री कॉलेज दे दिया, आपको पी.एच.सी., सी.एच.सी. इत्यादि दे दी। ऐसा करते-करते इन्होंने सैंकड़ों संस्थान जाते-जाते खोल दिए और नोटिफिकेशन कर गए।

15/03/2018/1210/MS/HK/1

मुख्य मंत्री जारी----

एक दिन मैं अपने लोक निर्माण विभाग का रिव्यु कर रहा था तो मैं देख रहा था कि लोक निर्माण विभाग के 15 सब-डिवीजन्ज खोले गए हैं जिनमें से 7 में वित्त विभाग ने लिखा है कि 'sanction not concurred'. जब वित्त विभाग ने स्वीकृति नहीं दी उसके बावजूद भी आपने कागज का टुकड़ा पकड़ाकर कह दिया कि हमने नोटिफिकेशन कर दी है। मुझे लगता है कि यह बात कोई बहुत व्यवहारिक नहीं है। हमने एक बात को लेकर निर्णय लिया है और पहले ही दिन घोषित किया है कि पिछली सरकार के अंतिम 6 महीनों के दौरान जो सही निर्णय होंगे, जिनका विकास ही मकसद होगा, उन सारी चीजों को हम उस तरह से देखेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दृष्टि से पिछले 6 महीने में कुछ निर्णय संस्थान खोलने के बारे में इन्होंने लिए हैं और जिन संस्थानों का सिर्फ नोटिफिकेशन किया है, जमीन पर वहां कुछ भी नहीं है, उनको हम उस तरह से देखेंगे। आजादी के 70 साल बाद एक नई परम्परा को हमने पहली बार देखा है कि शिमला में एक बड़ी-भारी दीवार ढूंढी गई और उस दीवार पर फट्टे टांग दिए गए जिसमें कोई सुलह का, कोई सिरमौर का, कोई नाहन का और कहीं कोई सिराज का फट्टा था। एक जगह उन फट्टों को लगाकर उद्घाटन/शिलान्यास की रस्म की गई और उन फट्टों को यहां से उक्त स्थानों पर पहुंचाकर कह दिया कि आपको

अस्पताल दे दिया, आपको कॉलेज दे दिया। मुझे लगता है कि ये जो किया है इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता है। फिर भी इसके बावजूद हमने खुले मन से कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। लेकिन जो संस्थान खुला ही नहीं है, जिसके लिए बजट का प्रोविजन ही नहीं है जिसमें सारी चीजों की व्यवस्था नहीं है और न ही शुरू किया है, ऐसे निर्णयों पर विचार करने के लिए हमने कहा है। उस दृष्टि से कुछ निर्णय करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे लेकिन जहां आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से हमने कहा कि पिछले 6 महीने के निर्णयों पर हम पुनर्विचार करेंगे और उसके बाद जो उचित लगेगा उस पर निर्णय देंगे। हमने सिर्फ इतनी बात कही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर, खबर बनाकर बाहर यह कहने

15/03/2018/1210/MS/HK/2

की कोशिश कर रहा है तो लोग बाहर आपका मजाक भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से उसका आपको लाभ होने वाला है तो आप लोग उस तरफ नहीं होते बल्कि इस तरफ होते। आपने अपने हाथों से अपना स्मारक बना दिया जो आने वाले समय में याद रहेगा। लोग इसको नहीं भूलेंगे। इसलिए जो आपने किया है उसके बावजूद हमारी इस तरफ वालों की कोई ऐसी भावना नहीं है। हम खुले मन से सब बातों पर विचार करेंगे।

अध्यक्षः मैं एक व्यवस्था अवश्य देना चाहूंगा। वैसे तो नियमों में और व्यवस्थाओं में स्पष्ट प्रावधान है कि बिना किसी नियम के अंतर्गत दिए गए नोटिस के बिना जो कोई भी सदस्य कुछ प्रश्न रेज करेगा, वह इस सदन की प्रौपर्टी नहीं होनी चाहिए। यह व्यवस्था मैं स्पष्ट शब्दों में दे रहा हूं कि बिना नोटिस के कोई भी प्रश्न रेज करेगा, वह सदन की प्रौपर्टी नहीं मानी जाएगी।

15/03/2018/1210/MS/HK/3

<u>कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःका0(प्रशि0)ए(3)-1/2017 दिनांक 10.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 5.01.2018 को प्रकाशित; और
ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सहबद्ध सेवा/पद (वर्ग-III, अराजपत्रित) परीक्षा नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2017 दिनांक 29.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.10.2017 को प्रकाशित ।

15/03/2018/1210/MS/HK/4

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

अध्यक्षः अब श्री हर्ष वर्धन चौहान, सदस्य, लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री हर्ष वर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं :-

i. समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-

08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

ii. समिति का **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से **प्राक्कलन समिति**, (**वर्ष 2017-18**), समिति का **द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं-

i. समिति का चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा जनजातीय विकास विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति का पंचम कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का षष्टम कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप,सभापति, सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2017-18), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2017-18), समिति का प्रथम मूल प्रतिवेदन जोकि परिवहन विभाग से

15.03.2018/1215/जेके/एचके/2

सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का प्रथम मूल प्रतिवेदन जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

15.03.2018/1215/जेके/एचके/3

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

अध्यक्षःअब वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों/वार्षिक वित्तीय विवरण पर आगे चर्चा प्रारम्भ होगी। मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे पास 21 सदस्यों के नाम आज बोलने के लिए आए हैं। मैं माननीय सदन के नेता का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे पास 21 नाम चर्चा में भाग लेने के लिए आए हैं और यदि समय पर सदन का कार्य निष्पादित करना है और सभी को इसमें भाग लेना है तो 10 मिनट में सभी को अपनी बात कहनी होगी। इसलिए सभी 10 मिनट में अपनी बात कहें। जो बात आ चुकी है उसको रिपीट किए बिना अगर अपना विषय रखेंगें तो सभी को समय मिल सकेगा। कल प्रातः प्रश्नकाल के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी चार दिन की इस लम्बी चर्चा का उत्तर देंगें। तो मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि 10 मिनट के बाद हम घण्टी बजाएंगें और 12 मिनट के बाद अगले सदस्य को बोलने के लिए आग्रह कर देंगें। मैं श्री हंस राज जी, उपाध्यक्ष, विधान सभा को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

15.03.2018/1215/जेके/एचके/4

श्री हंस राज (उपाध्यक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मझे बजट परिचर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं कि मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आज इस सम्मानित पद पर आसीन हूं और यह जो बजट आया है इसने उस दृष्टि को सामने रखा है जो भारतीय जनता पार्टी किा दृष्टि पत्र रहा है। जो पं0 दीन दयाल उपाध्याय और पं0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी और शांता कुमार

जी और धूमल साहब जैसे लोगों ने जिस परिपाटी को शुरू किया था उसको माननीय जय राम ठाकुर जी ने आगे किया है। अन्त्योदय की भावना से इस बजट को पेश किया है क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा है कि जो चीजें पहले इस माननीय सदन में आयीं हैं उनका यहां पर उल्लेख न हो लेकिन कुछेक चीजें थी जिन्होंने इस बजट को ऐतिहासिक बना दिया है इसीलिए मैं स्वयं खड़ा हुआ हूं। क्योंकि मैं एक अति पिछड़े जिला से आता हूं बाकी सारी चीजें किसानों, बागवानों और विशेषकर युवाओं के लिए स्वरोज़गार की बात कही गई है और महिलाओं को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और यह प्रदेश किस तरह से सुरक्षित हो इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और पूरी टीम को पूर्णतः साधुवाद देता हूं।

15.03.2018/1220/SS-YK/1

उपाध्यक्ष महोदय क्रमागतः

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मान्यवर मुख्य मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि जो आपने एस0एम0सी0, पंचायती राज और अन्य लोग हैं उनके लिए वेतन वृद्धि की है, उसके लिए प्रावधान किये हैं उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र पर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विस्तार से अपनी सारी बातें कह पाऊं। लेकिन जो एस्पैशली डिस्ट्रिक्ट भारत सरकार ने जिला चम्बा को घोषित किया है, एक भारत सरकार है जिसने पिछड़े जिला को सच में पिछड़ा कहा तो है। इसके लिए श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सरकार को धन्याद करता हूं। वैसे तो यह ऐसा तगमा है जिसमें ज्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी धन्यवादी हैं कि किसी सरकार ने हमें आइडेंटीफाई तो किया। साथ ही मैं इसके लिए भी धन्यवादी हूं, जिस तरह से बजट में कहा है। सिरमौर और चम्बा की सब लोग चर्चा करते थे कि सिरमौर और चम्बा बड़े बैकवर्ड हैं लेकिन रोजगार कैसे पैदा हो, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता था। लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से फोकस रूप में कहा है कि सीमेंट उद्योग सिरमौर और चम्बा में लगेगा, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मान्यवर मुख्य मंत्री जी आप पिछड़े विधान सभा क्षेत्र से आते हैं आपने स्वयं ऐसी परिस्थितियों को झेला है इसलिए मैं आपके समक्ष दो-चार बिन्दु

रखना चाहूंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 47 पंचायतों की लगभग 90 हजार पापुलेशन को हमारा सिविल हॉस्पिटल, तीसा फीड करता है। मैं मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूं कि जो पी0एच0सी0 पिछली सरकार ने 5 सालों में पूर्ण रूप से खाली रखी और सिविल हॉस्पिटल तीसा जिसकी ओ0पी0डी0 400-500 के तकरीबन पर डे है उसमें सिर्फ दो ही डॉक्टर रखे। वहां न एक्सरे, न सिटी-स्कैन, न अल्ट्रा साऊंड था। उसमें आपने एक डॉक्टर कम-से-कम फौरी रिलीफ के लिए तीसा और अन्य पी0एच0सीज़0 में दिए हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी व धन्यवादी हूं। लेकिन जब आपका चम्बा दौरा बने तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो पहली अनाऊंसमैंट आपकी तरफ से हो, वह यह हो कि तीसा जो अति पिछड़ा ब्लॉक में आता है, हिन्दुस्तान के जो अति 35 पिछड़े ब्लॉकस आते हैं उसमें हमारा तीसा आता है इसीलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय आपसे निवेदन रहेगा और यह प्रावधान रहे कि उस तीसा के सिविल हॉस्पिटल को 100 बेडिड हॉस्पिटल बनाया जाए

15.03.2018/1220/SS-YK/2

ताकि वहां पर जो गाइनी की प्रॉब्लम आती है, चाइल्ड स्पैशलिस्ट की प्रॉब्लम आती है, ऑर्थो की प्रॉब्लम आती है उसको सही तरीके से सोल्व किया जाए। 90 हजार की पापुलेशन जो 100 किलोमीटर दूर चम्बा में छोटे-छोटे इलाज के लिए आते हैं उस समस्या को दूर करेंगे। इसका हमें पूर्ण विश्वास है। पिछली सरकार ने हमें पी0डब्ल्यू0डी0 का डिवीजन तो दिया था उसके लिए मैं पिछली सरकार का बहुत-बहुत धन्यवादी हूं लेकिन उसमें विभिन्न पदों को सृजित नहीं किया गया था। लेकिन जब से आपने सत्ता सम्भाली है आपने पदों को सृजित करवाया है और कुछ लोगों को भेजा है मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। क्योंकि 182 किलोमीटर के लगभग हमारी मेन स्टेट हाईवे आती है। उसके साथ-साथ जब केन्द्र सरकार ने हमें नेशनल हाईवे दिया है जो द्रमण वाया जोत से होते हुए चम्बा, हमारे तीसा से वाया सत्याश, ध्याश से होते हुए बैरागड़ और पांगी की तरफ जायेगा उसके लिए यह डिवीजन बहुत महत्वपूर्ण डिवीजन हो गया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर आग्रह रहेगा कि वह डिवीजन एक फुल-फलैज डिवीजन बने। बिजली बोर्ड का डिवीजन होना भी वहां बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले पांच सालों में 36 मैगावाट की एक बिजली की लाइन पांगी के लिए जा रही थी, जिसका बहुत बड़ा महत्व था। भाई जिया लाल जी बैठे हुए हैं। उसका इतना महत्व था कि हाइड्रो पावर का जो दोहन

होना है, जो हमारी 36 मैगावाट की एक लाइन निकलनी थी उससे वहां पर फीडर्ज़ तैयार होने थे, वहां से बिजली को तैयार होना था लेकिन उस लाइन को न चला करके पिछले पांच सालों में ठंडे बस्ते में पड़ी रही। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि एक डिवीजन जो सलूणी और हमारे चम्बा के लगभग चार या पांच सब-डिवीजन को फीड करेगा और मैं तो यह कहूं कि लगभग दो कांस्टीचुऐंसी को फीड करेगा, आप एक डिवीजन इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का दे दें तो बड़ी महान् कृपा उस पिछड़े इलाके पर होगी ।

15.03.2018/1225/केएस/वाईके/1

उपाध्यक्ष जारी....

जो आजकल सबसे क्रिटिकल चीज़ बनी हुई है, वह है शिक्षा, इसमें क्या हुआ है कि पिछली सरकार ने खैर इतने स्कूल तो नहीं खोले क्योंकि हमारे पूर्व के विधायक इतने तेज नहीं थे कि अंधाधुंध घोषणाएं करवा पाते और इसके लिए हम पूर्व मुख्य मंत्री के धन्यवादी भी हैं कि वहां पर घोषणाएं नहीं हुई थी। इसलिए हम वहां पर ज्यादा नहीं लटके हैं। उसमें मैं थोड़ा बरी हुआ हूं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सिर्फ यह आग्रह करना चाहूंगा कि पिछड़ा और हिल ट्रैक टफ माऊंटेंड एरिया हैं और उस इलाके में टीचर सेवाएं देने के लिए बड़े कम जाते हैं इसीलिए जो एस.एम.सी. या पी.टी.ए. या कोई और पॉलिसी जो हमारी पीछे चली थी, एस.एम.सी. भी हमारी सरकार के समय में 2007 में शुरू हुई थी और बाद में दूसरी सरकार ने भी परस्यू की है। इस तरह की योजना चले क्योंकि लगभग 70 प्रतिशत स्कूल चुराह विधान सभा क्षेत्र के खाली चले हुए हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि इस पॉलिसी को हम लोग अडॉप्ट करें जिससे स्थानीय युवाओं को वहां पर रोज़गार मिले।

अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर एक बटालियन की स्थापना होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा क्षेत्र जे.एण्ड के. के साथ लगता है। मुख्य मंत्री जी , एस.पी.ओज़ का मुद्दा बहुत समय से आपने स्वयं भी चलाया है और एस.पी.ओज़. 18-20 सालों से उस इलाके में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे 18-20 साल

पहले प्लस टू और ग्रेजुएट लोग थे । दो-चार या पांच हजार, इस तरह की उनकी फीडिंग रही है। बाकियों को तो अलग-अलग डिपार्टमैंट्स में मर्ज कर दिया गया है लेकिन मुख्य मंत्री जी से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इस बार उन चार-पांच सौ परिवारों को, जो एस.पी.ओज़ हैं, जिसमें हमारे लाहौल और पांगी के भी कुछेक इलाके में आते हैं, उनको भी सरकारी व्यवस्था में लाया जाएगा।

15.03.2018/1225/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष महोदय, हमारा चुराह विधान सभा क्षेत्र अति सुन्दर और रमणीय स्थान है। इसीलिए जो टूरिज्म में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रावधान किया है इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं लेकिन वहां से साचपास और माणीमसरून जैसे इलाकों को, क्याणी के इलाके को और तीसा के प्रमुख स्थलों को भी टूरिज्म केन्द्र के रूप में एक स्थापना मिले ओर वह इलाका टूरिस्ट प्वाइंट ऑफ व्यू से डलहौजी और खजियार की तरह एक मानचित्र में आए ताकि वहां के बच्चों को स्वरोज़गार की सम्भावनाएं बनें।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने स्वरोज़गार के लिए युवाओं को छोटी दुकानें और छोटे-छोटे उद्यम शुरू करके अपना जीवन यापन करें, ऐसी व्यवस्था की है। मैं उस दिन बड़ा परेशान था जब माननीय मुकेश जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी युवाओं को दुकानें और छोटे-छोटे उद्यम चला कर इस बजट के माध्यम से टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुकेश जी, जो मुख्य मंत्री जी युवाओं के लिए चाहते हैं कि वे अपना स्वरोज़गार उत्पन्न करके अपना जीविकोपार्जन कर सके, ऐसी व्यवस्था नहीं करवाना चाहते या क्या ये युवा विरोधी हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने को तो बड़ी सारी चीजें थी लेकिन हम और आप स्वयं व्यवस्था में है इसीलिए आसन का आदर करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा और मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारा चुराह विधान सभा क्षेत्र बहुत बैकवर्ड है । जब आप दौरा बनाएंगें तो बहुत ही हर्षोल्लास से, जिस तरह पूरा हिमाचल आपका

स्वागत कर रहा है, हमारा इलाका भी करेगा और हम चाहते हैं कि आप अगले महीने तक अपना दौरा बनाएं और दो-तीन सौगातें वहां के लिए ले कर आएंगें, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

15.03.2018/1225/केएस/वाईके/3

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट परिचर्चा में बोलने का समय दिया और यह अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बजट जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, मैं इनको साधुवाद देता हूं, मुबारकवाद देता हूं और इनका विज़न जो गरीब लोगों और गरीब सोसायटीज़ के लिए दिखता है, वह हमें नज़र आया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन पांच सालों में हिमाचल प्रदेश बहुत आगे जाएगा और हम सभी मिलकर एक बहुत अच्छा हिमाचल बनाएंगें। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः धन्यवाद हंस राज जी, आपने समय के अंदर अपनी बात कही, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब आदरणीय श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी चर्चा में भाग लेंगें।

15.3.2018/1230/av/ag/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठें। आपने जो शेर बोले उसकी ऊंचाइयों को देखकर हमें तो खुशी हो रही है। हमें उम्मीद थी कि जो छाले आपके पांव में पड़े हैं उसके दर्द को आपने सहा होगा। मगर आम आदमी के दर्द को भी अगर आप इस बजट में प्रस्तुत करते तो अच्छा होता। यहां पर एक बात बड़ी अच्छी आई है कि जब कोई पहली कुर्सी से उस कुर्सी पर पहुंचता है तो शायरी आ जाती है। जो भी मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठता है वह शायरी करने लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह रंगत जल्दी ही आपको भी आने वाली है। उस कुर्सी पर भी जो बैठता है वह भी शेरो-शायरी करने लग

जाता है और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद आप भी शेरो-शायरी करने लग जायेंगे, यह कुर्सी का असर है।

अध्यक्ष : आप अपेक्षा करते हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : यहां जो नया विधायक चुनकर आता है तो सोचता है कि विधायक बने हैं, अब जीत हमारे साथ चलेगी। हम भी विधायक बनें तो सोचा कि अब जनता की इतनी सेवा करनी है, इतनी ज्यादा योजनाएं लानी है, लेकिन जनता की अदालत में जब हम हिचकोले खाते हैं तो पता लगता है कि जनता सब जानती है। वहां पर बैठे हमारे विधायक महोदय और मंत्री महोदय; सारे इस मीठी गोली को चूस रहे हैं तथा बड़े स्वाद से चूस रहे हैं। इनको इस गोली का स्वाद भी आ रहा है और ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी सरकार 20 साल तक आती रहेगी, अब हम 20 साल तक जाने वाले नहीं है। यह कुर्सी ही ऐसी है परंतु हिमाचल की जनता जागरुक जनता है। वह जानती है कि समय पर हमें क्या जवाब देना है। आपकी पार्टी में जिसको मुख्य मंत्री घोषित किया जाता है वह चुनाव हार जाता है और भाग्यवान जीत जाता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों चुनाव हुए और कल ही उसके रिजल्ट आए हैं। आप भावनाओं की कद्र करते हैं मगर इस बजट में भी आप लोगों की भावनाओं की कद्र करते तो अच्छा होता। यह तो रूटीन का बजट है और जिस मुद्दे को लेकर मुख्य मंत्री जी ने

15.3.2018/1230/av/ag/2

पहले दिन बयान दिया था कि हम जीरो टोलरैंस अगेंस्ट करप्शन करेंगे उसके लिए आपके पास कोई अच्छी नीति नहीं है। मुख्य मंत्री के चारों ओर तो ग्रह-दशाओं का चक्र चल पड़ा है। अब चक्र ऐसा कि आप मुख्य मंत्री बनें, कटवाल साहब ब्यूरोक्रेसी से चुनकर आए, बड़े धक्के खाए और एम0एल0ए0 बनें तथा पहले ही दिन एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई। आपके सांसद वीरेन्द्र कश्यप आते हैं और कोर्ट में चार्जशीट हो जाती है। यहां पर माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि (***) (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : मैं आपको (श्री जीत राम कटवाल द्वारा कुछ बोलने के लिए खड़ा होने पर कहा।) बाद में समय दूंगा।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : मैंने तो आपके (श्री जीत राम कटवाल जी को कहा।) पक्ष की बात कही है, मैंने आपको बुरा नहीं बोला है। जगत सिंह जी ने कहा था कि (***) अब मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे नीतिन गडकरी जी आए और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि 31 मार्च तक जितने भी नेशनल हाई-वेज हैं उनकी डी0पी0आर0 बन जानी चाहिए। अच्छा प्रयास है (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : मैंने डी0पी0आर0 नहीं कहा, मैंने कनसल्टैंसी के टैंडर के बारे में कहा था।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

15.3.2018/1235/TCV/AG-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः आप जिन 69 नेशनल हाईवेज़ का नारा लेकर विधान सभा चुनाव में गये थे, क्या वे नेशनल हाईवेज़ डिक्लेयर हो चुकें हैं? अगर वे डिक्लेयर हो चुकें हैं, तो उनके नेशनल हाईवे नम्बर क्या हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी आप जो बात कर रहे हैं, वह आप कंसल्टेंसी फॉर डी0पी0आर0 फॉर नेशनल हाईवेज़ की बात कर रहे हैं। अभी तक नेशनल हाईवे कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। कौन से रोड़ में कौन सी फिजीबिलिटी होगी, क्या ट्रैफिक होगा? उसके बाद नेशनल हाईवे डिक्लेयर होगा। अभी सिर्फ नेशनल हाईवे अथोरिटी ने कंसल्टेंसी के लिए हमें पैसे दिए हैं। आपने रोना रो दिया कि 69 नेशनल हाईवे अप्रूव हो गये। हमीरपुर में 14-17 हाईवे हो गये। लेकिन अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुए हैं अगर नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुए हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी जब अपना रिप्लाई दें, उस समय नेशनल हाईवे के नम्बर के साथ रिप्लाई दें कि ये 69 नेशनल हाईवे हुए हैं। ---(व्यवधान)--- मैंने आपसे पूछा है, तभी जवाब चाहिए। आप ऐसे ही बता दीजिए। आपके यहां कौन सा नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ है?

माननीय मुख्य मंत्री जी मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आपके प्रवक्ता ने कहा कि हम धारा-118 को बदल कर रहेंगे। हमारी सरकार है, हम बदलेंगे। सरलीकरण कुछ नियमों में होता है। इंडस्ट्रीज लगनी है, पहले भी लगी है। पर्यटन की दृष्टि से कुछ करना है, वह पहले भी करते आये हैं। लेकिन कानून में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव किया गया, तो कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए, गरीब किसान के हितों के लिए आन्दोलन करेगी। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः प्लीज बात मत करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट ये भी दे देना, जो इन्होंने बोला है। अध्यक्ष जी, बजट में कहा गया है कि ड्रग्ज़ को हम दूर करेंगे। अच्छा प्रयास है। आज चिट्टा, हमने भी शब्द सुना। अभी पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा, रोहडू में चिट्टे का पहला केस रजिस्टर्ड हुआ, बिलासपुर में भी रजिस्टर्ड हुआ। लेकिन सवाल हरोली रोहडू का नहीं है, सवाल है, ड्रग्ज़ का। हिमाचल प्रदेश के जो छात्र-छात्रायें स्कूल, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन तक कैसे चिट्टा पहुंच रहा है? हम आपकी 2 महीने की सरकार के विकास कार्यों का हिसाब नहीं ले रहे हैं। हम जानते हैं, 2 महीने में आप कुछ नही कर सकते हैं। लेकिन समय आएगा, हम 5 साल के लिए

15.3.2018/1235/TCV/AG-2

चुनकर आये हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आज चिट्टा किस तरह रोहडू में कॉलेज के छात्रों के बीच में पहुंचाया जा रहा है? उसके लिए कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है। हम सब उन परिवारों के बच्चे हैं। किसी को चिट्टे की आदत लग जाती है, वह अपना जीवन छोड़ देता है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। पहले चरस हुआ करती थी, चरस पीकर भी लोग हिल जाया करते थे, लेकिन चिट्टे से तो पूरी तरह हिल गये हैं। ये चीज़ बड़ी गम्भीर हैं, ये चाहे कहीं से भी शुरू हुई है। मेरा कहने का मतलब है कि कानून व्यवस्था में कही-न-कहीं कमियां रही है और कानून व्यवस्था के नाम पर आप सरकार बदल कर आये हैं। 'गुड़िया प्रकरण' हुआ, हमने 4 दिन के भीतर सी0बी0आई0 को केस सौंप दिया।

15-03-2018/1240/NS/DC/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु -----जारी।

जो उनको पूछते रहे और ढूंढते रहे, वह एस0आई0टी0 अन्दर हो गई । वे थर्ड डिग्री अपनाते रहे कि आप बताईये कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र में सी0बी0आई0 भी आपकी और हिमाचल प्रदेश में दो महीने से आपकी सरकार है। जिस बेटी को न्याय मिलना चाहिए था, उस पर राजनीति की गई। हमें भी इस बात का दुःख है कि उस बेटी के साथ ऐसा हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते रहे कि जो भी उस बेटी का हत्यारा या कातिल होगा, उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। एस0आई0टी0 का गठन किया गया। एस0आई0टी का गठन करते वक्त जब पूछताछ हुई तो जो उसका सहपाठी था, उसकी हत्या हो गई। हम मानते हैं कि जो पूछताछ करने वाले थे, वे सारे अन्दर हो गये। लेकिन अभी तक गुड़िया के हत्यारे का पता नहीं लगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के विधान सभा क्षेत्र सिराज़ में होशियार सिंह फोरेस्ट गार्ड का कांड हुआ, उसकी भी सी0बी0आई0 इन्कवायरी मांगी गई। हमारी सरकार ने उसकी सी0बी0आई0 इन्कवायरी दे दी। लेकिन आज तक उसका भी कोई पता नहीं लगा। आप 13 विधायक अनुसूचित जाति से चुनकर आये हैं। प्रधानमंत्री जी के "मन की बात" हो रही थी और चेष्टा स्कूल में दलित बच्चों को अलग से खाना दिया गया। यह ठीक है कि सरकार ने कुछ कार्रवाई की। लेकिन इस प्रकार की घटनायें क्यों हो रही हैं? यह सोचने की बात है। इन घटनाओं को खत्म करने के लिए हमें कोई नीति बनानी चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाईंड अप कीजिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः सर, यह तो बहुत जल्दी हो गया। पांच-पांच मिनट तो यह (सत्ता पक्ष) रोक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। आपने कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए कुछ योजनायें लाई हैं। हिमाचल प्रदेश में इरिगेशन की जितनी भी योजनायें बनी हैं, चाहे आप जितनी भी योजनायें लें, वे आज बंद हैं। नादौन में इरिगेशन स्कीम पर 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो रही है, पहले 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। 80 प्रतिशत योजनायें सफल नहीं हो पाती हैं। आप जितना मर्ज़ी पैसा लगा दीजिए। टैंडर होता है और पाईपों की सप्लाई होती है और जो ठेकेदार हैं वे पाईपों की सप्लाई करते हैं लेकिन जब खेत में पानी पहुंचाने की बारी आती है तो पानी पहुंचता नहीं है। इसका क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय, इसका कारण पाईप नहीं है। इसका कारण यह है कि कृषक को जब पानी चाहिए तो उसकी सुविधा के अनुसार उसको पानी नहीं मिलता है। उसको assured irrigation चाहिए। Assured का मतलब है कि अगर उसको 11.00 बजे दिन में पानी चाहिए तो 11.00 बजे उपलब्ध होगा। सिंचाई विभाग क्या करता है कि 09:30 बजे और 08:30 बजे पानी छोड़ेगें और पानी छोड़ने के बाद 2.00 बजे बंद होगा। जहां भी आपकी इरिगेशन की स्कीमें बनती हैं, वहां आप assured irrigation करें। पोपुलेशन वाईज़, विलेज़ वाईज़ , जहां पर 500 और 1000 की पोपुलेशन है, अगर आप एक टैंक बना देते हैं और किसान जब चाहे तब अपने खेत में within territory of one kilometer में पानी छोड़ सके तो ये योजनायें सफल होंगी। आप जितनी मर्ज़ी सबसिडी दे दीजिये।

अध्यक्षः माननीय सदस्य थोड़ा जल्दी करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, अब तो अच्छा बोल रहा हूं।

अध्यक्षः हां आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः आपने हमारे लिए समय रख दिया और पहले चर्चा हो रही थी, आप उसका भी ख्याल रखिए। assured irrigation पर आपने 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च दी और किसान अपने खेत में पानी नहीं पहुंचा पा रहा है। उसको उम्मीद होती है कि पानी 10 बजे आएगा, मैं उठूंगा। जब उसे यह सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर पर किसान उस पानी पर निर्भर करेगा। जब ये पानी किसान के खेत में पहुंचेगा तभी तो सब्जी, अनाज़ और फल उगेंगे। उसके खेत में जब सब्जी उगती है तो उसकी मार्किट वैल्यू नहीं रहती है। हम सबसिडी खाद, बीज, औजार और पावर टिल्लर खरीदने के लिए देते हैं। मैं समझता हूं , इस सबसिडी की कोई जरूरत ही नहीं है। किसान जो उत्पाद पैदा करता है, उसके सामान को खरीद लिया जाये,

15.03.2018/1245/RKS/YK-1

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु...जारी

अगर minimum support price उसको मिल जाए तो हमारे युवा साथी भी खेती करने लगेंगे और किसान भी खुशहाल होगा। भारत सरकार ने एक योजना आरम्भ की है उसमें 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुझे बड़ा दुःख होता है, यहां पर न तो माननीय सिंचाई मंत्री बैठे हैं और न ही माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर हैं। मैं उनके फायदे की बात ही यहां पर कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर नहीं है। (***) यह नॉन सीरियस सरकार है। यह सरकार गम्भीर नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। (...व्यवधान...) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वक्ता बोल रहे हों, तो माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी को यहां बैठना चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप अपनी बात कीजिए।

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने टमाटर के समर्थन मूल्य, प्याज के समर्थन मूल्य और आलू के समर्थन मूल्य पर 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। क्या हिमाचल सरकार भी, जो किसान टमाटर उगाता है, लाहौल स्पिति का किसान, अब तो कृषि मंत्री जी भी वहीं से हैं, आलू उगाएगा, प्याज उगाएग या कोई फल या सब्ज़ी उगाएगा तो उसका समर्थन मूल्य किसानों को देगी? इस सन्दर्भ में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। एक और बात जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना पेटैंट समझते हैं। पेटैंट इस चीज का समझते हैं कि गौ-सदन बनाए गए। गौ-सदन की शुरूआत पिछली सरकार द्वारा की गई थी। उसके लिए बजट का प्रावधान भी हमारी सरकार द्वारा ही किया गया था। (...व्यवधान...) आपने शराब की बोतल पर एक रुपया टैक्स लगा दिया। हमारी राय यह है कि गाय हम सबकी गौ माता है। उसमें आप सबका अधिकार है। आप 1 रुपया लगाकर 8 करोड़ रुपये कमाते हैं। हम चाहते हैं कि इसे प्रति बोतल 1% लगाया जाए। यदि आप 1 रुपया लगाते हैं तो

————————————————————————————————————

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

15.03.2018/1245/RKS/YK-2

हिमाचल प्रदेश को शराब से 1800 करोड़ रूपये रेवेन्यू आएगा और 1% लगाते हैं तो 40-50 करोड़ रुपये रेवेन्यू आएगा। आप तीन हजार पंचायतों में 8000 करोड़ रूपये से, 50 हजार करोड़ रूपये से, गौ सदन में चारा दे सकते हैं। गौ सदन की रखवाली कर सकते हैं। अगर शुरूआत करनी है तो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। काम टालने के तरीके से नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंड अप कीजिए।

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि कम-से-कम 1% या 5 रुपये शराब की बोतल पर टैक्स लगाइए ताकि पीने वाला खुश होकर बोले कि आज मैं पी रहा हूं तो पांच रुपये गौ-माता के लिए भी दे रहा हूं। (...व्यवधान...) मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने 10 जिलों में 10 रेजिडैंशियल स्कूल खोलने की बात की है। यह एक अच्छा काम है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक अच्छी सोच है । लेकिन जो आप रेजिडैंशियल स्कूल खोलने जा रहे हैं, उनके लिए जो नियम बनाने जा रहे हैं कि इतने बीघे में इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी, उसमें बच्चों के लिए स्पोट्स की सुविधा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। आप 50-70 बीघा के बीच में एक रैजिडैंशियल स्कूल खोलते हैं, तो उसमें बच्चों की स्ट्रैंथ कितनी होगी ,उसका कैडर कौन-सा होगा या इसमें भी एस.एम.सी और पी.टी.ए. की तरह भर्ती होगी। उसके लिए आप तैयारी कीजिएगा। श्री बिक्रम जी हमारे उद्योग मंत्री हैं। नए-नए मंत्री बने हैं, नई-नई झंडी लगी हैं। शोक भी होता है, विजिट भी कर रहे हैं। क्रशर भी बंद किए हैं।

15.03.2018/1250/बी0एस0/एच0के0-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु .....जारी

माननीय मंत्री जी आपने कहा कि माईनिंग के खिलाफ, माफिया के खिलाफ आपने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर आप सही मायने में खनन को बंद करना चाहता हैं तो आप एक समय में सारी माईनिंग की ऑनलाइन ऑक्शन करेंगे? स्लैकटिड लोंगो को क्यों आप ऑनलाइन टैंडर करवा रहे हो। मैं आपको नहीं कह रहा हूं। हम चाहते हैं कि पूरे हिमाचल में एक साथ ओपन बिडिंग हो। अगर आप माईनिंग में क्रप्शन को दूर करना चाहता हैं तो हर साल इसके ऑन लाईन टैंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शराब काफिए पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार के पास भी लोग आते थे हमारे समय में जो बेवरेज पॉलिसी थी उसको 15 करोड़ रुपये का फायदा हुआ और जो लोग आते थे जो लोग आपके पास गए , आपके नेताओं के पास गए और पहली ही कैविनेट में आपने उस शराब कोर्पोरेशन को बंद कर दिया। ऐसी नीति होनी चाहिए, शराब की पॉलिसी के लिए यह जो एक यूनिट के थ्रू , एल-वन के थ्रू आप बेचने की बात कर रहे हैं, एल-2 के थ्रू आप शराब बेचने की बात कर रहे हैं। इसमें आप एक ठोस एक्साईज पॉलसी बनाई। हमें पिछले साल बेवरेज पोलिसी के तहत 18 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था। इस वर्ष कम से कम 16 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। जब रेवेन्यू ही पिछले साल 10 प्रतिशत इंक्रीज किया गया था तो आने वाले समय में और रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, यह हमारी आशा है।

अंत में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कहना चाहता हूं कि यह जो 20 साल वाली गोली है, इस गोली का स्वाद थोड़े ही दिन रहता है। यह ठीक है कि यह दो ही व्यक्तियों के पास है, एक मोदी जी के पास एक अमित शाह जी के पास। उनके पास यह गोली है और उनके पास जो गोली है उसकी जानकारी हमारे पास है। उस गोली की जानकारी यह है कि मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा उस गोली की जानकारी

15.03.2018/1250/बी0एस0/एच0के0-2

आपके पास भी नहीं है। वह गोली है ई.वी.एम. वह गोली ई.वी.एम. है। अभी बाई इलैक्शन में वह इस्तेमाल नहीं होगी। हमारे लोकसभा चुनावों में वह इस्तेमाल हो सकती है। ई.वी.एम. के द्वारा भी इस्तेमाल हो सकती है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाईंअप करें, नहीं तो मैं दूसरे सदस्य को बुलाऊंगा।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अभी तो बेचारों के छालों के दर्द भी दूर नहीं हुए। आप जो माननीय मुख्य मंत्री जी को गोली दे रहे हैं। यह हिमाचल की जनता है यह सड़क से खुश होने वाली नहीं । हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जितना कांग्रेस पार्टी ने दिया किसी ने नहीं दिया, जनता स्कूलों से खुश होने वाली नहीं। आपकी लोकप्रियता में कमी आई है। दो केश बन चुके हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दों में आप पिछड़ रहे हैं। यह आने वाले समय में प्रदेश की जनता बताएगी और गोली का असर जल्द खत्म होगा। मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय आपका धन्यववाद।

अध्यक्षः मुझे एक विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना है, 2001 में बार-बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जिक्र हुआ है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऊपर विस्तृत चर्चा 12 घंटे इसी माननीय सदन में हुई है। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो अपने बात को यहां पर रख चुका है। उसके बारे में (***) थोड़ा सा उसमें मर्यादा का ध्यान रखें। चर्चा बहस ले ले हम उस बारे में अनुमति देंगे। सदन उस पर चर्चा कर सकता है। दूसरी बात अधिकारियों के प्रति में कहना चाहूंगा कि किसी अधिकारी का नाम (***) न ले तो अच्छा रहेगा। एक मिनट माननीय सदस्य का नाम ले करके बात हुई थी।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

15.03.2018/1250/बी0एस0/एच0के0-3

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमें इस माननीय सदन में अपनी बात नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा। अगर विधायक यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। It is our fundamental right. यह एक विधायक का फंडामेंटल अधिकार है, वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति को प्रकट करना चाहेंगे वह कर सकता है। इस तरह से यह सदन नहीं चलेगा। कांग्रेस की विचारधारा अगर खत्म हो जाएगी तो इस देश को नुकसान होगा। हम अगर यहां पहुंचे है तो आर.एस.एस. की विचार धारा से नहीं, कांग्रेस की विचार धारा से यहां पहुंचे हैं। मैं सिर्फ यही आपके कहना चाहता हूं।

15.3.2018/1255/DT/YK-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य ने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। इस सदन में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। आप दोबारा चर्चा मांगेगे तो हम आपको अलौ करेंगे। आप इस पर खूब चर्चा करना। माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री जीत राम कटवालः अध्यक्ष जी मेरे बारे में एफ. आई.आर. के बारे में माननीय सदस्य श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने कहा इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। यह मामला, जब मैं विभागाध्यक्ष था, आर.टी.आई. से जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति गंभीर अनियमिताओं के चलते हाईकोर्ट गया था। उसको नौकरी से निकलना पड़ा था उसकी पिटीशन हाईकोर्ट में डिसमिस हुई है। उस जमाने में उसे एक लाख कोस्ट भी पड़ी थी। उसके बाद में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस तरीके से एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हर सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से दूंगा। वह तथ्यों के विपरीत है। यह भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। आरटीआई में जो अधिकारी है उनके नीचे पांच अधिकारियों से होकर मेरे पास फाइल आती है। मैं हाउस को सूचित करना चाहता हूं कि मिसलीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेरा रिकॉर्ड है वह इसका प्रमाण है। इन्क्वायरी होने दीजिए। --- (व्यवधान)--- मुझे न अभी तक किसी पुलिस ने पूछा है और न ही कोर्ट ने पूछा है। जब मैं

सेवा में था तब यह मामला हाई कोर्ट में गया था। और उस वक्त उसको एक लाख फाइन और गलत एफैडैविट देने के लिए उसकी भर्त्सना भी हुई है। यह उसकी कॉपी है।

धन्यवाद ।

15.3.2018/1255/DT/YK-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु।

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष जी, मैंने तो आप ही का पक्ष रखा और आपने स्पष्टीकरण भी दे दिया। आपको फायदा हो गया। दूसरा, आरएसएस के संबध में जो मैंने चर्चा के दौरान बात कही है मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं। झूठ के मामले में भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई सानी नहीं है। आप 69 नैशनल हाईवे बोलते रहते हैं। अभी तक कोई नैशनल हाईवे डिक्लेयर नहीं हुआ।

अध्यक्षः आदरणीय कटवाल जी आप बैठिए। अब चर्चा में माननीय उद्योग मंत्री श्री बिक्रम सिंह जी भाग लेंगे।

15.3.2018/1255/DT/YK-3

उद्योग मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 मार्च, 2018 को आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने जो बजट अनुमान प्रस्तुत किया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है । इस बजट का जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास उसको लेकर यह बजट बना है लेकिन हमारे मित्र श्री मुकेश अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है। कहते हैं कि शराब भी वही और बोतल भी वही। ऐसी बातें कर रहें आदरणीय वीरभद्र सिंह जी बैठे हैं। जब आदरणीय श्री जय राम ठाकु र जी बोल रहे थे तो सबसे ज्यादा खुश श्री वीरभद्र सिंह जी थे। वे टेबल थपथपा रहे थे। चाहे वे इसलिए थपथपा रहे थे कि हम नये हैं। आपको ऐसा

लगता है कि अखबार के अंदर मेरा नाम आना चाहिए। बड़े अक्षरों के अंदर खबर आनी चाहिए। इसलिए यह बजट कुछ नहीं है। ये तो एक्टर, डायरैक्टर और प्रोड्यूसर यही हैं।

15.03.2018/1300/SLS-YK-1

माननीय उद्योग मंत्री...जारी

इस बात को मैं अपने बजट भाषण में सिद्ध करूंगा कि जो आप जो डायरैक्टर और प्रोड्यूसर की बात करते हैं, आप उनका कितना कहना मानते थे और वह आपका कितना कहना मानते थे। मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार और इस सरकार की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। यह नौजवानों की सरकार है और काम करना चाहती है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : भोजनावकाश का समय हो रहा है। कृप्या आप 10-12 मिनट में अपनी बात रखें।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार एक नई सोच के साथ, नए इरादों के साथ और एक कमिटमैंट के साथ आई है। यह सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। इस सरकार में जो बातें होंगी, जो कहा जाएगा, वह फ़ैसले केवल कमरे में बैठकर नहीं होंगे और कमरे में बैठकर पॉलिसी भी नहीं बनेंगी। यहां सभी को साथ लेकर चला जाएगा और सभी से पूछा जाएगा। मैं आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं, यह पहले मुख्य मंत्री हैं जो सभी-के-सभी विधायकों को बीच में बिठाकर पॉलिसी के बारे में पूछते हैं, बात करते हैं और उसके बाद पॉलिसी को कार्यान्वित करते हैं। यहां कोई हिडन एजैंडा नहीं है। यहां केवल एक ही एजैंडा है कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की जाए, किस प्रकार से हिमाचल को आगे बढ़ाया जाए। हिमाचल के नौजवान को रोज़गार चाहिए। उसको इंडस्ट्री में आना है, व्यापार करना है, उसमें यह सरकार किस प्रकार से सहायता कर सकती है, यह सरकार की सोच है।

सुक्खु जी यहां पर अपनी बात रख रह थे। आप तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपकी पिछली सरकार में एक मंत्री बोल रहा है कि बेरोज़गारी भत्ता मिलना चाहिए लेकिन

मुखिया बोल रहा है कि मंत्री तो बोल रहे हैं लेकिन यह इलैक्शन मैनिफैस्टो में नहीं है। मंत्री कहता है कि इलैक्शन मैनिफैस्टो में है। मुखिया जी कहते

15.03.2018/1300/SLS-YK-2

हैं कि इलैक्शन मैनिफैस्टो में होगा लेकिन मैंने तो मैनिफैस्टो बनाया नहीं। यह कितना अच्छा तालमेल था। लेकिन फिर भी उस समय के मुख्य मंत्री की आत्मा नहीं चाहती थी कि इस प्रकार के फ़ैसले लिए जाएं। लेकिन आप लोगों के दवाब से उस समय इनसे गलत फ़ैसले भी करवाए गए। मैं तो इनका सम्मान करता हूं और मेरे साथ इनका बड़ा पुराना रिश्ता है। एक मंत्री थे जो यहां पर जब जवाब देते थे; हमारे पास भी महेन्द्र सिंह जी हैं। वह जब जवाब देते हैं तो विस्तृत चर्चा करते हैं और सारी बातें बोलते हैं। अपने आदरणीय अध्यक्ष जी का तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आप जितनी मरज़ी सप्लीमैंटरी पूछते रहो, ये कभी रोकते ही नहीं हैं। लेकिन आपके ज़माने में क्या होता था? मंत्री आकर यही बोलती थी कि मैं तुम्हारी तसल्ली करवा दूंगी। लेकिन जवाब नहीं दिया जाता था। यहां पर बिल्कुल साफ-सुथरा काम चल रहा है। यहां पर हर मंत्री, हर व्यक्ति सारी चीजों को पढ़कर गंभीरता के साथ यहां पर रख रहा है। इसलिए आपको इस सरकार के बारे में जो भ्रांतियां हैं; आप जिसे मीठी गोली कह रहे हैं वह मीठी गोली नहीं है। जो व्यक्ति धरातल पर काम करेगा, प्रदेश के लिए काम करेगा, नौजवान के लिए काम करेगा, वह मीठी गोली की बात नहीं है।

आप 20 साल की बात कर रहे हैं। आप कल के नतीजों की भी बात कर रहे हैं। क्या आप नॉर्थ ईस्ट को भूल गए? आपका हाल क्या है? आप खत्म होने वाले हैं, केवल 1-2 राज्यों में हैं। इसलिए अच्छी सोच रखो और अच्छी कमिटमैंट के साथ चलो। ये जो आपके मन के अंदर भ्रांति है कि आप दूसरे दलों के साथ मिलकर कुछ कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वह क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने पिछली सरकार में लोगों को ठगा है। आपके इस प्रकार के पॉलिसी और प्रोग्राम बने हैं जिनके कारण.. ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, आप अपनी बात रखें।

Shri Virbhadra Singh: You have said that 'ठगा है'. This is not a parliamentary language, not a parliamentary word. He pays me respect, it hardly matters but he has no reason to say anything about anybody. दायरे में रह कर बात करो और तमीज़ से बात करो। आप दिल के साफ व्यक्ति हो लेकिन मुंह फट हो।

15.03.2018/1300/SLS-YK-3

श्री बिक्रम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, ये बुज़र्ग हैं और बोल सकते हैं। इनके पक्ष के लोग क्या-क्या बातें कर रहे हैं, क्या कुछ बोलते हैं, तब आपके पास कमैंट देने के लिए समय नहीं होता, तब आप सो जाते हैं। पूछें कि क्या कहा तो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। ऐसा न करें। हां, मैं मानता हूं कि अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। हो सकता है कि मेरी कोई बात आपकी बुरी लगी होगी।

15/03/2018/1305/RG/YK/1
उद्योग मंत्री-----जारी

मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन यह जो जमात आपके साथ(श्री वीरभद्र सिंह जी की ओर इशारा करते हुए) बैठी है, इनको भी थोड़ा-बहुत समझाओ। आपके साथ बैठा व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, तो बाकी लोग क्या मानेंगे?

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आते ही एक बहुत अच्छा काम किया। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने वृद्धावस्था पेन्शन को 80 वर्ष से शुरू किया था कि जो 80 वर्ष का होगा, उसकी पेन्शन लग जाएगी। चाहे उसका बेटा क्लर्क या एस.डी.एम. लगा हो। लेकिन माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आज के दौर में 80 वर्ष से ऊपर कौन जाता है? इसलिए आपने पूरा हिसाब-किताब लगाकर रखा था कि 80 से ऊपर कोई व्यक्ति जाएगा नहीं और पेन्शन मिलेगी नहीं।

इसलिए हमने सबसे पहले सत्ता में आते ही उस उम्र को 80 से 70 वर्ष किया ताकि इस धरती पर जीवित व्यक्ति जिसकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर हो गई है, उसको पेन्शन मिले।

अध्यक्ष महोदय, आज कानून-व्यवस्था के ऊपर बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। अभी मेरे भाई ने कानून-व्यवस्था के बारे में बोला। कानून-व्यवस्था की बात जब-जब हिमाचल प्रदेश में होगी, तो जो दास्ताएं पिछली सरकार ने इस बारे में लिखी हैं, उनको लोग याद करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार को बने हुए अभी मात्र लगभग दो माह का ही समय हुआ है। आपने गुड़िया और होशियार काण्ड की बात की है। लेकिन आप इस बात को झुठला नहीं सकते कि तथ्यों को मिटाने या उनको समाप्त करने के लिए आपके लोगों ने पूरा-का-पूरा जोर लगाया ताकि इस बारे में किसी को पता हीं लग पाए और यही कारण है कि पुलिस विभाग में बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग आज सलाखों के पीछे हैं। यही कारण है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार की मन्शा ठीक होती, तो इस प्रकार का वातावरण नहीं बनता। मैं मानता हूं कि माननीच पूर्व मुख्य मंत्री जी ने जैसे ही सी.बी.आई. जांच के लिए कहा, उन्होंने जांच के आदेश दिए। लेकिन जो गल्तियां सी.बी.आई. को बुलाने से पहले आपने कीं, उन गल्तियों के बारे में भी आप लोगों के बीच में चर्चा करें। यह होशियार काण्ड हो गया, गुड़िया काण्ड हो गया या कानून-व्यवस्था गड़बड़ हो गई। यही कारण है आपके उधर जाने का। इसका और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आपने क्या-क्या नहीं किया? आपने कोई लाईन नहीं छोड़ी और उधर आदरणीय श्री जय

15/03/2018/1305/RG/YK/2

राम ठाकुर जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने गुड़िया और होशियार हैल्प लाईन और 'शक्ति ऐप' की जो शुरूआत की है, मैं उसके लिए इनको बधाई भी देता हूं। इसके कारण से हिमाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार आएगा और जो इस प्रकार के काण्ड हो रहे हैं, उनमें कमी आएगी। कम-से-कम आपको इस बात के ऊपर तो बधाई देनी चाहिए थी कि आपकी विधायक क्षेत्र विकास निधि 1,25,00,000/-रुपये कर दी है और विवेक अनुदान राशि बढ़ाकर 7,00,000/-रुपये कर दी गई है। थोड़ा-बहुत तो रहम करो, लेकिन आप तो एक लाईन को पकड़ते हैं और उसको छोड़ते ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय, यहां भाई सुबह बहुत परेशान थे, भाई ने सुबह उठकर सबसे पहले यह कहा कि आपने तो स्कूल, कॉलेज, पॉलिटैकनिक आदि बंद कर दिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब एम्स की बात होती है, तो कोई भी मेरा कांग्रेसी भाई या मित्र श्री गुलाम नवीं आजाद का नाम लिए बिना नहीं रह सकता। उनका नाम लेते हैं क्योंकि घोषणा की थी कि एम्स होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया? आप लोग एक कागज़ के ऊपर कोड ऑफ कन्डक्ट लगने से तीन दिन पहले हजारों संस्थान खोलते चले गए। आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जिस संस्थान की बात कर रहे थे, तीन दिन पहले उसकी अधिसूचना जारी हुई है। जब पहले यहां बात आई थी, तो मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था। लेकिन क्या कागज के ऊपर संस्थान खुलते हैं। जिस पॉलिटैकनिक की बात आप कर रहे हैं, अगर उन लोगों के बारे में आपके मन में पीड़ा होतीं, तो आप पहले दो वर्षों में ऐसे संस्थान खोलते। लेकिन आप जानते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हमें शंका है कि ये उस संस्थान में अपने चुनाव क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं।

उद्योग मंत्री : इसलिए उन लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिन्होंने पूरे-के-पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया हो। आप बात करते हैं कि पॉलिटैकनिकल कॉलेज या कोई कॉलेज बंद कर दिया। आपके समय में क्या हुआ है? सबसे पहले मैं भुक्तभोगी हूं। पता नहीं मैंने आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री जी के पैरों को कितनी बार हाथ लगाया, कितनी बार हाथ जोड़े। लेकिन इनकी एक बड़ी खासियत है कि जो इनका मित्र है, वह मित्र है और जो इनका दुश्मन है, वह दुश्मन है। यह बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार

15/03/2018/1305/RG/YK/3

का गुण हम लोगों में भी आना चाहिए। अगर हमारा कोई दुश्मन है, वह हमारे पैरों को हाथ लगा देता है, तो हम नर्म हो जाते हैं और इनके कोई पैरों को हाथ लगा देता है, हाथ जोड़ता है, तो ये गर्म हो जाते हैं, नर्म नहीं होते और

15/03/2018/1310/MS/AG/1

उद्योग मंत्री जारी----

ये बातें कर रहे हैं कि संस्थान बन्द हो गए? मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने आते ही कॉलेज बन्द कर दिया। कॉलेज बन्द करने के बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया, उच्च न्यायालय ने राहत दी कि यहां संस्थान होना चाहिए। लेकिन जब में उच्च न्यायालय में जीता तो ये उच्चतम न्यायालय में चले गए कि कॉलेज बन्द होना चाहिए। आज ये लोगों की बातें कर रहे हैं कि हाय, हाय, हमें बड़ा दर्द हो रहा है कि संस्थान बन्द हो गया? आपने तो चुने हुए प्रतिनिधि के बार-बार कहने पर भी, यहां बात आती है उनको नीचा दिखाया जा रहा है। उनको चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा है। यहां बात आ रही है। उस समय आप सबकुछ भूल गए? उस समय आपको नज़र नहीं आया कि ये भी इसी इन्स्टीच्यूशन का पार्ट एण्ड पार्सल हैं। लेकिन जिस समय हम विपक्ष में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आप फिर उच्चतम न्यायालय में चले गए। मैंने साढ़े बारह लाख रुपया अपनी जेब से खर्च किया। आपने तो बड़े महंगे-महंगे वकील उस केस में मेरे साथ लड़ाई लड़ने के लिए लगाए जोकि लिस्ट में भी नहीं थे। आप गुणवत्ता की बात करते हो और इन्स्टीच्यूशन की बात करते हो?

श्री वीरभद्र सिंहः यह शुरू से अंत तक बिल्कुल झूठ है।

उद्योग मंत्रीः मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं फ्लोर ऑफ दि हाऊस यह बात बोल रहा हूं। -(व्यवधान)- इसलिए आपको हमारा ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन जो सच्चाई है उसको आपको मानना चाहिए। यह भी बड़ा अच्छा लगा जो आप गौसदन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। -(व्यवधान)-आपके समय से कुछ नहीं हुआ। आपके समय में गौसदन के ऊपर कुछ नहीं हुआ। अब व्यवहारिकता के साथ गौसदन के ऊपर काम होगा। हम लोगों ने एक प्रयास किया है। यहां पर कहा गया कि मंदिरों का 15 प्रतिशत पैसा आप गौसदन के लिए क्यों लेंगे? अरे, हम क्या कोई बुरा काम कर रहे हैं? आपने महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए, ऐशो-आराम के लिए कार्यकर्त्ताओं को ऐसे संस्थानों से एक ही शादी के लिए 15-15 बार

15/03/2018/1210/MS/HK/2

पैसे दिए। हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। कल प्रश्न लगा था। मेरे ये दोस्त हैं इसलिए मुझे चुप रहना पड़ता है। आपका कामगार बोर्ड का कितना पैसा कहां-कहां गया? कल ठाकुर राम लाल जी का प्रश्न लगा था। आप लोग उस प्रश्न को देखिए तो वहां से पता चलता है कि आपने कितना काम किया है और हर जिले का आपने कितना ध्यान रखा है। मेरे जिला कांगड़ा के लिए कहते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट चला गया। अच्छी बात है आपने सेवा की है इसीलिए आप लगातार यहां आ रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आप यहां पर बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या-क्या किया है। अभी यहां पर माइनिंग की बात आ रही थी, मैं उस पर भी बोलूंगा। ये देखिए आपने क्या किया? Himachal Pradesh Scheme for Revival of Sick MSME Units, 2017. यह स्कीम उद्योग के लिए आप लाए। -(व्यवधान)- आप एक मिनट सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, ये लोग सिक युनिट को रिवाइव करने के लिए एक पॉलिसी लाए और जब उन सिक युनिट्स को रिवाइव करने की बात आई तो उन सिक युनिट्स का क्या किया? उसमें ऐसा किया कि जो नेगेटिव इण्डस्ट्री है उसको भी ले लिया। जिन प्रोड्यूसर एण्ड डायरेक्टर की आप बात करते हैं, जिन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। आपको रोकना चाहिए आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। उस समय आपने क्या बोला? आपने बोला कि यह जो स्कीम बनेगी इसके अंतर्गत इण्डस्ट्रियल सब्सिडी, इलेक्ट्रिकसिटी ड्युटि, सेल टैक्स, जी0एस0टी0, वैट और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, स्टेट एक्साइज ड्युटि आदि से छूट दी जाए और जिस समय यह सारा-का-सारा ड्राफ्ट बनकर आया, उस ड्राफ्ट को यहां के ऑफिसर्ज ने कहा कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग नहीं माने। उनकी बातों को न मानने के बावजूद आपने यह पॉलिसी बना दी है और इस पॉलिसी को पिछली केबिनेट में हमारे सभी केबिनेट मंत्रियों ने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी किसने बनाई है? इस पॉलिसी के कारण 2900 करोड़ रुपये का राजस्व बोझ स्टेट को पड़ना था। यह पॉलिसी भारत सरकार की MSME स्कीम के भी विरूद्ध थी

15.03.2018/1315/जेके/एजी/1

उद्योग मंत्रीः-----जारी-------

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि यह योजना किसके अनुरोध पर बनाई गई।

श्री वीरभद्र सिंहः हमने ऐसी पॉलिसी बनाने की आज्ञा दी थी जिससे कि जो छोटे कारखाने बन्द हो रहे हैं उनकी कैसे मदद की जाए और जिस रूप में यह मामला केबिनैट के पास आया, हमने इसको अस्वीकार किया। It was never implemented. गवर्नमैंट में कई किस्म की परपोजल्ज़ आती है और उन पर विचार होता है और कई विचार के बाद स्वीकार होती हैं और कइयों को किसी कारण से छोड़ दिया जाता है। हमने देखा था कि यह बहुत बड़ी है and we are not in a position to give money. We have no such resources, therefore, this matter was dropped.

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है, मैं उस पॉलिसी की बात कर रहा हूं जो इन्होंने बनाई। मैं उस पॉलिसी की बात कर रहा हूं जिस पॉलिसी को इम्प्लिमैंट करने के लिए आपने पूरा जोर लगाया। मैं उस पॉलिसी की बात कर रहा हूं जिसको केबिनैट में मंजूरी मिली है। मैं उस पॉलिसी की बात कर रहा हूं जिस पॉलिसी के अन्दर आपने लिक्कर इंण्डस्ट्री को एक्साइज़ डियूटि, जी0एस0टी0, बोटलिंग फीस, इम्पोर्ट फीस आदि को भारी भरकम प्रोत्साहन देने की आपकी क्या व्यवस्था थी? क्या कारण था शराब की इंडस्ट्री के ऊपर आपने इतना कुछ कर दिया? (Interruption) It is not the proposal. It is the policy, Sir.

श्री वीरभद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें स्वीकार की जाती है और कुछ चीज़ें अस्वीकार की जाती है और यह मामला भी आया which was considered. It was considered and found unfeasible and unworkable. The matter was entirely dropped by the Cabinet.

15.03.2018/1315/जेके/एजी/2

उद्योग मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो आदरणीय वीरभद्र सिंह जी कह रहे हैं मैं किसी ऐसे ही कागज को उठा कर यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं। यह पॉलिसी बनी। इस पॉलिसी के ऊपर ऑब्जैक्शन्ज़ लगे । यहां के ऑफिसर्ज़ ने आब्जैक्शन्ज लगाए थे कि क्या जरूरत है इसकी और इसमें नेगेटिव इंडस्ट्री को लेने की क्या जरूरत है? (व्यवधान) आप हमें बोलने दो। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। मैं यहां पर सभी विभागों का पढ़ देता हूं। आपको यदि कुछ लग रहा है तो मैं सारे का सारा पढ़ देता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, वाइंड अप करें।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे वाइंड अप करूं? माननीय वीरभद्र सिंह जी और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी यहां से खड़े हो करके बात कर रहे हैं और ये मेरे से पूछ रहे हैं और ये कहते हैं कि इम्प्लिमैंट कैसे नहीं हुई? इम्प्लिमैंट तो तब होनी थी जब आपने यहां आना था। हमने इसको देखा कि आपने क्या पॉलिसी बनाई है। सबसे पहली केबिनैट के अन्दर हमने इसको केंसिल किया कि इस प्रकार की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण हिमाचल के हितों की रक्षा न हो।

Shri Virbhadra Singh: The policy was never made. It was discussed and dismissed. It was never implemented. जब कोई परपोज़ल आती है उस पर विचार होता है उसके बाद सरकार फैसला लेती है। This proposal came which after study was found not feasible and Government dropped it. It was never implemented.

उद्योग मंत्रीः माननीय वीरभद्र सिंह जी आप हमारे बुजुर्ग हैं। आप गलत बोल रहे हैं। आपका ब्यान मेरे पास जो डॉक्युमैंट है उसके विपरीत है। आपने इसको ड्रॉप नहीं किया। इसको ड्रॉप करने वाली सरकार ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी की है और जयराम जी ने इसको कैंसल किया। आपने इसकी परपोज़ल बनाई और इसके ऊपर दवाब बनाया। दवाब बनाने के बाद आप इसको केबिनैट में ले कर गए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप नेगेटिव इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। आपने नेगेटिव इंडस्ट्री को फायदा देने के लिए, लोहे एंड स्टील को मदद देने के लिए किया है।

उद्योग मंत्रीः मैं जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात पूरी करें।

उद्योग मंत्रीः हमने किसी भी इंडस्ट्री को कोई छूट/रियायत दी है तो वह व्यावहारिक छूट है। वह ऐसी छूट नहीं है जो इसमें आपने दी है। हमने किसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए छूट दी है। आपने क्या किया हुआ है? --(व्यवधान)--

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः हमने तो छूट दी नहीं। आपने बजट बुक में दिया है कि लोहा एंड स्टील को 25 परसैंट की रिबेट देंगे। लोहा एंड स्टील नेगेटिव इंडस्ट्री है आप उसको फायदा देने जा रहे हैं।

अध्यक्षः मंत्री जी, आप अपनी बात कहें।

उद्योग मंत्रीः अब मेरे को और आगे जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के कारण से आप ये पॉलिसी बना रहे थे, मैं उसको भी जानता हूं। आप ऐसी बातें मत करो। आप ऐसे विषयों को मत उठाओ। आपने कुछ किया है, अगर आपका यह डाक्युमैंट बना है तभी मैं बोल रहा हूं।

श्री वीरभद्र सिंहः अगर आपमें हिम्मत है तो आप यह बात बाहर कहिये।। will sue you for this.

उद्योग मंत्रीः आपने हमें डरा-डरा कर मार दिया है। आप हमें हमेशा डराते हैं। क्यों डराते हैं? मुझे अपनी बात बोलने दो। जब भी हम वहां बोलते हैं तब भी आप कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसा मत करो। मैं फैक्ट्स एंड फिगर पर बोल रहा हूं।

श्री वीरभद्र सिंहः आप सदन के अंदर झूठी बातें मत करो। It was never implemented.--(interruption)--. We had dropped it.

अध्यक्षः मंत्री जी, आप मैटर स्क्वीज़ करें। आप अगला विषय लें।

15.03.2018/1320/SS-DC/2

उद्योग मंत्रीः यहां पर सैक्शन-118 की बात आई। आप कहते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर इसको रोका गया या इसको कुछ किया गया तो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आंदोलन करेंगे। यहां पर सबसे पहले आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने यह कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उस समय सोये हुए थे जिस समय आपने क्या किया। धारा-118 को लेकर जो आप आज चिन्ता कर रहे हैं आपके कार्यकाल के दौरान हजारों लोगों की जमीन खरीदने की परमिशन दी गई। यही नहीं कानूनी तौर पर जितनी एलाऊड थी उससे ज्यादा दी गई। उसके बाद जिनकी वैस्ट हो गई, उसको वैस्ट नहीं किया बल्कि गैर-कानूनी ढंग से आप लोगों ने उसको रेगुलराईज किया है। इसके बाद आपने कानूनी दायरे से बाहर निकल कर तीन साल से आगे की एक्सटेंशन भी दी है। जबकि टैनेंसी ऐक्ट के मुताबिक ऐसे हिमाचल प्रदेश में जमीन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप उस समय कहां थे? आप उस समय भी अध्यक्ष थे। आपका प्रश्न लगा है उसमें नाम भी आयेंगे। आप धारा-118 के बारे में बोल रहे हैं इसके बारे में आपको हमारे से ज्यादा चिन्ता नहीं है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हिमाचल प्रदेश से प्रेम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करते हैं। आपने धारा-118 की धज्जियां उड़ा दीं। जिला सोलन के अंदर एक होटल की एग्जैम्पल है--(व्यवधान)--

अध्यक्षः मुकेश जी, मैं आपको समय देता हूं।

उद्योग मंत्रीः अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई। आप यहां पर बात कर रहे हैं। आप लोगों ने तो आबकारी नीति की छज्जियां उड़ा दीं। आपने ऐसे काम किये हैं। 2015-16 में आपने जो दुकानें बांटी, जवाब आता है कि जिस-जिस तरीके से पॉलिसी चली उसके कारण से यह हुआ। यह आपका राज है। आपकी बढ़ोत्तरी हुई 15.76 परसैंट। 2016-17 में क्या हुआ? आपने 1387.04 करोड़ का टारगेट रखा, आपको 1307 मिले। जो अनुमानित आय होनी थी उससे 5.71 परसैंट कम हुई। आपने 2017-18 में क्या किया? आपने एक तरफ कारपोरेशन बना दी कि इस कारपोरेशन के माध्यम से शराब लेकर जायेंगे। उसी कारपोरेशन के अलावा आपने कई लोगों को लाइसेंस दे दिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अमूमन मंत्री इंटरवीन करते हैं, यहां पर कोई मंत्री और महकमा कौन-सा और बोल किस बात पर रहे हैं। --(व्यवधान)-

15.03.2018/1320/SS-DC/3

उद्योग मंत्रीः आप क्यों प्रॉब्लम में हो, आपको क्या समस्या है। --(व्यवधान)--मैं तो बोलूंगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः ये बोल किसी और विभाग पर रहे हैं।

15.03.2018/1325/केएस/डीसी/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी----

(व्यवधान)मंत्री जी, आप अपने महकमें के बारे में बोलें। यह इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है। आबकारी नीति के बारे में एक्साइज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर बोल सकते हैं। ये पता नहीं कहां जा रहे हैं? ये केवल अपने महकमे के बारे में बोलें।

अध्यक्षः एक मिनट। एक तो मेरे पास बिक्रम सिंह जी का नाम वक्ताओं की सूची में विधायक के नाते और रूलिंग की तरफ से आया है और उस नाते इनको परमिशन दी है । दूसरा, मेरा माननीय बिक्रम सिंह जी से कहना है कि वे दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मुकेश जी, मैं आपको भी समय दूंगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम पीठ का सम्मान करते हैं। अध्यक्ष जी, आपका फैसला अन्तिम है लेकिन बिक्रम सिंह जी सिर्फ सदस्य नहीं है, ये इस हाउस के मंत्री भी हैं, यह सच्चाई है और इसलिए आपसे आग्रह है कि अध्यक्ष के नाते आप बतौर मंत्री इनको बोलने की इजाज़त दिया करें।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री यह बता रहा है कि पिछली सरकार ने क्या कारनामे किए और हमारी सरकार क्या कर रही है परन्तु यह मंत्री बोल नहीं सकता, यह मुझे पहले बताना था। मुकेश जी, आप तो सारी चीजों को बहुत ज्यादा जानते हैं। 2016 में पूर्व सरकार

ने एच.पी.बी.एल. खोल दी। इसका मकसद केवल यही था कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करना है और इसके साथ-साथ पड़ौसी राज्यों के जो शराब व्यापारी हैं, उनको भी इसमें किस तरीके से बचाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन थे वे ब्ल्यू लाइन डिस्ट्रिब्यूटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड? ये कौन लोग थे? अगर आपकी तरफ से अब कोई सदस्य बोलेगा तो उसको इसकी फीड बैक दे दो कि ब्ल्यू लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड कौन थे? हमने तो सारे के सारे सिस्टम को बदल दिया है और आपके ध्यान में रहे कि जो आपने इस बार किया है उसके कारण पहली बार 2017-18 में -2.7% की रेवन्यू की कमी आने वाली है। यह क्यों हुआ क्योंकि जो-जो चीजें आपने बनाई उनको अच्छे तरीके से नहीं रखा।

15.03.2018/1325/केएस/डीसी/12

उन चीजों के अंदर राजनीति हुई।

अध्यक्ष जी, अभी टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की बात चल रही थी। हम जब इस बारे में बात करते हैं तो ये लोग गुस्सा होते हैं कि आप यह बात क्यों करते हैं? हम इसलिए इनकी बात करते हैं क्योंकि इन लोगों के कारण इस प्रकार की पॉलिसीज़ बनी। इनके कारण यह सारा कुछ हुआ। लगभग 3500 लोगों को आपने री-इम्पलॉयमैंट दी हुई थी। आपके दफ्तरों के अंदर इस प्रकार के लोग बैठे थे जिनको हिमाचल के लोगों की कोई चिन्ता नहीं थी। उनको केवल अपने हित की चिन्ता थी और इसी कारण इस प्रकार की पॉलिसी समय-समय पर बनती रही। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष जी, इस हाउस में चर्चा कराई जाए कि 58 साल के बाद का हर आदमी टायर्ड और रिटायर्ड है, जो कि उद्योग मंत्री जी कह रहे हैं?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी, मुझे नहीं लगता था कि इनको मेरे बोलने पर इतनी ज्यादा तकलीफ़ होगी क्योंकि एक्साइज़ में इन्होंने क्या किया है, मैंने उसकी बात की। धारा-118 में

क्या किया, उसकी बात की। आप इंडस्ट्री के अंदर जैसी पॉलिसी ले कर आए हैं, मैंने उसकी बात की। और यहां पर माइनिंग के बारे में आप चिन्ता कर रहे थे। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले दो महीनों के अंदर जो आपका सजैशन है, आपने जो ऑन लाइन का विषय लिया है, हमने ट्रायल बेसिज़ पर पहली बार 15 दिन के लिए ऑन लाइन कर दिया है जितने भी आपके माइनिंग से जुड़े हुए मसले हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि लोग कहते हैं कि दफ्तर में लोग पैसे लेते हैं। हमारे पास शिकायतें आई हैं कि इस प्रकार का यहां पर ट्रैंड चला है। मैंने सारे का सारा सिस्टम ऑन लाइन किया है। आपके ध्यान में रहे, पिछले दो महीनों के अंदर लगभग 24-25 क्रशर्ज़ बन्द हुए हैं। आपके यह भी ध्यान में रहे कि करोड़ों रुपये के जुर्माने इलिगल माइनिंग करने वालों को लगाए हैं। यह सरकार साफ-सुथरी सरकार है। यह सरकार वह नहीं है कि कोई बिचौलिया बीच में आ जाएगा, एडजस्टमैंट हो जाएगी। यह वह सरकार नहीं है जिसके

15.03.2018/1325/केएस/डीसी/3

कारण भ्रष्टाचार पनपेगा। यह आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार है इसमें सब कुछ साफ-सुथरा होगा। आप स्वास्थ्य मंत्री जी को देखिए इनका कार्यक्रम कैसा है। आज आते ही कृष्ण कपूर जी ने चीनी का 40 लाख रुपया एक महीने का बचाया। (व्यवधान) आपने कुछ शुरू नहीं किया आप एक फास्ट मंत्री थे, आपके मन में था ये लेकिन आपको ये पता था कि शुरू कब करवाना है।

15.3.2018/1330/av/hk/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री : सिरमौर की माइनिंग ऑन-लाइन हो गई थी।

उद्योग मंत्री : आपने नहीं किया, यह मैंने किया है। उद्योग विभाग के अंदर अब साफ-सुथरे काम होंगे। हमारी सरकार बढ़िया-बढ़िया निर्णय ले रही है।

अध्यक्ष जी, मेरे कारण बातचीत लम्बी हो गई। मेरी बात से हमारे बुजुर्ग और भाई लोग परेशान हुए उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन यहां पर जो माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है यह दूरगामी बजट है। इस बजट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ होने वाला है। इस बजट से प्रदेश के नौजवानों को लाभ होने वाला है और यह बजट कोई छल-कपट करने वाला बजट नहीं है इसलिए मैं इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.3.2018/1330/av/hk/2

अध्यक्ष : सुखविन्द्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बड़े जोश में बोलते हैं। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने बार-बार कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से इण्डस्ट्री की पोलिसी बनती है और जब इम्पलीमैंट न की जाए तो उसके बाद नई पोलिसी लाई जाती है। आपने धारा 118 के बारे में कहा कि इतनी जगह गई, इतनी जगह गई। (---व्यवधान---) बोला आपने। हम आपसे नाम पूछते हैं कि यह जगह किसके पास गई है? कितनी जगह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को गई, कितनी किस को गई? (---व्यवधान---) अभी आप बैठ जाइए, आप बोलने के लिए बहुत जल्दी रखते हैं। यहां पर कहा गया कि धारा 118 के तहत इतनी हैक्टेयर जगह गई तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जगह किसके नाम से गई? इस प्रकार की बातें किसी प्रोजैक्ट रिपोर्ट के आधार पर कही जाती है। (---व्यवधान---) हमने आपको भी कहा, अपने भाषण में भी कहा कि कोई प्रोजैक्ट आता है तो उसको धारा 118 के तहत परमिशन दी जाती है। वह चाहे इण्डस्ट्री का आता है या पर्यटन का आता है। मगर ऐसे ही कह देना कि आपने पूरा हिमाचल बेच दिया, गलत है। हमने कहा है कि धारा 118 के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। यहां पर आप जब कुछ बोलें तो फैक्ट्स के आधार पर बोलें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : क्या आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं?

उद्योग मंत्री : माननीय सुक्खु जी, आप जो मेरे से चीजें पूछ रहे हैं, मेरे पास उन सबकी जानकारी है लेकिन मैं आपकी मन्शा जानता हूं। आप इनको बदनाम करने के लिए यह सब जानबूझकर पूछ रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको इसकी लिस्ट बाहर दे दूंगा।

अध्यक्ष : अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.30 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

15.3.2018/1430/TCV/YK-1

माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के उपरान्त अपराह्न 2.30 बजे पुनः आरम्भ हुई।

उपाध्यक्ष : अब श्री राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बजट में बोलने के लिए, शरीक होने के लिए मौका दिया। जहां तक मैंने इस बजट को पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि यह बजट दिशाहीन, मक्कड़जाल और आंकड़ों के जाल से भरा हुआ है। अभी मेरे से पूर्व साथियों ने कहा-बोतल भी पुरानी है, शराब भी पुरानी है और बनाने वाली भी पुराने हैं, सिर्फ लैबल लगा दिया गया है कि 2018-19 । मैं तारीफ़ करना चाहूंगा कि कुछ बिन्दुओं पर कुछ अच्छे निर्णय भी लिए गये हैं। परन्तु जहां तक मैंने इस बजट में पढ़ा है, मैंने देखा है, पिछली सरकार में जो स्कीमें थी, उन्हीं के नाम बदले गये हैं। कुछ वही स्कीमें चली हुई हैं। हर बजट में थोड़ा सा इंक्रीज़, जितना हर वर्ष किया जाता है, उतना इंक्रीज भी किया गया है। जहां तक एम0एल0ए0 लैड की बात है, प्लानिंग की मीटिंग में बहुत-सारे विधायकों ने कहा था कि इसकी राशि को बढ़ाया जाये। वह 15 लाख रुपये बढ़ाई है, जबकि एम0एल0ए0 चाहते थे कि इस राशि को 2 करोड़ नहीं तो डेढ़ करोड़ किया जाये। वहीं पर ऐच्छिक निधि भी 2 लाख रुपये बढ़ाई गई है। माननीय विधायक चाहते थे कि इसको 10 लाख रुपये किया जाये। समय के साथ-साथ पैसे की वैल्यूएशन भी कम हो रही है, इसलिए इंक्रीज़ होना अति आवश्यक है।

श्री राजेन्द्र राणा-----जारी।

जहां तक पैंशन का प्रश्न है, आपने आयु सीमा 80 से 70 वर्ष की है। यह आपका अच्छा निर्णय है। पंचायती राज़ में चुने हुए लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है और 10 आदर्श विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है। इसमें यह भी नई योजना है। लोकभवन बनाने की बात भी इस बज़ट बुक में कही गई है। जहां तक मोक्षधाम की बज़ट में चर्चा हुई है तो इसके लिए बज़ट में कोई प्रावधान नहीं हुआ है। इसके अलावा माननीय जय राम जी प्रदेश के पहली बार मुख्य मंत्री बने हैं और इन्होंने पहला बज़ट पेश किया है। हम समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश की होगी। मैं कहना चाहूंगा कि

"मंज़िल यूं ही नहीं मिलती राही को,

ज़नून सा दिल में जगाना पड़ता है।

पूछा चिड़िया को घोंसला कैसे बनता है

वह बोली तिनका-तिनका उठाना पड़ता है।"

इसलिए मैं अपने साथियों को कहना चाहूंगा कि नई-नई सरकार बनी है, तिनका-तिनका उठाना पड़ेगा, इक्ट्ठा करना पड़ेगा और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। प्रदेश की ज़नता को बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं। परन्तु मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सदन में कई नये विधायक चुनकर आये हैं। उन्होंने अभी सीखना है और वे क्या देख रहे थे कि दूसरी तरफ जो हमारे साथी बैठे हैं, बज़ट में शरीक हुए हैं और जो चर्चा की है, बज़ट पर कम चर्चा हुई है और पिछली सरकार को पानी पी-पी कर कोसने का काम ज्यादा किया है। अच्छा होता, अगर बज़ट पर चर्चा करते और सरकार को सुझाव देते। नई सरकार बनी है, इस बज़ट में क्या-क्या कमियां रह गई हैं और हमें क्या-क्या और करना है, ये सब बताते तो अच्छा होता।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दृष्टि पत्र की बात है, पहले चुनावों में इसको घोषणा-पत्र का नाम देते थे और इस बार आपने दृष्टि-पत्र का नाम दिया है। अभी तो सरकार बने हुए अढ़ाई महीने का ही समय हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि दृष्टि-पत्र की जो नज़र या दृष्टि है वह प्रदेश की ज़नता पर सही रहे और जो आपने चुनावों में वायदे

किये हैं, उन वायदों को आप पूरा करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं क्योंकि अभी तो अढ़ाई महीने का ही समय हुआ है, अभी तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि आपने वायदे पूरे नहीं किये। जैसा कि आपने अपने श्वेत-पत्र में कहा है, कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें 4-9-14 मिलेगा और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हां, आपने अंतरिम राहत 4 प्रतिशत देने की जो बात कही है, वह तो पिछली सरकार ने भी कर्मचारियों को दिया है।

अध्यक्ष महोदय, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए नौज़वानों को रोज़गार मिले। इस तरफ बज़ट में कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं प्रदेश सरकार यानि जय राम सरकार का नज़रिया भी केंद्र सरकार की तरह तो नहीं है। कहीं वे भी इस बात से इत्तफ़ाक तो नहीं रखते हैं कि जैसे केंद्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने रखा है। केंद्र की सरकार ने वर्ष 2014 के चुनावों में वायदा किया था कि हम लगभग 2 करोड़ नौज़वानों को रोज़गार देंगे। अब जब रोज़गार मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि संस्थानों के बाहर जा करके पकौड़े बनाओ, आपको रोज़गार मिल जाएगा। कहीं आप भी इस बात से इत्तफ़ाक तो नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आवारा पुशओं और बन्दरों के बारे में हमारे सभी विधायक चर्चा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जब भी विधान सभा सत्र चला है, इन पर चर्चा अवश्य हुई है। क्योंकि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं और चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि आप विधान सभा जा करके इन आवारा पशुओं और बन्दरों की समस्या को ले करके क्या करेंगे? इसके लिए जो यहां पर ठोस नीति बनाने की बात कह रहे थे, वह होनी चाहिए। "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" जो पिछली सरकार ने चलाई थी और आपने उसे लागू किया है।

15.03.2018/1440/RKS/YK-1

श्री राजेन्द्र राणा...जारी

आपने दिहाड़ीदार की मजदूरी 210 रुपये से 225 रुपये जरूर की है। परन्तु मुझे लगता है कि जो व्यक्ति मजदूरी करता है, आज वह समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। उसके लिए सरकार ने बड़ी कंजूसी की है। केवल मात्र 15 रुपये ही बढ़ाये हैं। यदि आप इसे

दिल खोलकर बढ़ाते तो बहुत अच्छा होता। वाटर कैरियर का मानदेय 1900 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये किया है। इसी तरह आंगनबाड़ी और दूसरे लोग हैं, जिनके आपने थोड़े-थोड़े मानदेय बढ़ाए हैं। आपने जलरक्षक का मानदेय 1700 रुपये से 2100 रुपये किया है। आज के इस जमाने में, महंगाई के इस दौर में यदि आप किसी आदमी को महीने की 2100 रुपये तनख्वाह देंगे तो उसके परिवार का गुजारा नहीं होने वाला है। सरकार को इस बारे में कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। आई.पी.एच. विभाग में जो लोग काम करते हैं, उनसे पूरा-पूरा दिन काम लिया जाता है। सरकार को उनके लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि वे लोग सही ढंग से अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके।

महिलाओं को स्वाबलम्बन बनाने के लिए भी इस बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। (घंटी.) (उपाध्यक्ष जी , अभी तो हम शुरू हुए हैं)। 'मुख्य मंत्री खेल विकास योजना' के लिए 6.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि यह राशि बहुत थोड़ी है। यह काई पर्याप्त फंड्स नहीं है। आपने 'हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना' की घोषणा की है। इसमें जिक्र किया गया है कि जो सेवारत या सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनकी आपातकालीन चिकित्सा राशि 50 हजार से बढ़ाकर अढ़ाई लाख रुपये कर दी है। पत्रकारों को हम लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मानते हैं। वे हमारे समाज की हर तरह की समस्या को उठाते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा या दूसरे राज्य जहां 60 साल से ऊपर या जो पत्रकार सेवानिवृत्ति होते हैं, उनके लिए पैंशन का प्रावधान है। आपको भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। व्यापारी वर्ग का इस बजट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। सरकार को यदि कोई रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो वह

15.03.2018/1440/RKS/YK-2

व्यापारी ही है। सरकार को चाहिए कि व्यापारियों के लिए भी कोई कोष गठित किया जाए। उनके लिए कोई समस्या आती है तो पंजीकृत व्यापारियों के लिए इसका गठन किया जाए।

पर्यटन के क्षेत्र में 'नई राहें, नई मंजिल' योजना में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। 50 करोड़ रुपये आज के दौर में बहुत कम राशि है। सरकार को चाहिए की वे टूरिज्म के लिए कोई ठोस नीति बनाएं। हमारे प्रदेश में रिसोर्सिज़ की कमी हैं और इसकी वजह से हमें हर बार केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। यहां लोन लेने की बात आती है। दुनिया में ऐसे छोटे-छोटे मुल्क हैं जो टूरिज्म के दम पर पूरी दुनिया में ताकतवर बने हैं। फाइनैंशियल बहुत साउंड हो गए हैं। हमारे देश में टूरिज्म के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं। इसके लिए हमें दूसरे देशों से भी सीखना चाहिए। हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य बहुत हैं। हमारे पास वन हैं। जहां वन हैं, जहां थोड़ी-बहुत जगह है, वहां पर सरकार द्वारा लोगों को पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए टैम्परेरी हट्स बनाने इजाजत दी जाती है। इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। टूरिस्ट आता है। इसमें भी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जो ज़मीन की लीज 5-6 साल के लिए दी जाती है, पंजाब में यह 30 साल के लिए दी जाती है। इसे कम-से-कम 21-22 साल तक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने नैशनल हाईवे का बहुत ज्यादा जिक्र किया है। नैशनल हाईवे 69 बनाने की बात कही गई है।

15.03.2018/1445/बी0एस0/एच0के0-1

श्री राजेन्द्र राणाः जब केन्द्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी साहब हजी यहां आए, तब उन्होंने कहा कि 65 हजार करोड़ रुपया इसके लिए प्रदेश को मिल गया। आपकी डी.पी.आर. बनी नहीं सिस्टम आपका तय नहीं हुआ और 65 हजार करोड़ रुपये की घोषणा हो गई। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि नेशन हाईवे बनाने की बात कर रहे है, बनने भी चाहिए, समय लगेगा। हम भी उम्मीद करेंगे की सरकार 69 हाईवे जो बने हैं इनको मुकम्मल करें और मैं तो अपने मित्रों को कहना चाहूंगा कि हमने भी एक सुपर नेशन हाईवे बनाया है उसका भी धन्यवाद कर देते। बहुत सारे लोगों का जो नेशन हाईवे साफ हुआ है उसका भी धन्यवाद कर देते । मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा।

यहां पर चर्चा आई की लोहा और स्टील को सरकार प्रोत्साहन दे रही है जबकि यह नेगेटिव इंडस्ट्रीज हैं। मुझे लगता है कि लोहा और स्टील के ऊपर जो बजट में प्रोत्साहन देने की चर्चा की गई है। इस पर भी सरकार को पुनर विचार करना चाहिए। इसके अलावा मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि सुजान पुर क्षेत्र, जहां से मैं चुन कर आया हूं, वह सैनिक बहूल क्षेत्र है और वहां लोगों की कई समस्याएं हैं। पिछले पांच वर्षों में सूनाजपुर में अथाह विकास हुआ है। इसमें कोई कमी नहीं है। परंतु वहां पर जो विकास चल रहा है। उसको रोकने की कोशिश कुछ लोग जरूर कर रहे हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाईंडअप करें, अभी 17 माननीय सदस्य और बोलने वाले है।

श्री राजेंद्र राणाः माननीय उपध्यक्ष जी अभी तो 13 मिनट हुए हैं कई सदस्यों को तो 25-25 मिनट बोलने के लिए मिले हैं।

उपाध्यक्षः मैंने अपनी बारी में भी ऐसा ही किया कृपया वाईंडअप करें। इसके बाद माननीय सदस्य श्री गर्ग जी बोलने के लिए तैयार रहेंगे।

15.03.2018/1445/बी0एस0/एच0के0-2

श्री राजेंद्र राणाः मुख्य मंत्री जी सराज में बहुत सारी घोषणाएं करके आए हैं। हम चाहेंगे कि मुख्य मंत्री जी के लिए सुजानपुर की जनता का बड़ा योगदा है। वहां भी नजर रखें वहां भी घोषणाएं करें। अभी हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे कि हम लोग 20 वर्षों के लिए सत्ता में आए हैं। यह जो लम्बा पीरियड लेकर आप चल रहे हैं। लोकतंत्र में तो जनता तय करती है कि कब क्या होना है। परंतु मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि 2019 में क्या होने वाला है? अभी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार में वहां के लोगों ने जो संकेत दिया है। उस सकेंत को भी आप लोगों को समझना चाहिए। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कुछ प्रदेशों में चुनाव हुए, कहते हैं हमने सरकारें बना लीं। अरे जहां दो-दो सीटें आई वहां भी आप लोगों ने सरकारें बना ली, परंतु 2019 के लिए तैयार रहिए। अतं में मैं उपाध्यक्ष

महोदय, आपका धन्यवाद करता हूं और यही कह कर समाप्त करता हूं कि "यह सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मशरूफ हम जरूर हैं मगर बेखर नहीं" अपने साथियों के लिए एक लाईन और बोलना चाहूंगा। "झूठ कहूं तो लफ्ज़ो का दम घूटता है, सच कहूं तो आप ख़फा हो जाते हैं।" उपाध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत कुछ था परंतु आप बार-बार घंटियां बजा रहे है इसलिए समाप्त करता हूं। मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः इससे पहले कि अन्य सदस्य इस चर्चा में भाग लें, मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा कि 17-18 लोग अभी बोलने वाले हैं। तो निवेदन आप सभी से है कि 10-12 मिटन में आप अपना वक्तव्य मुकम्मल करें, वे चाहे इस पक्ष के हैं चाहे उस पक्ष के हैं। उसके बाद अन्य वक्ता को बुलाना हमारी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि मैंने भी 12 मिनट में स्वयं समाप्त किया था। इसलिए आप लोगों से निवेदन है की समय का ध्यान रखें। अब माननीय राजिन्द्र गर्ग जी चर्चा में भाग लेंगे।

15.03.2018/1445/बी0एस0/एच0के0-3

श्री राजिन्द्र गर्गः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018-19 का जो बजट माननीय सदन में प्रस्तुत किया उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

15.03.2018/1450/DT/DC/1

श्री राजिन्द्र गर्ग जी द्वारा जारी ....

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018-19 का जो बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया, उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है वास्तव में यह एक दूरगामी, बहुआयामी और सर्व स्पर्शीय बजट माननीय

मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिस बजट में सभी वर्गों को स्थान मिला हो, सम्मान मिला हो ऐसा बजट माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार का बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं और बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बजट में एक छोटी सी ईकाई से लेकर बड़ी ईकाई तक, सभी बातो का जीक्र इस बजट में किया है। चाहे वह आंगनबाड़ी सहायक हो आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे वह आशा वर्कर हो, चाहे वह पांचयत प्रतिनिधियो के मानदेय की बात हो, चाहे वह इस माननीय सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों की विधायक निधि या ऐच्छिक निधि की बात हो, हर तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने इस बजट को समायोजित करने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में शिक्षा, जो हमारे प्रदेश का या देश की बेसिक चीज़ है, जिसके कारण हमारा समाज पुष्ट होता है, उस शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए और उसके लिए एक मॉडल बनाने के लिए एक या दो मॉडल स्कूल विधान क्षेत्रो में खोलने का जो निर्णय लिया है यह निर्णय स्वागत योग्य है। हर विधान सभा क्षेत्र में यदि एक या दो मॉडल स्कुल बनेंगे तो इसकी पेरीफरी में आने वाले जो अन्य स्कूल हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी और उचित शिक्षा की दिशा तय होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम समाज के बीच जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो बुजूर्ग लोग हमको कहते

15.03.2018/1450/DT/DC/2

हैं कि बेटा हमारी पैंशन लगा दो, लेकिन उम्र के कारण यह करना बड़ा मुश्किल होता था। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने समाज के इस दर्द को समझा है और उसके लिएजो 80 साल की आयु की जो सीमा रेखा थी उसे घटाकर 70 साल कर दिया है उसके लिए प्रदेश के हज़ारों लोगों को इसका सीधा-सीधा लाभ पहुंचेगा। हमारे लिए भी एक सुविधा हो गई जब हम समाज के बीच जाते हैं तो ऐसे सभी लोग चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर

हो, जो मजदूरी करता हो और जब 65-70 की आयु में जब पहुंचता है तो उसकी बाजूओं में इतना दम नहीं रहता कि वह अपना या अपने परिवार का भ्रण-पोषण कर सके। ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक सहारा दिया है। उसकी जेब में पैसा होगा तो वह अपने नाती-पोतों को अपनी जेब से निकाल कर 10-20 रूपये उसके हाथ में रख सके, ताकि उसको किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, उसे लाचार न होना पड़े, ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा बजट में की गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रदेश में और मेरे विधान सभा क्षेत्र घुमारवीं में भी बेसहारा पशुओं की वजह लोगों को उनके आतंक का शिकार होना पड़ रहा है, वहीं किसानों को कृषि छोड़नी पड़ मजबूर होना पड़ रहा है है।

हमने भी चुनाव के समय लोगों से वायदा किया था कि जब हम चुनाव जितेंगे तो बेसहारा पशुओं के रख-रखाव के व्यवस्था करेगे। मैं इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होनें बेसहारा पशुओं के लिए पूरे प्रदेश में रख-रखाव की व्यवस्था खड़ी करने का ऐलान किया है और उस पर कार्य करना भी आरम्भ कर दिया है। इस तरह माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा एक बहुत बड़ा कदम इस प्रदेश में उठाया गया है वह वास्तव में ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। प्रदेश के अन्दर जो बन्दरों की समस्या है, मेरे विधानसभा क्षेत्र घुमारवी में भी बन्दरों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या लगभग 2004-2005 से है। पहले यह समस्या मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं थी। लेकिन प्रदेश की

15.03.2018/1450/DT/DC/3

तत्कालीन सरकार ने ट्रांसलोकेशन का जो सिस्टम अपनाया उस ट्रांसलोकेशन के सिस्टम में हमारे डंगार और जोखड़ के जंगल में यहां से बन्दर छोड़े गये

श्री राजिन्द्र गर्ग...जारी

पहले हमारे क्षेत्र में यह समस्या नहीं थी। लेकिन प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने ट्रांस-लोकेशन का जो सिस्टम अपनाया, उसके कारण हमारे डंगार और चोखड़ा के जंगल में यहां से बंदर छोड़े गए और उसके कारण आज पूरे घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र में बंदरों का आतंक बना हुआ है। लोग परेशान हैं और किसान परेशान है। लोगों से जब हम पूछते हैं कि कैसे बैठे हैं तो वह कहते हैं कि क्या करें, बैठना ही है क्योंकि बंदरों ने कुछ छोड़ा नहीं है; किसानी कर नहीं सकते इसलिए गपशप मारने के लिए बैठे हैं। आज इन बंदरों के आतंक के कारण ऐसी हालत हुई है। मेरा कहना है कि बंदरों के लिए ट्रांस-लोकेशन के सिस्टम को बंद किया जाए और इनकी सही व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने इस बजट में बेसहारा पशुओं और बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किए हैं, जिसके लिए हम मुख्य मंत्री जी का इस सदन मंच से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। पीने के पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था और सड़कों को अच्छी दशा में लाने के लिए अनेक प्रकार की बातें बजट में की गई हैं और पैसे का प्रावधान करके उनको मूर्त रूप देने का भी प्रयास किया है। जैविक खेती के बारे में भी कहा गया है जो आज के युग के लिए एक बहुत ही सामायिक विषय है। आज हमारे किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने टूरिज्म की चर्चा की। सभी सदस्यों ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आवाज उठाई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। टूरिज्म के लिए जहां अभी तक केवल 54 क्षेत्र ही चिन्हित हैं। मैं अपनी

तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि शिमला से आगे बिलासपुर और बिलासपुर से आगे हमीरपुर की तरफ भी टूरिज्म को बढ़ाया जाए।

15.03.2018/1455/SLS-DC-2

मेरे घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र में भी टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हमारे त्यून-सरियून की धारें, हमारे जंगलों छंज्यार, चोखड़ा और छन्दोह की जो धारें हैं उनके ऊपर भी टूरिज्म को बढ़ावा देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे जिला बिलासपुर और घुमारवीं तहसील के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं और जो फोरलेन्ज बनने वाली हैं, उनके किनारे जो क्षेत्र पड़ता है, उसको भी टूरिज्म में लेने और घुमारवीं क्षेत्र में भी टूरिज्म को बढ़ावा देने की कृपा करें। इससे वहां विकास में भी लाभ मिलेगा।

साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री ने इस बजट में प्रयास किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बजट में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि युवा किसी के आगे हाथ फैलाने लायक न हो, लाचार न हो, वह अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके। जो चर्चा पहले भी यहां सदन में हुई है उसी की कड़ी में मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने युवाओं को, बेरोज़गार युवकों को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही थी। फिर साढ़े चार साल तक जब वह बेरोज़गारी भत्ता न मिला और जब युवाओं ने इसके लिए आवाज उठाई तो तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा कि हमने तो अपने घोषणा-पत्र में यह वायदा किया ही नहीं है। शिमला से माननीय मुख्य मंत्री जी बोलते हैं कि नहीं, हमने वायदा नहीं किया है लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्हीं के एक मंत्री नगरोटा-बगवां से बोलते हैं कि नहीं, रुकिए मुख्य मंत्री जी, हमने वायदा किया है। दोनों के बीच में बहस छिड़ती है। फिर जब दोनों आकर शिमला में मिलते हैं तो उसके बाद विषय समाप्त हो जाता है। साढ़े चार साल तक बेरोज़गार युवकों को किसी प्रकार का बेरोज़गारी भत्ता न देने के बावजूद भी एक घिनौना मज़ाक जो प्रदेश की जनता और युवाओं के साथ किया गया कि घोषणा-पत्र में कहने के बाद भी सरकार मुकर जाती है, ये घिनौना मज़ाक नहीं तो और क्या है? इस मज़ाक की सीमाएं तब और लांघ दी गईं जब अगला चुनाव आया और कहा गया कि 2018-19 से हम

बेरोज़गार युवकों को दोबारा से बेरोज़गारी भत्ता देंगे। इस प्रकार का बहलाने का प्रयास किया गया।

15/03/2018/1500/RG/HK/1

श्री राजिन्द्र गर्ग-----जारी

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में टी.सी.पी. ऐक्ट को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कन्द्रौड़ से लेकर तरघेल तक लगभग 30 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में टी.सी.पी. ऐक्ट लगाना कहां तक न्यायोचित है? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि घुमारवीं विधान सभा चुनाव क्षेत्र में कन्द्रौड़ से तरघेल तक जो टी.सी.पी. ऐक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया है, मेरे बहुत सारे हरिजन बन्धु, छोटे किसान जिनके पास छोटी-छोटी जमीनें हैं, वे टी.सी.पी. ऐक्ट के तहत किस प्रकार अपना मकान बना पाएंगे? मैं इस माननीय सदन में इस बात को रखने के साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को भी इस बात से अवगत करवाना चाहता हूं और मेरी मांग है कि जो टी.सी.पी. ऐक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया है, उसको माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार हटाने की कृपा करे ताकि यहां के लोगों को राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी तबकों के लिए के लिए इस बजट में जो प्रयास किए हैं इसके दृष्टिगत मैं इस बजट का तहेदिल से स्वागत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

15/03/2018/1500/RG/HK/2

उपाध्यक्ष : अब श्री विक्रमादित्य सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट इस माननीय सदन में पेश किया गया है, उस पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं विधान सभा में पहली बार चुनकर आया हूं और वर्तमान विधान सभा का एक युवा विधायक होने के नाते मैं समझता हूं कि चाहे विपक्ष में रहते हुए, या अगर हमारी सरकार होती, तो

भी बजट से बहुत सी नई उम्मीदें एक युवा विधायक को सरकार से होती हैं। मैंने भी एक युवा विधायक होने के नाते केवल अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं इस बजट से रखी थीं। वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 41,440 करोड़ रुपये का वर्तमान बजट इस बार सदन में पेश किया है जिसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मगर जैसा पूर्व में वक्ताओं ने यहां कहा कि जो हमारी पूर्व सरकार ने बजट दिया था, यह उससे कोई भिन्न नहीं है। निश्चित तौर पर जो बजट सरकार द्वारा पेश किया जाता है, इसमें जो सारे आंकड़े दिए जाते हैं, वे ज़ाहिर तौर पर अधिकारियों द्वारा दिलवाए जाते हैं और कहीं-न-कहीं कई स्कीमों में पैसा कम या ज्यादा करके बजट पेश करवाने की एक प्रथा होती है। इसलिए यह बजट भी उससे कहीं अलग नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम बजट के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ग्रोथ रेट की बात की जाती है क्योंकि जब तक हम सही रूप में प्रदेश के ग्रोथ रेट के बारे में बात न करें तब तक मैं समझता हूं कि चर्चा को आगे ले जाना संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2015-16 का ग्रोथ रेट 8.1% रहा,, वर्ष 2016-17 में यह 6.9% था और वर्ष 2017-18 में यह 6.3% रहा है। इस बात पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यह बहुत आयरौनिक है कि इस समय में देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ जो छेड़छाड़ की गई और जिस तरह से जी.एस.टी. लगाया गया या डीमॉनेटाईजेशन किया गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ' this was nothing but systemized loot and organized plunder.' हम तो कोई अर्थ-व्यवस्था के बारे में बहुत ज्ञान रखने वाले नहीं हैं। मैं तो केवल एक युवा ही हूं। मगर केन्द्र सरकार में एन.डी.ए. के कार्यकाल में जो पूर्व वित्त मंत्री रहे, उन्होंने भी एक बहुत आलोचनात्मक तरीके से 'इण्डियन ऐक्सप्रैस' में अपने विचार रखते हुए यह कहा कि

15/03/2018/1500/RG/HK/3

'Private investment, industrial production and agriculture is in total distress and it has collapsed the Indian economy due to the misadventures of the Modi Government'. मैं यह बात यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था स्वाभाविक रूप से केन्द्र की नीतियों पर निर्भर है और केन्द्र सरकार द्वारा अर्थ-

व्यवस्था के साथ जो छेड़छाड़ अपने राजनीति मुद्दों को आगे रखते हुए की गई है, यह देश के हित के लिए अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल की बात है, तो उसमें लगभग 10,000 नए प्राथमिक विद्यालय

15/03/2018/1505/MS/HK/1

श्री विक्रमादित्य सिंह जारी----------

हिमाचल प्रदेश के अंदर खोले गए हैं और तकरीबन 2171 मिडिल स्कूल प्रदेश के अंदर हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश में 65 नये डिग्री कॉलेजिज खोले और हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी को "ए" ग्रेड का दर्ज़ा दिलवाया। वर्तमान बजट में 28 नई स्कीमें दी गई हैं, इसका हम स्वागत करते हैं।

उपाध्यक्ष जी, अगर हम रोज़गार की बात करें तो आज रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। "मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना", under which 25 percent capital subsidy on 40 lakh investment has been given. साथ-ही साथ "मुख्य मंत्री युवा आजीविका योजना" में 25 प्रतिशत सब्सिडी ट्रेड एक्टिविटिज पर दी गई है तथा इसके लिए 75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष जी, लगभग 8 लाख बेरोज़गार युवा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 18 से 35 वर्ष की आयु के हैं। जब केन्द्र में मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख युवाओं के लिए जॉब मार्किट हर महीने क्रिएट करेंगे और 2.3 लाख युवाओं को 9 महीने के अंदर प्रदेश में रोज़गार देंगे। वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने यह बात कही कि हम इसको अब अबंडन करते हैं और plan to train 5 lakh people by 2020-22 ,उन्होंने पहले जिस स्कीम को शुरू किया था उसको उन्होंने अबंडन किया है। इस बात को मैं हिमाचल प्रदेश के परिपेक्ष में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बहुत से तकनीकी शिक्षण संस्थान या अन्य शिक्षण संस्थान हैं, अभी जैसे राजेन्द्र राणा जी कह रहे थे कि उनसे रोज़गार अलग-अलग किस्म का मिलता है। जो हमारा युवा स्कूलों के माध्यम

से या हायर एजुकेशनल इन्स्टीच्यूट से पढ़कर आ रहा है तो बीजेपी की जो पकौड़ानोमिक्स की फिलोसफी आज प्रदेश और देश के अंदर लाई जा रही है, उससे हमको चिन्ता होती है क्योंकि यह पकौड़े की इकॉनोमिक्स हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाली नहीं है। यह चीज भी हमें देखने की आवश्यकता है।

मैं बेरोज़गारी भत्ते की भी बात करूंगा। हालांकि कांग्रेस ने आखिरी साल यानी वर्ष 2017-18 में बेरोज़गारी भत्ते को घोषित किया था जिसके लिए 2150

15/03/2018/1505/MS/HK/2

करोड़ रुपये का बजट प्रावधान पूर्व सरकार द्वारा रखा गया था और 21000 युवाओं को इसके द्वारा फायदा पूर्व सरकार द्वारा दिया भी गया। हालांकि बजट में लिखा गया है कि यह पूरी तरह से इल कन्सीव्ड प्लान पूर्व सरकार का था और इसको बन्द किया गया है। मैं इस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि इस नीति को जो बदला गया है, यह बदला है या "बदला" है, यह मैं सरकार से पूछना चाहूंगा?

अनुबन्ध कर्मियों की भी बात की गई थी। मुझे याद है कि जो उस समय के मुख्य मंत्री पद के उम्मीदवार थे उन्होंने चुनाव के समय यह बात कही थी कि जो हमारे अनुबन्ध कर्मचारी हैं उनके टाइम पीरियड को तीन साल से कम करके दो साल किया जाएगा। हालांकि उनके वेतन को इस बार बढ़ाया गया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा लेकिन अनुबन्ध कर्मचारियों के पीरियड को कम नहीं किया गया है इसलिए सरकार को इसे गम्भीरता से देखने की आवश्यकता है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

जहां तक शिक्षा की बात है तो "मुख्य मंत्री आदर्श विद्या केन्द्र" जो खोलने की बात की है उसका मैं स्वागत करता हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र में जहां पर नवोदय विद्यालय नहीं है वहां पर इसको खोलने का एक प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। मगर जो बात पूर्व में कही गई this is nothing but old wine in new bottle. अध्यक्ष जी, आप हंस रहे

हैं और मुझे लगता है कि आप मेरी बात को मान रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से पूर्व में जो "आदर्श मॉडल स्कूल" चलाए जाते थे अगर सही रूप से इसको बढ़ाना ही था तो इसी नाम से इनमें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज को देकर इस स्कीम को चलाया जा सकता था मगर getting in a new scheme just to get political dividend is something that I understand has been done but with the political motives.

15.03.2018/1510/जेके/वाई0के0/1

श्री विक्रमादित्य सिंहः------जारी-------

जहां तक हमारे टूरिज्म सेक्टर की बात है, मैं इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के अन्दर टूरिज्म की बहुत सी सम्भावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्दर एयरपोट्र्स की बात की गई, उड़ान सेवाओं की बात की गई, भून्तर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमारे शिमला का एयरपोर्ट है। शिमला का एयरपोर्ट वैसे भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण में आता है। इसके लिए जो मैं इकॉनोमिक स्टैटेस्टिक्स रिपोर्ट पिछले साल की पढ़ रहा था, उसमें यह बात मैंशन की गई थी कि तीनों एयरपोट्र्स को हमने समय रहते एक्सपैंड करना है। आज प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो उड़ान स्कीम चलाई जा रही है इसमें छोटे एयरक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश के अन्दर आते हैं। अगर हम शिमला एयरपोर्ट की बात करें इसको भी पिछले समय में एक्सपैंड करने की बात की गई थी, इसके ऊपर प्रदेश सरकार ने कोई भी लेखा-जोखा इस बार नहीं रखा है। जो भून्तर एयरपोर्ट है इसमें जो आई0टी0आई0, रूड़की है उन्होंने उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट दी थी कि 81.34 करोड़ रूपए से जो Rs. 81.34 crores diversion of Beas नदी के माध्यम से इसको एक्सटैंड किया जाए और वहां पर बड़े बोइंग विमान उतर सकते हैं। ऐसे ही कांगड़ा एयरपोर्ट को भी एक्सपैंड करने की बात कही गई थी कि इसका जो अभी वर्तमान 72 x 30 / 1852x50 meters को जो अभी इसका करंट रनवे है इसमें additional 571 acres लेकर इसको एक्सटैंड करने की बात की गई थी। साथ ही साथ क्योंकि अभी जो आतंकवादी हमले हमारे पठानकोट में हुए थे उसके तहत आई0एफ0 के माध्यम से भी एक नई पट्टी वहां पर बनाने की बात रखी गई थी उसके बारे में भी ज्यादा कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया

गया है। इसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। मैं पूर्व कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज जो उड़ान-2 की बात की जा रही है कि इसमें 63 ऑप्रेशनल हेलिपैडज़ आज जो हिमाचल प्रदेश के अन्दर है और हमने तीन नए हेलिपैड एक बंदेड़ू संजौली के अन्दर जो 7 करोड़ रूपए की लागत से बनने जा रहा है, एक चुवाड़ी में है, एक कुंडू जिला मण्डी में है। इनको हमने किस तरह से आगे एक्सपैंड

15.03.2018/1510/जेके/वाई0के0/2

करना है? अगर सरकार को यह लग रहा है कि हम इसको सरकारी क्षेत्र में ही और अगर हम इसको पवन हंस के माध्यम से या किसी पब्लिक सेवा के माध्यम से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें हम कहीं न कही गलत है। आज हमको हिमाचल प्रदेश को अध्यक्ष महोदय एक all seasons for all reasons के माध्यम से देखने की आवश्यकता है। आज जो हिमाचल प्रदेश के अन्दर टूरिज्म आ रहा है, बेशक उसमें वृद्धि हुई है, बेशक मैं उसमें मानता हूं कि आज हमारे बहुत सा टूरिज्म जितनी और कल भी यह बात हो रही थी कि जितनी हिमाचल प्रदेश की पॉपूलेशन है उससे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में एन्वल टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश के अन्दर आता है। But we need to ask ourselves that do we need to emphasize on the quantity or do we need to emphasize on quality of tourist that is coming in the State of Himachal Pradesh . इसके बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि टूरिज्म डिपार्टमैंट द्वारा बहुत से कार्य इसमें करवाए जा रहे हैं। अभी यहां पर स्की रिजॉर्ट की बात की गई। बहुत से हमारे जो वर्ज़न क्षेत्र हैं, उनको रोप वे से जोड़ने की बात की गई, मगर there is no concrete way of how we have to go about it . मैं इसके बारे में यह चीज़ जरूर कहना चाहूंगा कि हालांकि जंजैहली की बात की गई। मुख्य मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर वह आना स्वाभाविक था। मगर उसके साथ-साथ अगर शिमला जिला की भी उसमें कहीं न कहीं उसमें बात की गई होती। हमारे शिमला के अन्दर डोडरा-क्वार का इलाका है, चांशल घाटी का इलाका है, सराहन का इलाका रामपुर के अन्दर है। इसके बारे में यदि उसमें बात की गई होती तो निश्चित तौर से हम उसका स्वागत करते। मगर आने वाले समय में इसको अगर रखा जाएगा तो हम निश्चित तौर से उसका स्वागत किया जाएगा। मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहता हूं आज रिसोर्स मॉबिलाइजेशन की बात कही जा रही है कि प्रदेश में पैसा

कम है। मुख्य मंत्री जी ने भी इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है तो निश्चित तौर से मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि हमें अपनी सोच को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी जैसे कि जो बजट यहां पर पेश किया गया हम तो अभी युवा है मैं ज्यादा सरकार के ऊपर, सरकार की मंशा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर यदि हमें सही रूप से बजट को बढ़ाना है

15.03.2018/1515/SS-YK/1

श्री विक्रमादित्य सिंह क्रमागतः

तो हमें कहीं-न-कहीं आउट ऑफ दी बॉक्स थिंकिंग करने की आवश्यकता है। मैं एक दिन अखबार में आर्टिकल पढ़ रहा था। अमेरिका के अंदर लाओसवेगस जगह है, वैसे ही दुबई है, वैसे ही मकाओ है। कहीं-न-कहीं यह बहुत एरोनिक है कि ये तीनों जगहें एक समय में डैजर्ट हुआ करती थीं। मगर आज जितनी आमदनी अमेरिका, दुबई और मकाओ को कसीनों के माध्यम से आ रही है मैं समझता हूं कि इसको कहीं-न-कहीं हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में implement for the resource mobilization and for the betterment of the economy of the State इस चीज़ को लाया जा सकता है। एक चीज़ और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि भांग की बात की जाती है। मुझसे पहले भी भांग के बारे में ध्वाला जी ने ज़िक्र किया था। इसके बारे में बहुत-सी रिसर्चस हो रही हैं। इसको दवाई के रूप में किस तरह से इस्तेमाल किया जाए यह भी एक बहुत बड़ा विषय आज है। इसमें डॉक्टर विश्वकर्मा जो सी0एस0आई0आर0 के डायरेक्टर हैं उन्होंने इसको एक टर्म दिया है Cannabidiol(CDB) which has already been approved by USA, Europe and Canada. अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं कृपया मुझे निश्चित तौर से थोड़ा समय और दें। आपको जानकर यह खुशी भी होगी कि यह एप्लैप्सी, एच0आई0वी0 कैंसर और कीमोथरेपी के लिए बहुत उपयोगी है। इस चीज़ को हमें कहीं-न-कहीं देखने की आवश्यकता है। इससे एक ओर प्रदेश की इकोनोमी बढ़ेगी। अभी गौ रक्षा की बात कही जा रही थी। गऊ के लिए एक रुपया सैस लगाने की बात कही जा रही थी तो शराब के साथ-साथ यह चीज़ जो हिमाचल में abandon में ग्रो हो रही है अगर इसको हम सही रूप में रूट करें, ऐसा नहीं है कि हमने इस पर बैन लगाया हुआ है तो इसकी खेती नहीं हो रही है अभी भी इसकी खेती हो रही है और काला पैसा प्रदेश के अंदर बन रहा है वह हिमाचल की

इकोनोमी को बढ़ावा देने में कोई योगदान नहीं दे रहा है। अगर हम इसको सही रूप से देखेंगे तो निश्चित तौर से इसको बढ़ाया जा सकता है।

एग्रीकल्चर की बात करें तो मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना मुख्य मंत्री जी ने लाई है मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। मगर इसको 80 से 85 परसैंट क्लस्टर फॉर्म में बढ़ाया गया है। अब मैं आपको इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो हमें जमीनी तौर पर लोगों की आवाज़ सुनने को मिली है कि क्लस्टर फॉर्म में हमारे किसान/बागवान इसका

15.03.2018/1515/SS-YK/2

पूरी तरीके से फायदा नहीं ले पाते हैं। जिस तरह से सोलर पम्पिंग की बात की गई है और इसकी पहली शुरूआत भी मेरी कांस्टीचुऐंसी के खलोग में की गई थी और 200 करोड़ रुपये का इसके लिए बजट रखा गया है। मगर अध्यक्ष महोदय, जो यह सोलर पम्पिंग के माध्यम से 200 से 250 मीटर तक पानी उठाया जाता है, मगर सही रूप से बहुत से ऐसे हमारे प्रदेश के क्षेत्र हैं जहां पर जो वॉटर लेवल है अगर हमको सही रूप से पानी चाहिए तो वह 500 से 1000 मीटर तक है, वह पानी दिया जाता है। इसको सोलर पम्पिंग के माध्यम से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस पर सरकार ने अभी सही रूप से कार्य नहीं किया है। निश्चित तौर से इसको देखने की आवश्यकता है। साथ-ही-साथ मिनीमम गवर्नमैंट और मैक्सिमम गवर्नैंस की केन्द्र सरकार ने बात कही है। प्रदेश सरकार ने भी बात कही है। मगर इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आधार की बात की जाए, अभी तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक लिमिटेशन लगा दी है कि हमें अपने बैंकों के खाते और मोबाईल फोन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मोदी सरकार तो हमारे बटुओं तक पहुंच गई थी। मोदी सरकार हर वह चीज़ जिस पर इलैक्ट्रोनिक रूप से कार्य होता है उस पर पूरी सर्वेलैंस केन्द्र सरकार की होती है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य मैं मानता हूं कि आप पहली बार बोल रहे हैं पर थोड़ा-सा समय का ध्यान रखें।

श्री विक्रमादित्य सिंहः अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई। लॉ एंड ऑर्डर में भी हालांकि सरकार ने गुड़िया और होशियार हैल्पलाइन प्रदेश के अंदर शुरू

की है। उसका मैं स्वागत करता हूं। मगर साथ-ही-साथ जो आरोप पूर्व सरकार के ऊपर लगाए गए हैं उसकी हम पूरी तरह से निन्दा करते हैं क्योंकि पिछली बार जो गुड़िया मामला है जिसके ऊपर बहुत-सी राजनीति प्रदेश के अंदर करवाई गई, इसको हमें राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है।

15.03.2018/1520/केएस/एजी/1

श्री विक्रमादित्य सिंह जारी---

मगर सरकार की मन्शा इसमें साफ नहीं होती तो तीन दिन के अंदर एस.आई.टी. के बाद जो सी.बी.आई. को जांच दी गई, यह नहीं करवाया गया होता और सी.बी.आई. द्वारा इसके असली केस में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। केवल जो दूसरा मामला है उस पर अभी चार्जशीट कोर्ट के अंदर रखी गई है। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अभी तो सरकार का समय शुरू ही हुआ है इसलिए मैं कहना चाहूंगा किः

उम्र भर गालिब यही भूल करता गया,
धूल चेहरे पर थी और आइना साफ करता गया।

अध्यक्ष महोदय, यह चीज़ हमको देखने की आवश्यकता है कि आज सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है। सरकार की जो कमियां इस वर्तमान बजट में रही है उनको आने वाले समय में इम्प्रूव किया जाए। मैं केवल निन्दा करने में विश्वास नहीं रखता हूं। जो अच्छे कार्य प्रदेश सरकार ने किए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करने से भी पीछे नहीं हटता हूं। यहां पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी बैठे हुए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने 7 करोड़ रुपये अभी हमें कॉलेज और स्कूल के लिए दिए हैं। साथ ही साथ जो कमियां सरकार की रहेंगी उनको बताने में भी हम पीछे नहीं हटेंगें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूगा, अभी मुख्य मंत्री महोदय इस माननीय सदन में नहीं है लेकिन मैं इनको एक चीज़ के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा क्योंकि

उन्होंने एक प्रयास किया है कि राजनीति से ऊपर उठ कर जिस तरह से प्रदेश के अंदर टोपियों का कल्चर चल रहा था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं लाल टोपी और कांग्रेस को हरी टोपी के साथ देखा जाता था, हालांकि this is also very ironic. इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ही पूर्वजों ने बुशहर रियासत में हरी और लाल दोनों टोपियों को इसलिए शुरू किया था

15.03.2018/1520/केएस/एजी/2

because there had to be cultural assimilation. जो अलग-अलग समुदाय के लोग थे, उनको एक रंग में जोड़ने के लिए टोपियों का सिलसिला वहां से शुरू किया गया था मगर जिस तरह से इसका राजनीतिकरण पूर्व में किया गया था, इसमें जो मुख्य मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप किया है, और एक नई शुरूआत प्रदेश में की है उसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।जैसा मैंने कहा कि हम निन्दा में विश्वास नहीं रखते मगर मैं सरकार को इतना ही कहूंगा कि जो लोग आपकी निन्दा करते हैं, उनको आप अपने पास रखें ।

निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुवाय,

बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।

तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक और हृदय की सफाई में हम आप लोगों का समय-समय पर साथ देते रहेंगें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया गया है, मैं चाहता था कि उसका समर्थन करूं but because of the various reasons I am restrained to support this Budget that has been presented by the Hon'ble Chief Minister. Thank you.

15.03.2018/1520/केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जवाहर ठाकुर जी भाग लेंगें।

श्री जवाहर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में पहली बार आया हूं और बजट की चर्चा में पहली बार हिस्सा ले रहा हूं। मैं राजनीति में सन् 1977 से कार्य कर रहा हूं। मैं पंचायत का वार्ड मैम्बर, प्रधान, जिला परिषद का सदस्य भी रहा और चार बार मैं विधान सभा का चुनाव भी लड़ा हूं। 1998 में पहली बार हमारे वरिष्ठ नेता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री महेन्द्र सिंह जी द्वारा मुझको घर से बुलाया गया और मैंने पहली बार चुनाव लड़ा जिसमें मुझे असफलता मिली थी। मैं आज इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे व माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का भी बहुत आभारी हूं कि उनके प्रयासों से और द्रंग विधान सभा क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से मैं आज इस माननीय सदन में आपके बीच में हूं।

15.3.2018/1525/av/hk/1

श्री जवाहर ठाकुर----- जारी

मैंने 20 वर्षों के बाद अपनी मेहनत से एक ऐसे राजनीतिज्ञ की राजनीति को विराम लगाया है । (***)मैं चुनाव जीतकर इस सदन में पहुंचा हूं। (---व्यवधान---) अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज। नये सदस्य हैं, मेडैन स्पीच हैं और अगर कुछ कमी रह जायेगी तो उनको बतायेंगे।

श्री जवाहर ठाकुर : अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर उस व्यक्ति को विश्राम नहीं मिला होता तो आज मेरे छोटे भाई श्री मुकेश अग्निहोत्री जी माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी के साथ नहीं बैठते। (---व्यवधान---) मैंने 20 वर्षों में अपने राजनीतिक सफर में बहुत बजट देखे हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं वर्ष 1977 से राजनीति में हूं और वर्ष 1998 से सक्रिय राजनीति में आया हूं। यहां पर 9 मार्च, 2018 को जो बजट पेश किया गया है यह एक ऐसे मुख्य मंत्री द्वारा पेश किया गया है जो कि पहाड़ से सम्बद्ध रखने वाला, साधारण परिवार, अनेक व्यक्तित्व तथा नई सोच व नई आशा रखता है। माननीय मुख्य मंत्री ने इस बजट के द्वारा बच्चा पैदा होने से लेकर मोक्ष धाम तक का प्रावधान किया है। मेरे सामने बैठे हुए

भाइयों से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट बुक को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। इसमें 147 नई योजनाएं शुरू की गई हैं जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हमें विरासत में दी गई वित्तीय स्थिति व कर्ज के बावजूद इस बजट में गरीब किसान-बागवान, मुख्य मंत्री मधु विकास योजना, पंचायत प्रतिनिधि, पेंशन वृद्धि, युवा वर्ग, बेघर, कर्मचारी व प्रदेश के हर इनसान को लाभ दिया है। हमारी केंद्र सरकार की नीतियों को स्वीकार करते हुए 'सबका

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

15.3.2018/1525/av/hk/2

साथ, सबका विकास' इस बजट में दिखाई दिया है। प्रदेश में 90 प्रतिशत किसान व बागवान रहते हैं और लोगों के लिए यहां कृषि और बागवानी रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। साथ में, प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों की समस्या का समाधान करना, हर पंचायत में ओप्टिकल फाइबर की सुविधा देना, मुख्य मंत्री लोक भवन हेतु 30 लाख रुपये की राशि का प्रावधान करना, विधायक निधि को 1.25 करोड़ रुपये करना, ऐच्छिक अनुदान 5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये करना, किसानों को जल्दी से कृषि फल देना, चैक डैम तथा तालाबों, कूहलों व जल स्रोतों का नवीकरण करना, नई सौर सिंचाई योजना से किसानों के लिए ऊर्जा का संचार हुआ है। मुख्य मंत्री ने देसी गाय की नस्ल में सुधार, जैविक खेती, मजदूरों की दिहाड़ी 225 रुपये करना, मनरेगा में 120 दिन की बढ़ोतरी करना इत्यादि कई योजनाओं का शुभारम्भ करके खुशहाल किसान व बागवानों का राज्य बनाने की परिकल्पना की है जो कि हमारे विपक्ष के साथियों को रास नहीं आ रही है।

15.3.2018/1530/TCV/DC-1

श्री जवाहर ठाकुर..... जारी

मैं आज वन मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने वनों में आग न लगे, इसके लिए प्रयास किए हैं। इन्होंने जागरूकता की शुरूआत की है। यह एक अच्छा

प्रयास है, क्योंकि आग ही हमारे जंगलों का सबसे बड़ा नुकसान करती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने ऐसे बजट का वृक्ष लगाया है कि हमारे सामने वालों (विपक्ष) को भी छाया का लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बजट पर बहुत छींटाकशी की है। वे लोग पिछले साल तक सत्ता सुख भोगकर लोगों की आकाक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए लोगों ने उन्हें सामने वाली कुर्सी पर बिठाया है। उन्होंने कहा कि यह बजट दिशाहीन है, कोई रोडमैप नहीं है, ये गपोड़शंख, शेख़चिल्ली वाला बजट है। परन्तु हकीक़त में यदि इन्होंने जनता से गपोड़शंख और शेख़चिल्ली वाली बातें न की होती तो आज सामने वाली कुर्सी (विपक्ष) पर नहीं बैठते। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अधिकारी वर्ग पर भी छींटाकशी की है कि बोतल पुरानी है, लेकिन इसमें ग़रूर और सरूर पुराना नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें गंगा जल जैसा पवित्र जल है और इत्र जैसी खशबू है। इस जल को पूरे प्रदेश में छिड़क कर हर वर्ग का विकास किया जाएगा। मैं इनको कहना चाहूंगा कि 5 वर्षों में आपने अपनी पुरानी खाली बोतलों के सहारे सत्ता को चलाया है। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हम थोक के व्यापारी हैं। लेकिन इन्होंने 46 हजार 383 करोड़ रुपये का कर्ज़ लेकर प्रदेश को डूबोया है। स्कूल थोक में खोले गये हैं, उन स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बल्कि चालू स्कूलों से अध्यापक, खाली स्कूलों में भेजे गये हैं और गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। विशेषकर जो गांव में छात्र-छात्राएं हैं, उनको मीठा ज़हर दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले जंगल कटवाये , फिर सेब के पौधे लगाने की खुली छूट दी। लेकिन आज उन किसानों के सारे बागीचे काटे जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को नाजायज़ कब्ज़ों में काम करने की छूट दी गई। उन पर न्यायालय द्वारा बलडोज़र चलाये जा रहे हैं। इससे लोगों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। अच्छा होता यदि वन विभाग उन बागीचों को गरीब या अन्य लोगों को देता, जिससे सरकार को भी करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता था।

15.3.2018/1530/TCV/DC-2

अध्यक्ष महोदय, पशुओं के लिए ठीक गर्भाधान की व्यवस्था न होने के कारण आज किसानों को आवारा पशुओं की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे माननीय

मुख्य मंत्री, आवारा पशु प्रबंधन के लिए, शराब पर एक रुपया टैक्स लगाकर और मंदिरों के चढ़ावे से, इस धार्मिक कार्य के लिए धन का प्रावधान करते हैं, तो हमारे सामने वाले मित्रों (विपक्ष) को इससे तकलीफ़ हो जाती है। जबकि 5 वर्षों में उन्होंने किसानों की समस्या के लिए कोई भी कदम नहीं उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बंदरों की नसबन्दी पर लाखों रुपया खर्च किया गया है। परन्तु पकड़े हुए बंदरों को गाड़ियों में भरकर गांव के नज़दीक जो जंगल पड़ते हैं, वहां पर छोड़ा गया। जो आज किसानों का नुकसान कर रहे हैं, उसके लिए भी यही लोग दोषी है। आज बंदरों के बारे में जो ये चर्चा करते हैं, ये इनको शोभा नही देती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या श्रीमती आशा जी ने कहा था कि बजट की नींव ठीक नहीं है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस नींव को आपके अपने साथियों ने ही खराब किया है। इस पर कर्ज़ का महल खड़ा किया है। अब ठाकुर जय राम जी की सरकार को उसकी मरम्मत करने में समय लगेगा।

15-03-2018/1535/NS/DC/1

श्री जवाहर ठाकुर ------ जारी।

पिछली सरकार द्वारा बागवानों को इटली के वायरस वाला रूट स्टॉक दिया गया था, जो बागवानों के हित में नहीं है। मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी का रूट स्टॉक भी इटली का ही है। जो नये माननीय सदस्य चुन कर आपकी तरफ आये हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यदि श्री वीरभद्र सिंह जी का रूट स्टॉक हिमाचल प्रदेश में नहीं होता तो आपकी सीटों पर भी हमारे लोग मैक्सिमम होते। माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने जो बज़ट पेश किया है, मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा बज़ट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर अपने क्षेत्र की कुछ बातें रखना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सैंकड़ों किलोमीटर सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिना बज़ट और बिना डी0पी0आर0 के बनवायी गई हैं। मैं समझता हूं कि अन्य विधान सभा क्षेत्रों में भी ऐसी सड़कें बनी होंगी। हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 108 और 102 नम्बर एम्बुलैंसें चलाई जाती हैं मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई नया नियम बनायें कि छोटी गाड़ियां भी इसमें चलाई जायें ताकि लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन और भौगोलिक दृष्टि से, चाहे शिमला, सिराज़ या द्रंग का क्षेत्र है, इनकी एक जैसी भौगोलिक परिस्थिति है। आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से इन क्षेत्रों का ध्यान रखा जाये। इस माननीय सदन में विक्रमादित्य जी ने भांग के बारे में कहा है। पिछली सरकार ने इस पर बहुत बड़ी छूट दे रखी थी। लेकिन आज बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे हैं। यदि भांग या अफीम की खेती दवाई के लिए की जाये जैसे दूसरे प्रदेशों में भी इसकी खेती के लिए इज़ाजत है तो क्यों न हिमाचल प्रदेश में भी इसके लिए एक सीमा निर्धारित की जाए और इसको किसान बीघा या बिस्वा में उगायें। जैसे मलाणा का क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहां अच्छी फसल हो सकती है और कहां पर यह दवाई योग्य हो सकती है? इस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में इससे लाभ उठाया जा सके। मैं ज्यादा न कहते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया और पहली बार मुझे इस सदन में बोलने का मौका मिला है तथा इस बज़ट का तहदिल से हार्दिक समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय हिमाचल।

15-03-2018/1535/NS/DC/2

अध्यक्षः मुझे माननीय सदन को यह सूचना देते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी व श्रीमती मल्लिका नड्डा जी दीर्घा में पधारे हैं। आज सभी के सहयोग से श्री जे0पी0नड्डा जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार को सर्वसम्मति से राज्यसभा का सांसद चुना गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूं कि बिल्कुल साथ में सटे हुए मुख्य कमेटी रूम में 15 मिनट के लिए पधारें, जहां माननीय नड्डा जी, आपके साथ धन्यवाद चायपान करना चाहते हैं।

अब इस मान्य सदन की बैठक 15 मिनट, अपराह्न 03:55 बजे तक स्थगित की जाती है।

15.03.2018/1605/RKS/HK-1

(माननीय सदन की बैठक अपराह्न 4.05 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी बैठे थे इसलिए मैंने यह सोचा कि यह बात मैं बाद में कहूंगा। हमारे 9 बार विधायक रह चुके पूर्व सदस्य के बारे में जो माननीय सदस्य श्री जवाहर ठाकुर जी ने इंगित किया है, जो 2-3 शब्द कहें हैं, उनको आप रिकॉर्ड से डिलीट करवाने की कृपा करें।

अध्यक्षः जो ऐसे शब्द होंगे, जोकि अनपार्लियामैंट्री हैं उनको डिलीट किया जाए और मुझे दिखा दिया जाए। अब मैं माननीय महिला सदस्या, श्रीमती रीता देवी जी को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्रीमती रीता देवीः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे इस बजट सत्र में बोलने का मौका दिया। सरकार ने जो वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया है, वह काबिले तारीफ है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने इस बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा है जोकि उनकी दूरदर्शी एवं दूरगामी सोच का परिचय है। इस बजट से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस बजट में पेश की गई जन सुविधा के लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और उन्हें बधाई भी देती हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हैं, तब-तब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। जब वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। 50 % से भी ज्यादा महिलाएं आज पंचायतों में प्रधान, बी.डी.सी., मैम्बर्ज़ बनकर बैठी हैं। उसका श्रेय भी

15.03.2018/1605/RKS/HK-2

भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। इस बार भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हिमाचल गृहणी सुविधा योजना आरम्भ करने की बात कही है। इस योजना के तहत जो परिवार भारत सरकार की 'उज्ज्वल योजना' के तहत नहीं आते हैं, उन परिवारों को भी प्रदेश सरकार रसोई गैस

सिलेंडर की जमा राशि तथा गैस चूल्हे के लिए आर्थिक मदद देगी। जिससे मेरी बहनों को ईंधन की लकड़ी इक्ट्ठा करने के लिए जंगलों में नहीं भटकना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए महिला मंडल को प्रोत्साहित करने जा रही है। इसके लिए महिला-मंडलों को समुचित अनुदान भी दिया जाएगा जोकि एक सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की सबसे निम्न इकाई पंचायती राज है। 14वें वित्तायोग में जिला परिषद् तथा पंचायत समितियों का अनुदान बंद कर दिया गया है। मगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में वर्ष 2018-19 के लिए 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। जिससे जिला परिषद् व पंचायत समिति के सदस्यों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में मदद होगी।

15.03.2018/1610/बी0एस0/एच0के0-1

श्रीमती रीता देवी .....जारी

साथ ही साथ पंचायती राज संस्था में प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूं । महोदय, प्रदेश में इस समय लाखों लोगों को मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत हुए है। जिसमें केन्द्र सरकार की तरफ से 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है । महोदय, मैं लाखों मनरेगा मजदूरों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चहती हूं जिन्होंने मनरेगा मजदूरों के लिए 100 दिन का रोजगार बढ़ाकर 120 दिन करने का प्रावधान इस बजट में किया है।

महोदय, सरकार ने गुड़िया हेल्पलाइन और शक्ति ऐप शुरू की, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। इस हैल्प लाइन से प्रदेश में अप्रिय घटनाओं को रोका जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की और दिलाना

चाहती हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र इन्दौरा है। हिमाचल में अगर कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो वह इन्दौरा है। जिसमें बहुत ही ज्यादा समस्याएं है।

सबसे पहले मैं सड़कों की समस्या के बारे में कहना चाहूंगी । 2012 में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तो पहला दौरा माननीय मुख्य मंत्री का इन्दौरा का किया था। वहां जाते ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इन्दौरा की सड़कों का इतना बुरा हाल है? और कहा कि मैं इन सड़कों को छः महीनों में हेमा मालिनी के गालों की तरह बना दूंगा। अध्यक्ष महोदय, छः महीने तो क्या पूरे पांच सालों में हमारी पांच किलो मीटर सड़क भी नहीं बनी। मेरे चुनाव क्षेत्र में णोई क्षेत्र है जिसमें पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि आज भी 7 पंचायतें वहां ऐसी है जिनमें मेरी बहने चार-चार किलोमीटर दूर से सिर पर घड़ा उठाकर पानी लाती है। इसे देख कर बहुत दुख होता है कि यह हमारी विधान सभा क्षेत्र की हालत है। मेरे चुनाव क्षेत्र की सीमा पंजाब से लगती है। पंजाब में इतना ज्यादा नशे का चलन हो गया है कि वहां से हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में इसका प्रभाव दिख रहा है और वे इसकी चपेट में आ गई हैं। हमने पिछले मुछ महीने में तीन-चार बार गांव वालों के साथ

रैलियां निकाली , लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की मेरा अपनी सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस नशे का समाधान जरूर निकाले । मेरे क्षेत्र में एक समस खड्ड पड़ती है। जिससे बरसात के दिनों में फसलों को नुकसान तो होता है लेकिन दो मेरी पंचायतें तौकी और कन्दरोड़ी ऐसी हैं जिनमें घरों में पानी चला जाता है। पानी चार-चार फुट तक उन लोगों के घरों तक चला जाता है। लोगों को घर से बेघर होना पड़ता है। घर का सामान हमने तैरते हुए देखा है। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि उसमें भी पूर्व सरकार ने तट्टीयकरण करने का निर्णय लिया था लेकिन 34 किलोमीटर जो खड्ड है उसमें केवल 5 किलोमीटर बनी है, बाकी सब वैसी की वैसी है। वह कार्य अधर में लटका हुआ है। इसी तरह मढ़ क्षेत्र है उस मढ़ क्षेत्र में ब्यास नदी पड़ती है उसमें भी यही समस्या है कि जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो मेरे लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि उनको घर से बे घर होना पड़ता है । फसल का तो नुकसान होता ही है लेकिन काफी घरों में वह पानी

जाता है। दो हजार एकड़ जगह में लोग फसल लगाते हैं और भूमि भी वह इतनी उपजाऊ है कि हिमाचल को अनाज दे सकती है। लेकिन समस्या यही है कि उसका भी तट्टीयकरण करने की जरूरत है। मेरा सरकार से मुख्य मंत्री जी से यही विनम्र निवेदन रहेगा कि उस पर ध्यान दे। ये मेरे क्षेत्र की समस्या हैं मैं चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन समस्याओं का जरूर हल निकालेंगे और मेरी अपील भी यही है। मैं इस बजट का पुर-जोर समर्थन करती हूं, प्रशंसा करती हूं साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः धन्यवाद। अब इस चर्चा में श्री मोहन लाल ब्राक्टा भाग लेंगे।

15.03.2018/1615/डी0टी0/एच0के0-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री, श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा 9 मार्च 2018 को इस सदन में वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं, मैं इस संदर्भ में बोलने को खड़ा हुआ हूं। मुझ से पूर्व दोनों पक्षों के वक्तओं द्वारा इस बजट पर लम्बी चौड़ी बातें की गई है। जहां तक इस बजट की बात है, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और मेरा यह मानना है कि इस बजट में ऐसी कोई नई बात नहीं दिखती जैसा की हम माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी से अपेाक्षा कर रहे थे। इस बजट में दो-तीन बातें ऐसी हैं जिसके लिए मै माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। एम0एल0ए0 फण्ड जो 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 25 लाख हुआ, इसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूं। इस संदर्भ में मैं हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री, राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होनें पहले इसे 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया फिर 75 लाख से बढ़ाकर इसे 1 करोड़ किया गया तदुपरान्त इसे 1 करोड़ से बढ़ाकर 1 करोड़ 10 लाख किया। अब वर्तमान माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा इसे 15 लाख और बढ़ाया गया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मै माननीय मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, जैसा की मेरे पूर्व कुछ और माननीय सदस्यों ने भी कहा, की अगर इसे 1 करोड़ 50 लाख किया जाता तो और भी अच्छा होता।

अगर यह बढ़ता है तो विकास के कार्यो के लिए इसका काफी फायदा होगा। जैसा माननीय सदस्य जानते ही हैं कि जो हमारी विधायक निधी थी उसको भी हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री, श्री वीरभद्र जी द्वारा ही 5 लाख रूपये किया गया था । हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री, श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा इसे 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और साथ में यह भी आग्रह करता हूं कि अगर इसे 7 लाख की जगह 10 लाख किया जाता तो अच्छा होता। इसके अतिरिक्त जो सिक्योरटी पैंशन की बात यहां कही गई है जिसमें आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया है, मैं इस माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि यह पैंशन सुविधा भी कांग्रेस की

15.03.2018/1615/डी0टी0/एच0के0-2

पूर्व सरकार द्वारा ही चलाई गई थी। मनरेगा के अन्तर्गत कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया गया है यह एक अच्छा कदम है। इसके अलावा इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे यह लगे कि मै इस बजट का समर्थन करूं। मै अपने जिला शिमला की बात करूंगा, इस बजट को मैने पूरा सुना और मै सोच रहा था की माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जिला शिमला की स्थिति के लिए इस बजट में कुछ करेंगे कोई प्रोजैक्ट देंगे, कोई स्कीम देंगे पर शिमला जिला के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे रोहडू विधानसभा क्षेत्र का नाम तक मुख्य मन्त्री के बजट भाषण में कहीं नहीं आया। जहां तक केन्द्र सरकार की बात है, जैसा की हम सभी जानते हैं कि 2014 में जब लोक सभा के चुनाव हुए थे, उस समय चुनाव की कैम्पेनिंग के दौरान, मै केन्द्र सरकार की बात इस लिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने, झूठे वायदे करने में माहिर है। उस समय हमारे माननीय प्रधान मन्त्री हो या उनके मन्त्री मण्डल का कोई और सदस्य हो, उन्होनें बड़े-बड़े वायदे किये थे, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख आयेंगे। नौजवान लोगों को रोजगार दिया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नौजवान लोग भी ठगे गये। मंहगाई

कम होगी ऐसा कहा गया लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा हर चीज पर जी0एस0टी0 लगा दिया गया। कल ही उत्तर प्रदेश और बिहार के उप चुनावों का परिणाम आया है ।

15.03.2018/1620/SLS-YK-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा...जारी

इस रिजल्ट से केंद्र सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है। बात थी कि अच्छे दिन आएंगे, वह नहीं आए। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और मंत्रियों से भी आग्रह रहेगा कि केंद्र में आपकी सरकार है, वहां से हमें स्पैशल पैकेज मिले। अभी-अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर कर्ज़ के स्थान पर केंद्र सरकार स्पैशल पैकेज दे तो उससे लाभ हमें होगा।

कर्ज़ की जहां तक बात है, जब आप लोग इधर थे और हम उधर बैठते थे, उस वक्त आप यहां से चिला-चिलाकर बोलते थे कि हिमाचल सरकार कर्ज़ लेती जा रही है। आज अभी दो महीने के लगभग सरकार बने हुए हैं, आप भी कर्ज़-पर-कर्ज़ ले रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की स्टेटमैंट आती है कि मैं घर के लिए कर्ज़ नहीं ले रहा हूं। जब पूर्व मुख्य मंत्री कर्ज़ लेते थे तो क्या वह घर के लिए लेते थे? आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें यहां पर अपने निर्वाचन क्षेत्र की भी रखना चाहूंगा। माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हैं। मेरा इनसे अनुरोध है, मेरा कुछ दिन पहले एक विधान सभा प्रश्न भी लगा था जिसमें मैंने पूछा था कि रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में हमारी LWSS की जो मेज़र स्कीम्ज हैं वह पैंडिंग कितनी हैं? मुझे मंत्री महोदय का उत्तर मिला था कि ऐसी 19 स्कीमें हैं। मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि आज की तारीख में, जहां तक आई.पी.एच. रोहड़ू की बात है, उसके कार्य में काफी सुस्ती नज़र आ रही है। उसको चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको करेंगे।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी सदन में आ गए हैं। मेरा स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह रहेगा, मैं सिविल हॉस्पिटल रोहड़ू की बात करना चाहूंगा कि जो हमारा सिविज हॉस्पिटल रोहड़ू है, उस हॉस्पिटल में अगर आप डेली की ओ.पी.डी.

15.03.2018/1620/SLS-YK-2

रजिस्ट्रेशन देखें तो वह हमारे डी.डी.यू. हॉस्पिटल शिमला के बराबर की है। वहां डेली इतने ज्यादा पेशैंट आते हैं। वहां केवल रोहड़ू से ही रोगी नहीं आते बल्कि साथ में हमारा जुब्बल निर्वाचन क्षेत्र भी है जहां से रोगी आते हैं। वहां उत्तराखंड से भी रोगी आते हैं। वहां पर काफी भीड़ रहती है। वहां पर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के कारण डाक्टर्ज़ की सैंक्शंड स्ट्रैंथ 30 है। लेकिन अगर आज आप वहां पर देखें तो केवल 10 डॉक्टर हैं और डॉक्टरों के 20 पद खाली पड़े हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इन पदों को जल्दी-से-जल्दी भरने के आदेश दें ताकि जो हमारे दूर-दराज से गरीब लोग आते हैं, उनको छोटी-छोटी बीमारी के इलाज के लिए शिमला न आना पड़े। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने रोहड़ू दौरे के दौरान एक सी.एच.सी. सुडांसु, चिड़गाव का दर्ज़ा सिविल हॉस्पिटल का किया गया है। मैंने विधान सभा में एक प्रश्न भी लगाया था जिसका मुझे उत्तर मिला कि इसमें औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। मेरा आपसे भी और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध है कि जब घोषणाएं होती हैं तो उस वक्त सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। जब माननीय मुख्य मंत्री कहीं घोषणा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब औपचारिकताएं पूर्ण हुई हों। अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय कुछ देर पहले बोल रहे थे कि पहले कुछ संस्थान कागज़ों में ही थे, स्पॉट पर नहीं थे। मेरा आग्रह रहेगा कि उस हॉस्पिटल के सिविल हॉस्पिटल के दर्ज़े को बरकरार रखा जाए। साथ-ही-साथ डॉक्टर्ज़ के जो पद खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए भी मेरा आग्रह रहेगा। मैं एक बात कहना तो नहीं चाहता था लेकिन आप भी पिछली बार यहां से

कहते थे कि जो पूर्व सरकार थी या हमारे पूर्व मुख्य मंत्री राजा साहब हैं वह फट्टों-पर-फट्टे लगाने पर विश्वास रखते हैं।

15/03/2018/1625/RG/AG/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा-----जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी -----(घण्टी)----जो अभी यहां पर नहीं हैं, शायद कहीं चले गए हैं। उन्होंने अभी रोहड़ू का दौरा रखा। अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने रोहड़ू का दौरा रखा। एक सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया और वह भी अधूरी थी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करिए क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : दूसरी सड़क का उन्होंने भूमि पूजन किया, उसके भी टेण्डर नहीं लगे थे और तीसरी सड़क जिसका भूमि पूजन पहले ही हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी कर दिया था, उसका भी भूमि पूजन कर डाला। तो ऐसा अधूरा काम करने की क्या आवश्यकता थी? अभी तो आपके पास पांच साल बाकी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मत आओ या आप उद्घाटन नहीं करो। जब सड़क पूरी बन जाती ताकि सारे लोगों को फायदा होता तब उसका उद्घाटन करते। तो ऐसी-ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं यहां सदन में रखना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, अन्त में जब बजट की बात आती है, तो इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मैं इस बजट का समर्थन करूं। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

15/03/2018/1625/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री हीरा लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हीरा लाल : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री मान्यवर श्री जय राम ठाकुर जी ने वर्ष 2018-19 का जो बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया, वह गांव, गरीब, मजदूर, किसान, बागवान, कर्मचारी, युवा एवं महिला सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक और पारदर्शी बजट यहां पेश किया है। मैं माननीय श्री जय राम ठाकुर जी के सम्मान में दो शब्द कहना चाहूंगा :

'हे महारथी, पुण्यपथी आपको प्रदेश का चिन्तन करते देखा है, इसमें 'महारथी' बोलने का मतलब यह है कि महारथी आप लगातार पांच बार विधान सभा के सदस्य चुनकर आए हैं और आप एक गांव और एक गरीब घर में जन्म लेकर आज हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और 'पुण्यपथी', इसका तात्पर्य कि आपने इस प्रकार का पुण्य किया है कि ऐसा बजट विधान सभा में पेश किया है जो सभी के हित में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 'हे महारथी, पुण्यपथी, आपको प्रदेश का चिन्तन करते देखा है, चिन्ता है प्रदेश के उत्थान की, बजट में प्रावधान करते देखा है। '

अध्यक्ष महोदय, हमारा यह हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहां प्राकृतिक सौन्दर्य है। ऊंची-ऊंची पहाड़ियां और देवदार के हरे वृक्ष का नजारा यहां देखते ही बनता है। यह धार्मिक आस्थाओं का भी केन्द्र है, धार्मिक स्थल, देवी-देवताओं के यहां प्राचीन मंदिर हैं और यह एक आदर्श राज्य है। दूसरे राज्यों में भी इसकी प्रशंसा होती है। मैं जहां माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में इन्होंने इस बजट में काफी कुछ दिया है। हमारे यहां एक पर्यटन उद्योग है और पर्यटन के बारे में यहां बहुत चर्चा हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने 'नई राहें, नई मन्ज़िल' पर्यटन के क्षेत्र में एक नई योजना शुरू की है। इसमें जो अनछुए स्थान हैं जहां पर आज पर्यटन नहीं पहुंचा है। उन स्थानों तक जाने की आवश्यकता है। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की सुविधा हो, यहां आने-जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था हो और इन क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा हो एवं मूलभूत सुविधाएं इन पर्यटक स्थलों पर पहुंचे ताकि हमारे प्रदेश में अधिक-से-अधिक पर्यटक आएं। इससे हमारे यहां युवाओं के लिए स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

15/03/2018/1630/MS/ag/1

श्री हीरा लाल जारी----

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उच्च श्रेणी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हैली टैक्सी सेवा का आरम्भ करने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। मैं मुख्य

मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारा तत्तापानी जोकि पर्यटन की दृष्टि से एक धार्मिक स्थल है इसकी बात भी बजट में कही गई है। यहां पर गर्म पानी के स्त्रोत और गर्म पानी के चश्मे भी हैं। यहां पर जो कोल डैम बना है उसमें जल क्रीड़ा के लिए भी प्रयास किया गया है। पूर्व मुख्य मंत्री जी बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं। अध्यक्ष जी, मेरे चुनाव क्षेत्र के अगली तरफ शिमला ग्रामीण सुन्नी है और दूसरी तरफ तत्तापानी है परन्तु वहां के लिए आपने अपनी आंखें बन्द करके रखीं। श्री विक्रमादित्य जी मेरी बात सुनकर हंस रहे हैं। -(व्यवधान)- हमने वहां पर हड़ताल भी की। तत्तापानी में जो भी श्रद्धालू आते हैं उनके लिए वहां पर कोई भी घाट सही ढंग से नहीं बने हैं। आप मेरे साथ चलिए और देखिए कि तत्तापानी का क्या हाल है। वहां पर पिछले पांच सालों में पर्यटन की दृष्टि से कुछ नहीं किया गया है। वहां पर एन0टी0पी0सी0 है और करोड़ों रुपयों का बजट है इसलिए कुछ कर सकते थे लेकिन जब मंशा ही नहीं थी तो कैसे करते?

ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। हमारा जो करसोग क्षेत्र है उसमें आगे चिण्ढीवाला क्षेत्र है जहां पर पर्यटन निगम का होटल बहुत बढ़िया बना है। उसके साथ-साथ हमारा माहुनाग है जोकि पहाड़ी क्षेत्र में बसा है। वह क्षेत्र धार्मिक आस्था से जुड़ा है और वहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ-साथ जो शिकारी मां है वह बखरोट से सीधा 17 किलोमीटर आगे पड़ती है और उसके साथ ही जंजैहली है। शिमला से नालदेहरा, नालदेहरा से तत्तापानी-सुन्नी और उसके पश्चात चिण्ढी और चिण्ढी के पश्चात बखरोट और जंजैहली होते हुए फिर सीधा हम शिकारी देवी पहुंचते हैं। इसको भी पर्यटन की दृष्टि से उभारा जा सकता है।

मैं पर्यटन और लोक निर्माण के बारे में कहना चाहूंगा कि इसकी सीढ़ी क्या

15/03/2018/1630/MS/ag/2

है। जब तक हमारी सड़कें ठीक न हों जोकि हमारी भाग्य रेखाएं हैं जिनकी यहां पर काफी चर्चा भी हुई है, इससे ही पर्यटन बढ़ता है। मैं केन्द्रीय भाजपा सरकार और माननीय अटल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसके तहत वर्ष 2000-01 में "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" शुरू करके हिमाचल प्रदेश में लगभग 2300 करोड़ रुपये का बजट आज तक

पहुंचा है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के हर गांव में सड़कें पहुंची हैं और करसोग क्षेत्र में भी सड़कें पहुंची हैं। मेरा प्रश्न भी था कि "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" के तहत मेरे क्षेत्र में 83 सड़कें स्वीकृत हुई हैं जोकि वर्ष 2014-17 तक है और वर्ष 2017-2018 में 600 करोड़ रुपये और देकर 2300 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल को दिए हैं। इसके लिए मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। आप कहते हैं कि माननीय मोदी जी ने क्या किया। मैं आपको बता दूं कि ये सड़कें जो हमारी भाग्य रेखाएं हैं उनके लिए केन्द्र सरकार ने प्रयत्न किया है।

आपने फोरलेन और नेशनल हाइवेज की बात कही। यहां 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत हुए हैं जिनके लिए लगभग 65000 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत हुई है। पीछे 280 करोड़ रुपये इनकी डी0पी0आर0 बनाने के लिए दिया था लेकिन आपने नहीं बनाई। अभी जब मैं करसोग गया था तो मुझे रास्ते में सर्वेयर मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नेशनल हाइवेज की डी0पी0आर0 बनाने के लिए हम यहां पर आए हैं। मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 65000 करोड़ रुपये हिमाचल के राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए दिए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने भी -(व्यवधान)- आप हमारे साथ हमारे क्षेत्र करसोग में चलिए। जब वहां पर माननीय वीरभद्र सिंह जी आए तो उस समय वहां पर सड़कों में थोड़ी लीपा-पोती की गई कि माननीय राजा साहब आ रहे हैं उसके बाद कोई भी सड़कों का कार्य वहां पर नहीं हुआ। अब वहां पर टारिंग/मैटलिंग के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह से नई योजना "हिमाचल रोड इम्प्रूवमैंट स्कीम" के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।

15.03.2018/1635/जेके/एजी/1

श्री हीरा लालः------**जारी**-------

और जहां पर ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको काटने के लिए 50 करोड़ और साथ-साथ गांवों के लिए हमारी सड़कें जाएं उसके लिए "मुख्य मंत्री सड़क योजना" में 50 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हमारे

स्वास्थ्य संस्थान हैं, प्रधान मंत्री सुरक्षा कार्यक्रम है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जो कि बिलासपुर में 1, 351 करोड़ रूपए की लागत से बनाया जाएगा, उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट के अन्दर अपनी स्पीच खत्म करें।

श्री हीरा लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आते ही पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया बजट दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर संस्थान खोले गए, अभी हमारे करसोग में एक सीनियर सैकेंडरी स्कूल पुरला में खोला गया। वहां पर केवल एक प्रिंसिपल है और दूसरा जो सीनियर सैकेंडरी स्कूल का नाम तेबन है मगर वह अशला में है, इसकी दूरी केवल तीन किलोमीटर के अन्दर-अन्दर है। जो पुरला है वहां पर, नराहल और शिलवा केवल तीन गांव हैं, इनमें चौथा गांव कोई आता नहीं है। इन तीन गांवों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक प्रिंसिपल है। वहां पर न टीचर्ज का प्रावधान, न जगह का समाधान और न ही बच्चों का इन्तज़ाम। वहां पर बच्चे भी नहीं है। मुझे फोन आ रहे हैं कि टीचर भेजो और जब मैं पूछता हूं कि कितने बच्चें हैं तो कहते हैं कि छः बच्चें हैं। वह प्लस टू स्कूल है। इन संस्थानों का क्या किया जाए, हम समस्या में हैं? अभी पॉलिटैक्निकल कॉलेज की बात आई। यह तो केवल जाते-जाते, जब दो दिन रहे तब इसकी घोषणा की है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पारदर्शी सरकार है। आपके अच्छे विचार है। आप इस विषय में अच्छे कदम उठा करके जब निश्चित

15.03.2018/1635/जेके/एजी/2

समय आएगा तब आप इस विषय में अच्छा कदम उठाएंगे। उन संस्थानों को आगे चलाएंगे। अब घंटी बज चुकी है। पॉलटैक्निकल कॉलेज की आप जाते-जाते घोषणा करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में शुरू हुई है,

अभी आगे इसमें बहुत कुछ होना है। एक बार फिर से दो शब्द बोलना चाहूंगा कि फ़कीरी में भी आप हमें अमीर नज़र आते हैं, माननीय ठाकुर जय राम जी, फ़कीरी का मतलब है यहां हिमाचल प्रदेश में इतने ज्यादा आर्थिक संसाधन नहीं है और यहां पर पिछली सरकार कर्ज़ से चल रही थी, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया।

फ़कीरी में भी आप हमें अमीर नज़र आते हैं,

तुफां में आप हमें साहिल नज़र आते हैं,

हमने ऐसा बजट नहीं देखा है,परन्तु आप हमें गरीबों के मसीहा नज़र आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का बहुत-बहुत पुरज़ोर से समर्थन करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.03.2018/1635/जेके/एजी/3

अध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य, श्री राजेश ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री राजेश ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस बजट की चर्चा में खुद को सम्मिलित करके गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि मुख्य मंत्री, जय राम ठाकुर जी ने इस बजट में गांव, गायं और समाज के हर वर्ग की चिन्ता करके अपनी परिपक्व सोच का परिचय दिया है। इस बजट को देख कर कौन कह सकता है कि मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी का यह पहला बजट है। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा अतीत के सदनों से परिचित करवाना चाहता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि प्रदेश में ज्यादा समय राज़ कांग्रेस सरकार ने किया। इस प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस का एक ही लक्ष्य रहा किसी तरह से सत्ता को हासिल करना न कभी पहाड़ की चिन्ता की गई और न कभी पहाड़ के लोगों की चिन्ता की गई। कांग्रेस की एक ऐसी योजना बता दें जो मील का पत्थर साबित होती हो।

15.03.2018/1640/SS-DC/1

श्री राजेश ठाकुर क्रमागतः

पूर्व कांग्रेस सरकार की अगर बात की जाए तो विधान सभा क्षेत्र गगरेट में एक नगर पंचायत के अंदर एक मल-निकास योजना का शिलान्यास करके आए थे। परन्तु दुख की बात है कि पांच साल तक वहां पत्थर भी नहीं लगा। उसके बाद धूमल सरकार ने भंझाला (गगरेट) में इंडियन ऑयल डिपो की घोषणा की थी। 302 कैनाल भूमि हस्तांरित होनी थी परन्तु सरकार बदल गई और इंडियन ऑयल का डिपो बदलकर रामपुर क्यों ले जाया गया जिससे अनेकों लोगों को रोजगार मिलना था। इंडियन ऑयल का डिपो तो बदला, राजनीतिक भेंट चढ़ा। पूर्व सरकार की सिंचाई एवं जन-स्वाथ्य मंत्री, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी दौलतपुर चौंक में आईं। बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलना था और तीस नलकूप देने की घोषणा कर गई जबकि न कोई बजट की व्यवस्था की गई और न ही आज तक वह कार्यालय खुला। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राज्यसभा सांसद, विप्लव ठाकुर आईं। उन्होंने तीन इंडो स्टेडियम खोलने की बात कही। एक स्टेडियम वहां के विधायक के घर के पास बना, पूरे पांच साल लगे और दो स्टेडियम का पता ही नहीं चला। हमारी सरकार जब-जब भी आई है शांता कुमार जी ने पानी वाले मुख्य मंत्री के नाम पर अपना नामकरण किया है वहीं धूमल जी ने सड़क वाले मुख्य मंत्री के नाम पर नामकरण किया है। आज कांग्रेस की सरकार बताए कि उनको किस नाम से पुकारा जाए। घोषणाओं की सरकार के नाम से पुकारा जा सकता है। उनको किसी और नाम से नहीं पुकारा जा सकता। हमारी सरकार में स्वां तटीयकरण योजना आई। आपको पता है कि धूमल सरकार ने यह 900 करोड़ की योजना मंजूर करवाई थी। परन्तु उसका भी आज काम बंद पड़ा है। अंत में 2017 में 53 करोड़ की लास्ट किस्त आई। हमें आज तक पता ही नहीं चला कि वह किस्त कहां गई और काम रूका हुआ है।

माइनिंग के ऊपर बड़ा जोर से बोला जाता है। माइनिंग, खनन माफिया, परन्तु आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत सी सरकारों में जब विधायक माइनिंग का मुद्दा यहां उठाकर जाते हैं तो उनके घरों में भीड़ लग जाती है। यह भी होता आया है। हमारे किशन कपूर जी, पूर्व सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उस वक्त इंवायरनमैंट क्लीयरैंस की बात आई। पूरे प्रदेश

के क्रशर्ज़ को बंद करना पड़ा। परन्तु शॉर्ट टर्म परमिट देकर उस वक्त इन्होंने क्रशर चलाए। उस वक्त

15.03.2018/1640/SS-DC/2

फिशरीज़ पौंड और सड़क की कटिंग के ऊपर क्रशर चलाने पड़े क्योंकि एकदम केन्द्र सरकार ने क्रशर बंद कर दिए थे। परन्तु किसी को भी धर्मशाला से घूमकर शिमला नहीं जाना पड़ता था। लेकिन पूर्व सरकार में क्रशर के ऊपर इतनी मार पड़ी कि उनको ऊना से घूमकर शिमला जाना पड़ता था। तीन-तीन महीने के परमिट दिए जाते थे। एक महीना तो रास्ते में ही गुजर जाता था। चार-चार चक्कर लगाने पड़ते थे। दीपक वर्सिज़ स्टेट में 2013 में एन0जी0टी0 ने ऑर्डर पास किया, जिसमें प्रेम कुमार धूमल जी ने राहत दी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2005 में 50 रुपये पर टन, जिसकी बात माननीय अध्यक्ष जी करते थे कि 80 करोड़ की देनदारी क्रशर्ज़ पर है। उसको 500 गुणा 500 टन के हिसाब से पैनल्टी डाली गई। आज हाई कोर्ट में क्रशर उद्योग वाले लड़ रहे हैं। पूरे देश में हरियाणा, जम्मू, पंजाब कहीं भी जे0सी0बी0 बंद नहीं है। परन्तु क्रशर जितना मर्जी लीगल हो जाए अपनी जमीन अपनी खरीद के बाद उसको एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती है। ज्वाइंट इंस्पैक्शन करवानी पड़ती है। डेढ़ साल लग जाते हैं। परन्तु घूमते-घूमते जब तक वह क्रशर सिर पर चढ़ने लगता है उसके बाद ब्लैकमेलिंग और कई बातें चल पड़ती हैं। हम चाहते हैं कि जिसने गलत किया है वह क्रशर बंद हो परन्तु हर व्यक्ति को खनन माफिया के नाम पर यहां पुकारा जाता है। आज पूरे प्रदेश में जितने भी क्रशर चल रहे हैं, यह सदन देख रहा है कि खनन जे0सी0बी0 से हो रहा है। परन्तु परमिशन नहीं है। हमारे उद्योग मंत्री जी आए हैं मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा प्रावधान कीजिए कि जे0सी0बी0 के ऊपर जितनी मर्जी सिक्योरिटी रखकर क्रशर वालों को जे0सी0बी0 की परमिशन देनी चाहिए।

15.03.2018/1645/केएस/एचके1

श्री राजेश ठाकुर जारी---

आज के वक्त में लेबर से कोई क्रशर नहीं चला रहा और जो गलत करेगा उसको जैसे मर्जी आप दंड दे सकते हैं परन्तु जब जे.सी.बी लगती है वहां अधिकारियों को, डी.एस.पी., एस.डी.एम. को भेजा जाता है उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी,

लगातार किसी की सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं बनी। श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के सम्माननीय मुख्य मंत्री रहे हैं । ये छः बार मुख्य मंत्री रहे परन्तु इन्हें भी दोबारा सरकार रिपीट करने का मौका नहीं मिला। धूमल जी, शांता कुमार जी की सरकार भी दोबारा रिपीट नहीं हुई।

अध्यक्ष जी, जय राम ठाकुर जी की सरकार ने जो गाय की बात की है, गौ-सम्बर्द्धन की बात की है, मैं उस पर बोलना चाहता हूं कि गौमाता के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी ने एक रुपया टैक्स लगाया तो कहा गया कि गौमाता के ऊपर टैक्स क्यों लगा दिया, शराब के ऊपर टैक्स क्यों लगा दिया? आज गाय हमारी मूल है । 33 करोड़ देवी-देवता जिसमें वास करते हैं उस गाय की आज क्या दशा है? पूर्व सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश पर डमटाल में एक गऊशाला खोली। खोलने की जब घोषणा हुई, उससे पहले ही ट्रकों में गायों को भरकर वहां पर फेंका गया। पंचायत के चुनाव थे। कुछ तो रेलवे से कटकर मरीं और कइयों को ट्रक एक्सिडैंट में मरना पड़ा। कई लोगों की वहां मृत्यु हुई। उस वक्त मैंने अखबार में दिया। वहां रोज की दस गाय मरती थी और उनको जे.सी.बी. से गड्ढा करके दबाया जाता था। हमारे बीच आज वह विधायक नहीं है । हमारी पार्टी की वजह से जीतकर उस तरफ गए थे मैंने उनसे एक बार कहा कि विधान सभा में आप खनन-खनन करते हैं और फिर छः महीने के लिए चुप हो जाते हैं। एक बार आप गाय का मुद्दा तो उठाओ। दस गाय रोज़ की डमटाल में मर रही हैं। आपने इसके बारे में सदन में क्या कहा? परन्तु वे इस बारे में सदन में कुछ नहीं बोले और आज वे यहां पर नहीं है। हम गऊ की पूजा करने वाले लोग है । माता के दूध के बाद हमें गाय का दूध जीवन भर

15.03.2018/1645/केएस/एचके2

मिलता है। उसके बाद हमारी सरकार आई तो भी वहां डमटाल में गाय मरने लगीं और गाय मरी, रीता धीमान विधायक को फोन गया, जिंदा गाय को कुत्ते खींचकर ले जा रहे थे। अखबार में खबर लगी। वहां का पूर्व अधिकारी आज भी मंदिर को सम्भाल कर बैठा है। मैंने कहा कि अगर तुम गऊशाला नहीं चला सकते तो खोली क्यों है, तुमने तो गऊशाला को

कब्रिस्तान बना दिया? बहुत सी गऊशालाएं खोली गई परन्तु उनका सम्वर्द्धन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। एक गऊशाला डाकलाड़ा में खोली थी वहां पर 35 गाय भूख के कारण मर रही थी। मैं उनको खोल कर ले गया। इस सदन का अगर एक भी सदस्य गऊशाला चलाता है तो मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं खुद भी चलाता हूं। मेरे पास 200 गाय कंदरौड़ी में हैं। कोई भी जा कर देख सकता है उसका एक लाख 10 हजार रुपया मैं महीने का खर्च करता हूं। वह गऊशाला बदरी विशाल मंदिर में चल रही है। डी.सी. प्रजापति जी आज भी हमीरपुर में हैं उन्होंने खुद बताया था कि हिमाचल में अगर कोई गऊशाला चल रही है तो वह कंदरौड़ी की है।

अध्यक्ष जी, हमेशा आर.एस.एस. के बारे में यहां पर बात की जाती है। आर.एस.एस. का मतलब आपने तो सदन में कई बार समझाया होगा परन्तु मैं दो मिनट लूंगा। स्व प्रेरणा से, निस्वार्थ भाव से, राष्ट्रवाद समाज के हितों के कार्य करने वाला स्वयं सेवक होता है। कहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री ही के इर्द-गीर्द स्वयं सेवक, आर.एस.एस. के लोग घूम रहे हैं। अगर अच्छे लोग मुख्य मंत्री जी के साथ होंगें तो किसी को क्या आपत्ति है? इनको तो बधाई देनी चाहिए कि अच्छे लोग रखे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा पाकर 70 से ज्यादा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसा कोई जिला और ब्लॉक नहीं जहां संघ का कार्य न हो रहा हो। 41 से ज्यादा देशों में संघ का कार्य चल रहा है और अरब के देशों में भी संघ का कार्य चल रहा है। अपने से प्रेरित संगठन पूरे देश में दो-पौने दो लाख सेवक कार्य कर रहे हैं। समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। माननीय विपक्ष के नेता यहां पर बैठे हैं इनके जीजाजी श्री कुलभूषण शर्मा जी बड़े अच्छे स्वयं सेवक हैं, मैं इनको बधाई देता हूं।

15.3.2018/1650/av/hk/1

श्री राजेश ठाकुर----- जारी

कभी भी उनको पूछ लेना। अन्त में मैं एक शेर कहना चाहता हूं :-

तुमने चाह ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे,

तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, बनते दरिया तो दूर निकल सकते थे।

अब मैं श्री जय राम ठाकुर की तरफ से शेर कह रहा हूंः-

अपने पहले बजट का मैं इतिहास हो जाऊंगा, तुम्हारे विरोध करने से क्या मैं छोटा हो जाऊंगा।

तुम मुझे गिराने को लगे हो, तुम समझते नहीं, मैं गिरा तो मुद्दा बन के खड़ा हो जाऊंगा।।

हिमाचल की जनता वाकिफ़ है मेरे ऐहदे वफ़ा से, क्या विपक्ष के कहने से मैं बेवफा हो जाऊंगा।

अभी चलने दो राहें सफर है मेरा, रास्ता रोका गया तो काफ़िला हो जाऊंगा।।

इसी के साथ मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं। यहां पर जो जय राम ठाकुर जी ने बजट दिया है जिनका नाम है जय, राम, ठाकुर यानि जिनकी 'जय' होगी, 'राम' उनके बीच है और 'ठाकुर' कृष्ण गोपाल जी को कहते हैं; तीनों शक्तियां उनके साथ है। हिमाचल में कहा जाता है कि यहां पर सरकार रिपीट नहीं होती। मैं मानता हूं कि गौशाला के बहाने लोगों का लालच भी होगा, इसके बहाने लोग आगे भी आयेंगे। मगर अच्छे लोग जो गौशाला चलाते होंगे उनको आगे लाकर गौशाला निर्माण करने में अच्छा काम करेंगे तो सरकार भी रिपीट होगी और हम दोबारा यहां पर होंगे। धन्यवाद, जय हिन्द। जय भारत।

15.3.2018/1650/av/hk/2

अध्यक्ष : श्री राकेश पठानिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरा छोटा भाई है जो कि थोड़ा भावुक हो गया और अपने ही दल का है। इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारी पार्टी पिछले तीन साल से खनन माफिया या जो भी माफिया हो उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश में संघर्ष कर रही है। मैंने यहां विधान सभा के अंदर जो भी बातें रखी हैं वह तथ्यों के साथ रखी हैं और आगे भी रखता रहूंगा। मेरे घर में न तो कोई शाम को आता है और न ही किसी को आने दिया जाता है। मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर ऐसी बातें रिकार्ड में आई तो मुझे प्रिविलेज न मूव करना पड़ जाए। जब तक राकेश पठानिया जीवित

है इस खनन की लड़ाई को लड़ता रहेगा। यहां पर जो मर्जी जिस किस्म की बात करता रहे। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से वहां पर माफिया के तहत और मैं आगे बोलना नहीं चाहूंगा कि किस-किसके नाम के आगे किस-किसका जुर्माना कितना-कितना हुआ है। मैं अपनी बात को यहीं तक सीमित रख रहा हूं परंतु केवल ये लाइनें स्पंज की जाए कि 'जो लोग माइनिंग माफिया के बारे में यहां बोलते हैं', ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राकेश जी, उन्होंने किसी का नाम उद्धृत नहीं किया है। (---व्यवधान---) आप बैठिए, आप बैठिए। प्लीज, आप बैठिए।

अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

15.3.2018/1650/av/hk/3

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने जो अपने प्रथम बजट भाषण को यहां पर प्रस्तुत किया मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट भाषण में बहुत से वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी। इस वर्ष का जो बजट है इसमें कोई भी नयापन नहीं है, यह आलोचना वाली बात नहीं है। इसमें 85 प्रतिशत बजट पिछले बजट से, जो पूर्व में हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने कल्याणकारी योजनाएं बनाई थी उन्हीं बिन्दुओं को थोड़ा बदलकर यहां पर प्रस्तुत किया है जैसे कि मुख्य मंत्री आवास योजना;

15.3.2018/1655/TCV/YK-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल ..... जारी

जो पूर्व में वीरभद्र सरकार ने बी0पी0एल0 में हमारे लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं- उनके लिए इजाद की थी। इसमें भी कोई नयापन नहीं है। 'मुख्य मंत्री सड़क योजना' ये भी वीरभद्र सिंह जी ने प्रदेश में शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जो सड़कें हैं, जिसके लिए

अधोसंरचना की जरूरत थी, वह माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू की थी। पिछली बार भी इन्होंने 50 करोड़ रुपये दिये थे और इस वर्ष भी इसमें 50 करोड़ रुपये ही दर्शाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, सड़कें किसी भी प्रगति की भाग्य रेखायें होती हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें बनी है, वह कोई डी0सी0 डिपोजिट से बनी है, कोई मनरेगा के माध्यम से बनी है। लेकिन उनके रखरखाव का कोई भी प्रावधान नहीं है। बजट में टारिंग- मैटलिंग बढ़ाने की बात तो कही, हम आज 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी जो पी0डब्ल्यू0डी0 का Mannual है, उसको बदले जाने की जरूरत है। सड़कों का घनत्व बहुत ज्यादा हो गया है। उनकी मैंटेनेंस के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब देश में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, तो उस समय उन्होंने बड़ी जोर से एक चर्चा की थी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं, उनकी अद्योसंरचना व रखरखाव के लिए विशेष रूप से बजट में प्रावधान करेंगे। उनकी सरकार बने हुए दिल्ली में 4 वर्ष बीत गये हैं और इस बजट में भी उन सड़कों के रखरखाव के लिए पैसों का कोई प्रावधान नहीं है। ये बजट पिछली सरकार की नकल प्रतीत होता है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने 'कन्यादान योजना' के तहत 21,000/- से लेकर 50,000/- रुपये की राशि कन्याओं के विवाह के लिए जारी की थी, आज इस बजट में बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाव की बात तो बड़े जोर से की जाती है, लेकिन सरकार ने कन्या के विवाह के लिए, आज के इस मंहगाई के दौर में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकतर पंचायतों में, सिलाई-कढ़ाई की जो शिक्षायें हैं,उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। अभी प्रथम वर्ष है, जो हमारी मूलभूत सुविधायें हैं, जैसे पानी, बिजली की समस्यायें हैं, स्वास्थ्य संस्थानों की समस्यायें हैं, अच्छा होता कि उसके

15.3.2018/1655/TCV/YK-2

लिए बजट में ज्यादा प्रावधान किया जाता। अगर आपकी सड़कें अच्छी होगी तो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए आम नागरिकों को ज्यादा सुविधायें मिलेंगी। आज पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री

नहीं बैठे हैं। बड़ी अचम्बे वाली बात है, कोई कहता है, यहां पानी वाले मुख्य मंत्री थे, कोई कहता है कि यहां सड़क वाले मुख्य मंत्री थे। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि 15 अप्रैल, 1948 को जब इस प्रदेश का निर्माण हुआ था, उस समय कच्ची-पक्की केवलमात्र दो-अढ़ाई सौ किलोमीटर सड़कें थी। कुछ स्कूल थे, कुछ ईका-दूका कॉलेज थे। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि विपक्ष ने कुछ नहीं किया। पिछले 4 वर्षों में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यदि कोई बहुत बड़ा काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी को कोसने के सिवाय उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि वहां नहीं की है। वही परिपाटी यहां पर भी शुरू हो गई है कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, वह नहीं किया। लेकिन आपने क्या करना है, उसकी कोई दिशा इस बजट में नहीं है। चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो, इसमें आपने बड़ी लुभावनी बातें की है। हम कृषि के क्षेत्र में ये उपदान देंगे, बागवानी के क्षेत्र में ये उपदान देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि

15-03-2018/1700/NS/AG/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल------ जारी।

हमारा युवा कृषि से क्यों विमुख हो रहा है? कभी किसी अधिकारी ने किसी गांव में जा करके यह देखा है कि हमारे कितने युवक ग्रीन हाउस लगा रहे हैं? जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं या जो हमारी नई जेनरेशन है, क्या वह कृषि, बागवानी और होर्टिकल्चर का काम कर रही है? कोई भी अधिकारी यह देखने नहीं जाता है और न ही किसी प्रकार का सेमिनार होता है। सरकार ने भी इतने प्रावधान नहीं किये होते हैं। आज यह देखने वाली बात है। आप युवाओं को रोज़गार और उनके हक देने की बात करते हैं, लेकिन इस बजट में आपका ऐसा कोई लक्ष्य नज़र नहीं आ रहा है कि युवाओं को आपने क्या देना है? पिछली बार जब इस मान्य सदन में बेरोज़गारी भत्ते को ले करके चर्चा हुई थी तो बहुत हल्ला हुआ था। आप लोगों ने बड़े जोरशोर से सदन के अंदर और बाहर कहा था कि आपने अपने मैनिफेस्टो में बेरोज़गारी भत्ते की बात रखी है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी ने युवाओं को बेरोज़गार भत्ता दिया तो आपने सरकार में आते ही उसको बंद कर दिया। अच्छा होता कि आप इस भत्ते को जारी रखते। तब हम समझते कि आपकी सोच युवा सोच है।

अध्यक्षः इस माननीय सदन की बैठक एक घंटा के लिए 6.00 बजे तक बढ़ाई जाती है।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, युवाओं के प्रति सरकार का क्या निर्णय है? वह स्पष्ट होना चाहिए। यहां पर गुड़िया और होशियार हैल्पलाइन की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ईमानदारी और अपनी कार्यक्षमता के लिए पूरे देश में नम्बर वन पुलिस गिनी जाती है। लेकिन हमारे प्रदेश में कुछ घटनायें ऐसी हुई हैं, जिसकी वज़ह से प्रदेश की पुलिस के ऊपर दाग लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश की पुलिस ईमादारी का प्रतीक है। यह पूरे देश के अन्दर सभी को विदित है। लेकिन इसका जो राजनीतिकरण किया गया है, ओच्छी हरकतें की गई हैं, सरकारी कार्यालय और गाड़ियां जलायी गई हैं, उसके ऊपर सरकार ने क्या निर्णय लिया है? उसका देनदार कौन है? सरकारी सम्पत्ति का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? यह चिन्ता का विषय है। सी0बी0आई0 जैसी एजैंसी फेल हो गई और आज तक

15-03-2018/1700/NS/AG/2

कोई तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं तथा बेवज़ह कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह निंदा का पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि हम ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन लागू करेंगे। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय और पंचायती राज मंत्री मौजूद नहीं हैं। आज गांव या ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो कस्बे कुक्करमुत्तों की तरह तैयार हो रहे हैं और स्वच्छता को ले करके स्वच्छता अभियान चलाये जा रहे हैं। लेकिन आप नज़र खोल करके देखें कि एक दिन सभी नेताओं और अधिकारियों द्वारा झाड़ू लगाया जाता है और अगले दिन वहां पर कूड़े के उतने ही ढेर होते हैं। आपके पास सही दिशा ही नहीं है कि आपने उस कचरे को कहां डिस्पोज़ ऑफ करना है। इस बज़ट में आपने लिए कोई नीति नहीं बनाई है कि हम इस ठोस कचरे को कहां ठिकाने लगायेंगे? पंचायतों के पास कोई ज़मीन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव और शहर बसे हैं, उनको कूड़ा फैंकने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे अधिकांश क्षेत्र वनों पर आधारित हैं और वन के अधिकारी कूड़े को वहां पर फैंकने नहीं देते हैं। वे डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए गड्ढा खोदने नहीं देते हैं। मेरा सरकार को सुझाव रहेगा कि इस पर जो पैसा खर्च करना है या आबंटन करना है तो उस पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। इसके लिए प्रावधान होना चाहिए।

15.03.2018/1705/RKS/YK-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी कृपया समाप्त करें।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष जी, अभी तो बोलना शुरू ही किया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था परन्तु अब तो ज्यादा समय हो गया है।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलूंगा और उसके बाद समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष जी, इस बजट में कम्प्यूटर टीचर और आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई उल्लेख नहीं है। कर्मचारियों/पैशन्र्ज के भत्तों में, जैसे राजधानी भत्ता, जनजातीय भत्ता और पुलिस कर्मियों के राशन भत्ते में कोई बढ़ावा नहीं किया गया है।

जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, जिनका संरक्षण पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल में किया, उसके बारे में भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

5 बीघा या इससे कम शामलात भूमि में लोगों ने हजारों की संख्या में मकान बना रखे हैं, पशुशाला बना रखी हैं।उनके रेग्यूलाइजेशन के लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2 घंटे 45 मिनट बड़ी लम्बी-लम्बी बातें और शरो-शायरी करके इस बजट को एक किताब तो बना दिया लेकिन धरातल में जो कार्यान्वयन होना है, वह मुझे नज़र नहीं आता है।

आई.पी.एच. विभाग में हैंडपंप लगाने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन हमारा समूचा प्रदेश आज सूखे की चपेट में है। समय पर वर्षा नहीं हुई है। मुझे यह बताएं कि 20 करोड़ रुपये में आप कितने हैंडपंप लगाएंगे? जिला हमीरपुर, सूखा क्षेत्र, जिला बिलासपुर, सूखा क्षेत्र, जिला ऊना, सूखा क्षेत्र, जिला कांगड़ा के अधिकांश क्षेत्र, सूखे क्षेत्र हैं। आपने पीने के पानी की क्या योजनाएं बनाई हैं? हमारी जितनी भी योजनाएं

हैं, जैसे ही गर्मियां शुरू होंगी, वाटर लैवल नीचे चला जाएगा और आपकी कोई भी स्कीम पानी लिफ्ट नहीं कर पाएगी।

15.03.2018/1705/RKS/YK-1

आप सिंचाई योजना की बात करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 सिंचाई की योजनाएं हैं। लेकिन उनमें न तो कोई फिटर है, न कोई पंप ओप्रेटर है, न ही ये योजनाएं पूर्ण हुई हैं, न ही इनकी मशीनरी की देखरेख के लिए कोई व्यक्ति है और न ही पानी छोड़ने के लिए कोई व्यक्ति है। (...व्यवधान...) यह मेरे चुनाव क्षेत्र की बात है। ये सारी स्कीम्ज पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय धूमल जी के समय में बनी हैं। इन स्कीमों में पानी भी नहीं है। वहां पर किसानों को पानी नहीं मिलता है। करोड़-करोड़ रुपये की स्कीमें जो बना कर रख दी हैं, उनको बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें आलोचना वाली कोई बात नहीं है। आपके निर्वाचन क्षेत्रों के भी यही हाल हैं। हमारा सारा पंपिंग सिस्टम खराब है। बिजली विभाग के पास लाइन मैन नहीं है, ए.एल.एम. नहीं हैं, फिटर नहीं हैं, पंप आप्रेटर नहीं हैं। आप इन योजनाओं को कैसे चलाएंगे? आउटसोर्स में काम करवाना इसका कोई समाधान नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था और हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि पानी की योजनाओं में आउटसोर्स बंद होना चाहिए। यह बहुत बड़ा गोरखधंधा है। इससे भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग 5-5 बार मोटरों को रिवाईंड करवा रहे हैं। पैसा खा रहे हैं और आई.पी.एच. विभाग का बेड़ागर्क कर दिया है।

यहां पर सभी युवा मंत्री बैठे हैं, आदरणीय प्रधान मंत्री जी भी युवा हैं, आप सारी योजनाओं का दौरा करें। आपने कर्मचारियों की भर्ती के बारे में कोई बात नहीं की है। सिर्फ एक लाइन लिख दी कार्यमूलक पद भरे जाएंगे। कहां भरे जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बजट का समर्थन कर पाना मेरे लिए असम्भव है। धन्यवाद। जय हिन्द।

15.03.2018/1705/RKS/YK-1

अध्यक्षः माननीय सदस्या, श्रीमती कमलेश कुमारी जी, अब इस चर्चा में भाग लेगी।

श्रीमती कमलेश कुमारीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार विधान सभा सत्र में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने जो बजट वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

15.03.2018/1710/डी.टी./डी.सी.-1

श्री कमलेश कुमारी... जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सर्वहितैषी बजट प्रस्तुत कर अपने अनुभव और उदारता का परिचय दिया है। पुष्ट संस्कृति से पले-बड़े, संगठनों के संस्कारों से आगे बढ़े, दो बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और संगठन का कुशलतापूर्वक संचालन किया। पांच बार विधायक बनने के बाद हिमाचल के मुख्य मुख्य मन्त्री बने और मुख्य मुन्त्री के रूप में जो आपने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है, यह आपके व्यक्तित्व का परिचय बन गया है। मैं 3-4 दिनों से जो चर्चा चली है उसको सुन रही हूं। गौ पर रोज चर्चा होती है । भागवत कथा में गौ माता की जय तो सब करते हैं। लेकिन गौ सेवा के लिए मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के बजट में गौ सेवा आयोग का गठन किया है। उससे गौ माता की जय बोलना सार्थक हुआ है। अध्यक्ष जी, गुड़िया हैल्प लाइन 1515 और महिला सुरक्षा हेतु शक्ति ऐप का शुभारम्भ किया गया है। काई भी महिला संकट के समय उपरोक्त मोबाइल पर जैसे ही लाल बटन दबाएगी

इसकी सूचना तुरंत पुलिस बल तक पहुंच जाएगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिए हैं उनका मैं इस सदन से धन्यवाद करती हूं। जो गुड़िया कांड हुआ मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। क्योंकि समय बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में , ग्रामीण खेती, बागवानी, आर्थिकी का रूपांतरण जिससे कृषकों की आय दोगुनी हो, यह हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी यही सोच है कि हम 2012 तक हमारे जो कृषक हैं उनकी आय दोगुनी हो। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।जमीन को उर्वरक बनाने के लिए तथा मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान है। जमीन उर्वरक होगी तो लोगों को पौष्टिक भोजन मिलेगा तथा तन मन स्वस्थ होगा।यदि नारी सशक्त होगी तो उसके

15.03.2018/1710/डी.टी./डी.सी.-2

बच्चे सशक्त और संस्कारवान होंगे और देश का भविष्य उज्जवल होगा। तभी आने वाली संताने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल और संस्कारी होगी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल योजना का शुभारम्भ किया और गरीब परिवार की पात्र महिलाओं को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध करवाई। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने भी प्रदेश में हिमाचल गृहणी योजना शुरू की है। मुझे तो यह लगता है कि आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुख्य श्री जय राम ठाकुर जी के विचार मिलते जुलते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी इनहोंने महिलाओं के लिए अच्छी योजना की शुरूआत की है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदैव प्राथमिकता रही है। मैं इस माननीय सदन को याद दिलाना चाहूंगी और अभी मेरी बहन रीता धीमान जी ने भी यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। हम भारतीय जनता पार्टी की सदा के लिए ऋणी रहेंगी।

15.03.2018/1715/SLS-YK-1

श्रीमती कमलेश कुमारी...जारी

और मेरी बहनें पंचायती राज संस्थाओं में 50% की सीमा से आगे बढ़कर 68% सीटें जीतकर इन संस्थाओं में पहुंची हैं।

13वें वित्तायोग में जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को अनुदान आबंटित किया जाता था। मैं स्वयं जिला परिषद की सदस्य रही हूं और पंचायत प्रधान भी रही हूं। अब लोगों के आशीर्वाद से मुझे यहां भी बोलने का मौक़ा मिला है। लोगों ने मुझे सहयोग-समर्थन दिया और यहां तक पहुंचाया। 14वें वित्तायोग द्वारा जिला परिषद और पंचायत समितियों का अनुदान बंद कर दिया गया था। मैं माननीय जय राम ठाकुर जी का इस सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने वर्ष 2018-2019 के लिए बजट में 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके लिए माननीय जय राम ठाकुर जी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी भी की गई है, कर्मचारियों को 4% अंतरिम राहत दी गई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है, आशा वर्कर्ज़ व जल रक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है और वह वर्ग, जो सबसे अधिक ईमानदारी से काम करते हैं जो कि हमारा मज़दूर वर्ग है, उसकी दिहाड़ी में भी वृद्धि की गई है। इसके लिए भी मैं इस सदन के माध्यम से और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी।

इसके साथ-साथ ही अगर मैं महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं के बारे में कहूं तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इन्होंने अनेक योजनाएं चलाई हैं। सभी के बारे में बताने में ज्यादा समय लगेगा। जैसे मदर टैरेसा, मातृ आश्रय संबल योजना आदि। इसमें

सहायता राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। इसी के साथ बहुत सारी और अनेक योजनाएं हैं।

15.03.2018/1715/SLS-YK-2

अब मैं भोरंज विधान सभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। जो मेरा भोरंज विधान सभा क्षेत्र है, मैं तो यह कहना चाहूंगी कि माननीय, सम्माननीय और बड़े ही आदर के योग्य आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी यहां बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जो 68 विधान सभा क्षेत्र हैं, शायद उनमें से भोरंज विधान सभा क्षेत्र को काट दिया गया था। जो हमारा भोरंज विधान सभा क्षेत्र है वह सारा ड्राई क्षेत्र है। वहां पेयजल योजनाओं की कमी है और पीने के पानी की समस्या है। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कुछ गांवों में तो इस समय भी समस्या है। इस समय की तो बात छोड़ें, जैसे हमारा बरसात या सर्दियों का मौसम होता है उसमें भी कुछ गांव हमारे पानी की समस्या से जूझते हैं। जैसे कड़ोता, मणोह, बडैहर और घमरोह गांवों हैं, उनमें पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रही हूं, इसलिए मुझे बोलने का कुछ और समय दिया जाए क्योंकि अब मैं अपने क्षेत्र की बात रखने जा रही हूं। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि मैंने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड लिया। उसमें हमारा जो भोरंज विधान सभा क्षेत्र है, जो ड्राई क्षेत्र है उसके बावजूद भी 5 वर्षों में वहां एक भी हैंड पंप नहीं लगा। जब मैंने विभाग से इसकी पूरी रिपोर्ट ली तो पता चला कि और विधान सभा क्षेत्रों में कइयों में 70 हैंड पंप लगे तो कइयों में 100 लगे लेकिन भोरंज क्षेत्र में एक भी हैंड पंप नहीं लगा।

15/03/2018/1720/RG/HK/1

श्रीमती कमलेश कुमारी-----जारी

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वहां एक बड़ी स्कीम दी जाए। मैं तो यह चाहती हूं कि यदि कोल डैम से कोई स्कीम दी जाए या सिचुई की तरफ से कोई स्कीम बने, तो अच्छा है। इसके

लिए मैं माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करुंगी कि मेरे चुनाव क्षेत्र में इस बारे में विशेष ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे चुनाव क्षेत्र में केवल एक अस्पताल पी.एच.सी., भोरंज है। पिछले वर्षों में उसका दर्जा बढ़ाकर उसको सी.एच.सी. किया गया और उसकी ओ.पी.डी. कम-से-कम 450 पेशेन्ट्स के लगभग है। लेकिन सुविधा के नाम वहां धरातल पर कुछ नहीं है। न तो कोई मशीन है, न ही कोई बिल्डिंग और न ही वहां कोई डॉक्टर है। हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। मेरी इनसे प्रार्थना रहेगी कि जल्दी-से-जल्दी मेरे चुनाव क्षेत्र में अस्पताल में चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाएं। मेरे चुनाव क्षेत्र में ही पिछले पांच वर्षो से चमोह और बिलोखर की पी.एच.सी. में कोई चिकित्सक नहीं है, न वहां बिल्डिंग है और न ही वहां के लिए कोई बजट का प्रावधान है। ---(घण्टी)--इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि तीन जिलों के केन्द्र जाहू में सी.एच.सी. बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि वह तीन जिलों का केन्द्र है। यदि भोरंज आना हो, तो वहां पहले ही चिकित्सक नहीं है और वह भी 15 किलोमीटर पड़ता है। यदि हमीरपुर जाना हो, तो कम-से-कम 35 या 40 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए मेरा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से विनम्र निवेदन रहेगा कि जाहू के लिए सी.एच.सी. दी जाए क्योंकि वहां के लिए इसकी अति आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगी कि जो पिछली बार विधायक प्राथमिकता में सड़कें पड़ी थीं उनका काम भी आज तक नहीं हुआ है। भोरंज में सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि उनमें खड्डे ही खड्डे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले पांच वर्षों में यदि सड़कों की थोड़ी-बहुत मरम्मत भी होती तब भी स्थिति थोड़ी बेहतर होती। लेकिन मुझे आज खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इन सड़कों की मरम्मत के लिए बजट का जल्दी से प्रावधान किया जाए। मैंने इस बारे में एक प्रश्न भी दिया था, परन्तु वह कल लगा नहीं। हमारे यहां चैंथ खड्ड,

15/03/2018/1720/RG/HK/2

सीर खड्ड और कुनाह खड्ड आदि का योजनाबद्ध तरीके से तटीयकरण किया जाए। मैं तो पांच वर्षों से सुन रही हूं कि इसका इतना बजट स्वीकृत हो गया है, लेकिन जो कल उत्तर

आया है उसमें मैंने यह पाया है कि इसकी डी.पी.आर्ज. में कुछ आपत्तियां थीं। मैं माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ---(घण्टी)---मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी आपत्तियां हों, उनको रिमूव करते हुए तटीयकरण का काम जल्दी-से-जल्दी शुरू करवाया जाए। जब यह काम शुरू किया जाए, तो मेरा उसमें एक सुझाव है कि इसमें योजनाबद्ध तरीके से डाई, चैक डैम, साईड में पौधारोपण तथा तालाब आदि बनें ताकि जल संरक्षण का भण्डारण बढ़े और

15/03/2018/1725/MS/HK/1

श्रीमती कमलेश कुमारी जारी-------

खनन माफिया पर भी लगाम लगे। इसी के साथ जो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत किया है, वह आम आदमी का बजट है और मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करती हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

15/03/2018/1725/MS/HK/2

अध्यक्षः माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मेरे छोटे भाई लखनपाल जी ने एक बहुत अच्छी चिन्ता जताई है कि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के अंदर कर्मियों की कमी है। उसमें पम्प ऑप्रेटर, हैल्पर, फिटर, पी0एल0एम0और चौकीदार भी नहीं है। दूसरी इन्होंने यह चिन्ता जताई है कि जितनी भी हमारी उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं उनको हम आउटसोर्स करके ठेकेदारों के हवाले कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात में आपके साथ हूं। क्यों साथ हूं, वह इसलिए क्योंकि जितनी भी योजनाएं ठेकेदारों को दी गईं वे आज ऐसी स्थिति में हैं कि उन योजनाओं के जो पम्प हैं वे बैठ गए हैं। उन योजनाओं की जो मोटर्ज हैं वे भी बैठ गई हैं। अमूमन क्या होता है कि जब बिजली स्टार्ट करते हैं तो बिजली का मीटर चला हुआ है और मोटर आहिस्ता-आहिस्ता घूम रही है, पम्प आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा है और जहां के लिए पानी प्रस्तावित है यानी जितना डिस्चार्ज होना चाहिए वहां उतना पानी नहीं पहुंच रहा है। इस बारे में प्रश्न भी लगा है। मैं उस प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। तो हम उस पर जितनी राशि ठेकेदारों को दे रहे हैं उस राशि से जितने प्रस्तावित स्किल्ड वर्कर्ज

वे वहां पर एग्रीमैंट में प्रस्तुत करते हैं उससे छः गुणा अधिक बेरोजगार उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं तो सदन से चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रश्न इस पक्ष और उस पक्ष का नहीं है बल्कि प्रश्न लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने का है। प्रश्न सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं उनसे उन खेतों को हरा-भरा करने का है और वह तभी संभव हो सकता है अगर हमारे पास मेनपावर हो। भाई लखनपाल जी, अगर यह सब दो महीनों में हुआ है तब तो मैं दोषी हूं। -(व्यवधान)- इसीलिए मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। मैं आपकी बात पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं कि अगर यह सब दो महीनों में हुआ है तब तो मैं दोषी हूं लेकिन यह व्यवस्था पिछले पांच साल में शुरू हुई है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः पिछले से पिछले पांच वर्षों से शुरू हुई है।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अग्निहोत्री जी, आप पिछली बार मंत्री थे। मैं उस

15/03/2018/1725/MS/HK/2

बैंच पर था और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो ठेकेदारी पर स्कीमों को देने की प्रथा है, यह आपके समय में शुरू की गई है। मुझे माफ करें(हाथ जोड़ते हुए)। हां, जो वैकेन्सीज हैं वे पीछे से हैं। भविष्य में हम इस प्रथा को इस प्रदेश के अंदर नहीं चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की प्रौपर्टी है वह इस विभाग के कर्मियों के पास ही रहनी चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे। अनेकों ऐसे पम्प हाऊसिज हैं जहां से मोटरें और पम्प चोरी हो गए हैं। वहां से सर्विस वायर और आगे जो केबल लगती है वह चोरी हो गई। इसके अलावा जितना भी अंदर सामान था वह भी चोरी हो गया। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को बदला जाए। इस व्यवस्था को बदलती बार हमें आपके भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी।

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री मुलख राज जी भाग लेंगे। मुलख राज जी, एक मिनट बैठिए। श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

15.03.2018/1730/जेके/एजी/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण में जो बात कही, उससे मैं सहमत हूं। मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि 14वें वित्तायोग में जो आई0पी0एच0 विभाग का मैंटिनैंस का वर्क है वह पंचायतों को हस्तांतरण कर दिया गया है। उन कामों को करने में पंचायतें सक्षम नहीं है। गांव में कोई पानी की लाइन बिछानी है, हेंडपम्प रिपेयर करना है, कूएं बनाने हैं या कोई नई लाइन बिछनी है, वह भी पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। इसमें हमने पिछले एक वर्ष में काफी कोशिश की कि पंचायतें उसमें सहयोग करें, लेकिन पंचायत के लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं और सारा प्रैशर आई0पी0एच0 के अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि 14वें वित्तायोग के उस पार्ट को खत्म करके आई0पी0एच0 विभाग में ही रहने दिया जाए।

15.03.2018/1730/जेके/एजी/2

अध्यक्षः अगले सदस्य, श्री मुलख राज जी।

मुलख राजः अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी सूझ-बूझ के साथ हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पेश किया है। इसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वृद्धा पैंशन आयु को कम करना, दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाना, गऊ सेवा आयोग का गठन करना और पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को नई दिशा देना आपकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, इसके लिए मैं, मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और प्रदेश के किसानों का बजट में विशेष ध्यान रखा है, उसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। मगर सारी बातें हमारे मित्रों को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इस बजट की चर्चा प्रदेश में, हर वर्ग में हो रही है कि ऐसा जनता में मानना है कि उसमें चाहे दुकानें हों, चाहे गली-

मुहल्ला हो, हर जगह में चर्चा है कि यह बजट जो इस बार पेश किया वह प्रदेश के हित में है, जिसके लिए मुख्य मंत्री, जय राम ठाकुर जी का आम जनता आभार प्रकट करती है। यहां पर समय की तय सीमा रखी है। मैं, अपने विधान सभा क्षेत्र बैजनाथ की बात करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बैजनाथ जो कि एक मुश्त कांग्रेस का कार्यकाल रहा और 15 साल से विधान सभा में सूखा रहा। वहां पर सबसे बड़ी समस्या बैजनाथ विधान सभा की जनता को पीने के पानी की और सिंचाई के लिए कूहलों की, कूहलें बन्द पड़ी हैं, सड़कों की हालत खराब है और पर्यटन की दृष्टि से बैजनाथ विधान सभा को इसमें विशेष ध्यान नहीं रखा गया। आज बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र में ऐसी सम्भावनाएं हैं जिससे पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जा सकता है

15.03.2018/1735/SS-AG/1

श्री मुलख राज क्रमागतः

और बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र को एक विश्व के मानचित्र पर लाया जा सकता है। उतराला-होली मार्ग, जोकि आम चर्चा में रहता है, अगर यह रोड बनता है तो इससे पर्यटन की बहुत सम्भावनाएं हैं जिससे हज़ारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में डाला है। दूसरा, खीर-गंगा घाट जोकि हरिद्वार के बाद भी ऐसा स्थान है जहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग अस्थियां प्रवाह करते हैं। मगर उसके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और एक ततवानी नामक स्थान है वहां पर तत्तेपानी का स्त्रोत है अगर उसको भी संजोया जाता है, वहां पर सड़क मार्ग पहुंचता है और उसमें सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं तो पर्यटन की दृष्टि से भी वह क्षेत्र आगे बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बात रही, मेरा छोटा भंगाल क्षेत्र बड़ी समस्याओं से घिरा रहता है। मगर मैं मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आते ही डॉक्टरों का प्रबंध किया। जिससे सीधा-सीधा मेरी बैजनाथ की जनता को लाभ मिला। चढ़ियार जो हमारा एक क्षेत्र है वहां काफी अरसे से डॉक्टर नहीं हैं। जब वहां से मरीज लाते थे तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती थी। मगर इस विधान सभा के मंच से मैं आदरणीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने वहां पर भी

तुरन्त दो डॉक्टर भेजे हैं, जिससे मेरी चढ़ियार की जनता खुश है। आज मैं बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र में 15 वर्ष के सूखे की बात करता हूं। बहुत बड़ी पीड़ा है। आज जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री बने हैं जब उनका बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र का दौरा हुआ तो इस पीड़ा को उन्होंने समझा और आदरणीय सिंचाई मंत्री महेन्द्र सिंह जी ने भी आते ही करोड़ों रुपये की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, बैजनाथ में एक बस अड्डा है जोकि बहुत तंग है। वहां पर हर समय ट्रेफिक जाम रहती है। तो मैंने मुख्य मंत्री और मंत्री, गोविन्द सिंह जी से आग्रह किया कि यह बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने तुरन्त मेरे कहने पर ही बैजनाथ विधान सभा बस अड्डे के लिए 50 लाख का प्रावधान किया। इसके लिए मैं मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

15.03.2018/1735/SS-AG/2

अध्यक्ष जी, काफी अरसे से बैजनाथ में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था, आज उस जनता को आस है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मेरी बैजनाथ की जनता को लाभ मिलेगा। दूसरा, मेरी नगर पंचायत, पपरोला (बैजनाथ) में ऐसे क्षेत्रों को जोड़ा गया जो

15.03.2018/1740/केएस/डीसी/1

श्री मुलख राज जारी---

ग्रामीण क्षेत्र थे । गरीब जनता वहां पर संघर्ष करती रही कि यह क्षेत्र नगर पंचायत में नहीं आना चाहिए इनमें करथौली, पंतेड़ और दो वार्ड थे, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वार्ड यहां से हटने चाहिए और जो इन्होंने टी.सी.पी. एक्ट वहां लगाया है, उससे भी जनता में काफी रोष है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विधान सभा पटल से कहना चाहता हूं कि वह भी हटना चाहिए और यह जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है मै इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है वह

गरीबों के लिए हैं और इस बजट से ऐसा लगता है कि ये मुख्य मंत्री जी अब लगातार 20 वर्षों तक सत्ता में रहेंगें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

15.03.2018/1740/केएस/डीसी/2

उपाध्यक्षः अब मैं चर्चा में भाग लेने के लिए श्री आशीष बुटेल जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री आशीष बुटेलः उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बजट पर जो चर्चा चल रही है, उसमें हिस्सा लेने के लिए मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उनका यह पहला बजट था और हम लोगों का भी यह पहला बजट सत्र है। मैं समझता हूं कि इस बजट से बहुत सी उम्मीदे पूरे प्रदेश की जनता को थी लेकिन unfortunately this Budget has proved to be against the youth of the State. उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का विरोध करता हूं। आज स्वास्थ्य मंत्री का दिन है। हमारे भारत सरकार में जो हैल्थ मिनिस्टर हैं वे आज राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, उनको बधाई और हमारी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आज जन्मदिन है तो उनको भी बहुत-बहुत बधाई।

उपाध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको पूरे सदन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई।

श्री आशीष बुटेलः उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट पर चर्चा शुरू हुई तो इस चर्चा में सिर्फ चार या पांच बातें सामने आई हैं। सबसे पहली बात जो ट्रेजरी बैंचिज़ ने कही, एक तो जो पिछली सरकार ने लोन लिए उनकी चर्चा हुई। दूसररे,इन्होंने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की जमकर तारीफ की। तीसरे, इन्होंने हमारी पिछली सरकार को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहा गया कि बिना मतलब के संस्थान खोले गए और चौथी इनके दृष्टि पत्र की बात हुई और पांचवी गऊ वंश की इन्होंने बात की।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 18 हजार रुपये के करीब लोन उठाए और जब उससे पिछली भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने सात हजार करोड़ रुपये के लोन उठाए थे। लोन की वृद्धि आपने 246 प्रतिशत की बताई । मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई अच्छे इकॉनोमिस्ट होते हैं तो वे हमेशा यही कहते हैं कि अगर

इन्फ्लेशन का कभी रेट नापना हो तो खाद्य की चीजें, चाहे दाल या चावल है, उनके रेट से नापना चाहिए। खाने की चीजों से इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा अच्छी तरह से पता लगता है ।

15.3.2018/1745/av/hk/1

श्री आशीष बुटेल----- जारी

और उसी को देखते हुए वर्ष 2013 में जब यू0पी0ए0 की सरकार छोड़कर गई थी तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम दाल मिलती थी। सिर्फ दो साल के अन्दर वह दाल लगभग 180 और 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंची। यानि कि उसमें 300 प्रतिशत से भी ऊपर वृद्धि हुई है। इसके अलावा आप गैस सीलैंडर की बात करें तो दखेंगे कि उसको यू0पी0ए0 की सरकार कहां पर छोड़ गई थी और एन0डी0ए0 की सरकार ने उसके दाम कहां पहुंचा दिए। जब यह वृद्धि सौ, दो सौ नहीं बल्कि तीन-तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ी तो क्या आप यह समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ डवलैप्मैंट इन द स्टेट, अगर वह 246 प्रतिशत से बढ़ गई तो उसमें क्या हुआ और वह पैसा जो उन्होंने लोन लिया वह सरकार ने अच्छे प्रोजैक्ट्स पर ही लगाया। अच्छे संस्थान खोलने पर लगाया, हर चीज पर लगाया तथा वह पैसा लोगों की सेवा में लगा इसलिए मैं इनको यह बता देना चाहता था। अभी सरकार को बने दो महीने भी नहीं हुए हैं और आप पहले ही कुछ हजार करोड़ रुपये का लोन ले चुके हैं। यहां पर जो 41,440 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है उसमें कहा है कि प्रति सौ रुपये जो खर्च होंगे उसके ऊपर हमें लगभग 73 रुपये की रिसीट कहीं-न-कहीं से आ जायेगी। बाकी बचे पैसे यानि हर सौ रुपये में से 27 रुपये बोरोईंग में लिए जायेंगे। अगर 41,440 करोड़ रुपये का ऐक्सपैंडिचर है तो उसके हिसाब से इसी वित्त वर्ष में 11,000 करोड़ रुपये का लोन लेना पड़ेगा। इस हिसाब से अगले पांच साल में आप कम-से-कम 70,000 करोड़ रुपये का लोन लेंगे। यहां पर गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद किया जा रहा था, किस बात का धन्यवाद? मैडिकल कालेज नाहन, चम्बा और हमीरपुर यू0पी0ए0 की सरकार ने दिए, अनाउंस उन्होंने किए तो धन्यवाद एन0डी0ए0 को क्यों दें। एक 'उड़ान' स्कीम शुरू की गई जिसके बारे में यह कहा गया कि इस स्कीम के अंदर हमारे यहां के एयरपोर्ट पर सस्ता

टिकट मिलेगा और 2000 रुपये के करीब टिकट मिलने का आश्वासन दिया गया। मैं यह बताना चाहूंगा कि जब से यह स्कीम चली है कुल्लू और शिमला की फ्लाइटें ही रद्द होती रहती है, क्या हम इनका इसके लिए धन्यवाद करें? जो टिकट 2

15.3.2018/1745/av/hk/2

हजार रुपये की मिलनी थी आज वह 18-18, 20-20 हजार रुपये की मिलती है। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की, उन्होंने पूरे भारत वर्ष की जनता को यह बताया कि डीमोनेटाइजेशन करने से फेक कंरसी वापिस आयेगी। टैरेरिस्ट के पास जो पैसा है वह वापिस आयेगा और यह भी कहा कि कालाधन भी वापिस हिन्दुस्तान की सरकार के पास आयेगा। मगर इस प्रोसैस में 120 लोगों की मौत हुई जिसकी आज तक किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। इसके बाद दो महीने के अंदर इसमें 60 चेन्जिज लाई गई जिसका मतलब तो यही हुआ कि यह पोलिसी बिना सोचे-समझे लाई गई थी। उसके बाद जब फेक करंसी की बात आई तो कहने लगे कि फेक करंसी वापिस आयेगी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ .00007 प्रतिशत फेक करंसी थी जिसके लिए आपने इतना बड़ा कदम बिना सोचे-समझे उठा लिया। ब्लैक मनी की बात की जाए तो आर0बी0आई0 ने सबके सामने कहा कि 15.44 लाख करोड़ रुपये की करंसी जो बाहर से वापिस लाई गई थी उसमें 99 प्रतिशत करंसी वापिस आ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक प्रतिशत ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं। क्या भारत सरकार को यह भी नहीं मालूम कि एक प्रतिशत ब्लैक मनी करंसी में है और बाकी सारी गोल्ड और रियल एस्टेट में छिपी हुई है। उसके ऊपर क्या हुआ,क्या वे इतना सीरियस थे कि ब्लैक मनी वापिस लेकर आयेंगे? यहां पर जी0एस0टी0 के ऊपर भी बहुत कुछ कहा गया है। जी0एस0टी0 के बारे में जब इतना कहा जा रहा है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपने इसको भी बिना सोचे-समझे लागू किया है क्योंकि ऐक्साइज ड्यूटी इत्यादि जी0एस0टी0 की वजह से कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज

भी लोग उस पर ऐक्साइज ड्यूटी लगाकर बेच रहे हैं। हरेक प्रोडक्ट को ऐक्साइज ड्यूटी लगाकर बेचा जा रहा है इसलिए महंगाई हो रही है।

15.3.2018/1750/TCV/YK-1

श्री आशीष बुटेल ..... जारी

अभी एक नीरव मोदी, ललित मोदी, माल्या ये आपसे पकड़े नहीं जा रहे हैं। मुझे तो यह लगता है कि कल की हार के बाद, यू0पी0 में जो हमारी एक बहन जी है, उनको भी अंदर न होना पड़े, क्योंकि उन्होंने सरकार का समर्थन नहीं किया है। सर, मैं थोड़ी-सी बातें यूथ के बारे में कहना चाहता हूं। आपने 'मुख्य मंत्री खेल विकास योजना' की बात कही है और इसका श्रेय भी आप लोग लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये श्रेय पिछली सरकार को जाता है। हरेक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 लाख रुपये की लागत से एक-एक ग्राउंड बनना था और ये माननीय वीरभद्र सिंह जी की देन है। इसका श्रेय भी यही (सत्ता पक्ष) लेना चाह रहे हैं। उसके बाद इस बजट में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ का प्रावधान आपने किया। आपने यूथ एण्ड स्पोर्टस के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे थोड़ी-सा संरक्षण चाहूंगा। मैं पहली-पहली बार बोल रहा हूं। Small Area Games को भी इसके अंदर लेना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसके अंदर बहुत बड़े प्ले ग्राउंड बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन यदि हम Small Area Games यहां पर लेकर आते, बजट में आपने इन स्पोर्टस के ऊपर ध्यान दिया होता, जिनको एस0ए0जी0 कहते हैं, तो प्रदेश के युवा इसके लिए आपका धन्यवाद करते। आप 21000 बेरोजगार लोगों को भत्ते की बात करते हैं, वे भी तो हिमाचल के ही लोग हैं, वे कौन-से पंजाब से आये थे। उनको यह भत्ता इसलिए दिया गया, क्योंकि हमारी सरकार ने कहा था कि उनको भत्ता मिलेगा और अगर हमारी सरकार फिर वापिस आती तो वह 21000 की जगह जितने भी बाकी बेरोज़गार बचे थे, उनको भी मिलता। अब आपकी सरकार है, अब आप देकर देखिये। आप दीजिए, आप क्यों उसको बंद कर रहे हैं।

दूसरा, यहां पर Drug Menace के बारे में चर्चा हुई। क्या आप हिमाचल प्रदेश को पंजाब बनाना चाह रहे हैं। आप उसकी तो रोकथाम करेंगे, लेकिन जो बच्चे पहले ही इसकी चपेट में आ चुकें हैं, उनका क्या करेंगे? बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं

15.3.2018/1750/TCV/YK-2

है, कि उनके लिए रिहैब्लिटेशन सैंटर खोले जायें। आपने लिखा जरूर है, लेकिन उस पर कोई बजट का प्रावधान नहीं किया है। इसके अलावा, आपने जब इलैक्शन लड़े, तो उस समय दृष्टि-पत्र में बहुत कुछ लिखा था। लेकिन आज इम्प्लाईमैंट के बारे कोई बात नहीं होती है और हमारे युवाओं को यह कहा जाता है कि वे अपना-अपना बिज़निस खोल लें। लेकिन महोदय मुझे लगता है कि ये उनके साथ धोखा हुआ है। आऊटसोर्स इम्प्लाईज़ के लिए कोई पॉलिसी नहीं हैं। जहां तक डेलीवेज़ वालों की बात है, मुझे याद आता है, कर्नल साहब यहां बैठे है, पिछली बार मैं स्पीकर गैलरी से बजट देख रहा था, उसमें जब 10 रूपये की वृद्धि हुई तो यहां से एक मैंबर (विपक्ष) ने कहा ये वृद्धि तो एक चाय के कप के बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो 15 रुपये की वृद्धि हुई है, वह ड़ेढ कप चाय के बराबर है और ये daily wagers की बहुत बड़ी Insult है। अभी तक आपके ट्रांसपोर्ट में STA और RTA की कमेटियां गठित नहीं हुई है। जिसकी वज़ह से बसों के परमिट रूके हुए हैं। Employment Generation के लिए आप टैक्सी परमिट दे सकते थे, वे रूके हुए हैं। आपकी सरकार को बने हुए 3 महीने हो गये हैं, लेकिन आपकी न STA और न ही RTA फॉर्म हो रही है। जबकि बाकी डिजॉल्व हो चुकी है। उसमें अब क्या दिक्कत है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पालमपुर की बात करूंगा। वहां जो टी-इंडस्ट्री है। टी-इंडस्ट्री के लिए unfortunately there is not even a single penny that has been given for this industry. This was an industry, which used to compete with Darjeeling and Assam. Today, this is an industry where it is difficult to maintain the tea gardens without the support and help of the Government. The Government has

decided not to support the tea industry in the State. This is most unfortunate part of it that there is no mention of tea industry in the Budget.

15-03-2018/1755/NS/HK/1

श्री आशीष बुटेल -----जारी।

टी बोर्ड का रीज़नल ऑफिस यू0पी0ए0 सरकार के श्री आनंद शर्मा जी, उस कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था। आज कुछ भी नहीं दिया गया है। No input subsidy. सबसिडी भी आप छोड़िये। क्या आपने यह भी देखा कि टी इंडस्ट्री के लिए क्या दिक्कतें हैं और उसका सामना कैसे किया जा सकता है? How can a planter's be helped to organize this tea industry? सर, इसके अलावा यहां पर ट्रॉमा सैंटर्ज़ की बात हो रही थी।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाईंड अप करें।

श्री आशीष बुटेलः Sir, I'll just take two minutes more.

उपाध्यक्षः देखिये, अभी छः और सदस्य बोलने वाले हैं। आप एक मिनट में वाईंड अप करें।

श्री आशीष बुटेलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब हैल्थ सैक्टर की बात करूंगा। यहां पर छः ट्रॉमा सैंटर्ज़ की बात कही गई है। लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत से ये छः ट्रॉमा सैंटर्ज़ बनेंगे। हरेक ट्रॉमा सैंटर में एक एम0आर0आई0 की मशीन होती है और इस मशीन का मूल्य कम-से-कम 7 या 8 करोड़ की आयेगी। आपने छः करोड़ की बात करके सबका eyewash कर दिया है। आपने यह कह दिया कि छः करोड़ इन ट्रॉमा सैंटर्ज़ को दिया जायेगा। लेकिन इन सैंटर्ज़ में एम0आर0आई0 मशीन तक नहीं होगी। इन ट्रॉमा सैंटर्ज़ में कोई ऐसी equipment नहीं होगी, जिससे मरीज़ को बचाया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र का ऐसा हाल हो गया है। मैं इस माननीय सदन में ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं सिर्फ एक बात इस बज़ट के बारे में बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं इस बज़ट का

समर्थन नहीं कर सकता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं अपनी बात दो लाइनों में खत्म करूंगा।

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,

जो चीरा तो एक कतरा एक खून न निकला।"

इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

15-03-2018/1755/NS/HK/2

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में श्री जिया लाल भाग लेंगे। आप समय का ध्यान रखें।

श्री जिया लालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार इस सदन में चुन करके आया हूं। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया। मैं भरमौर और पांगी की ज़नता को भी नमन करता हूं, जिन्होंन मुझे चुन करके इस सदन में भेजा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत किये गये बज़ट हेतु दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। मैं इनका धन्यवादी भी हूं। इस बज़ट से प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक नई गति प्राप्त होगी और यह बज़ट प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस बज़ट में प्रदेश के हर कार्यक्षेत्र के पूर्ण विकास का ध्यान रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व कई नेताओं ने इस बज़ट पर चर्चा की है। माननीय मुख्य मंत्री जी, गद्दी समुदाय, भेड़ पालकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखते हुए आपने वर्तमान में ऊन खरीद मूल्य में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी बज़ट में रखा है। इससे प्रदेश के हज़ारों भेड़ पालकों को जोकि अपने पशुधन के साथ हमेशा खुले आसमान के नीचे कठिनाईयों भरा जीवन-यापन करते हैं, को अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए भी मदद मिलेगी। इसके लिए मैं अपने गद्दी समुदाय और भेड़ पालकों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं स्वयं भी भेड़ पालक परिवार से हूं और मेरा प्रदेश के भेड़ पालकों से गहरा संबंध रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं प्रदेश सरकार का ध्यान प्रदेश के भेड़ पालक समुदाय की कुछेक गम्भीर और ज्वलंत समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इन समस्याओं का भेड़ पालकों को आये दिन सामना करना पड़ता है। इसके लिए सदियों से चले आ रहे पुश्तैनी व्यवसाय को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश का भेड़ पालक जब सर्दियों के मौसम में अपने पशुधन के साथ

पहाड़ों से उतर कर प्रदेश के निचले क्षेत्रों में आते हैं तो रास्तें में उन्हें शरारती तत्वों और चोरों द्वारा बहुत ज्यादा तंग किया जाता है।

15.03.2018/1800/RKS/ए.जी.-1

उपाध्यक्षः सायं के 6.00 बज चुके हैं, अभी और भी वक्ता बोलने वाले हैं इसलिए इस माननीय सदन की कार्यवाही 30 मिनट सांय 6:30 बजे और बढ़ाई जाती है।

श्री जिया लालः उपाध्यक्ष जी, भेड़-पालक दिन में यातायात की भीड़ से बचने के लिए अपने पशुधन के साथ रात को सफर करते हैं। चोर और शरारती तत्व उनके पीछे लग जाते हैं और मौका पाकर उनकी भेड़-बकरियों को गाड़ियों में भर कर ले जाते हैं। यदि भेड़ पालक द्वारा उनका विरोध किया जाता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। उन्हें मारने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में भेड़-पालक अपने को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करता है। उसे समय पर कोई सहायता भी उपलब्ध नहीं होती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु आवश्यक एवं उचित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध करता हूं ताकि प्रदेश के भेड़-पालकों को अपनी सुरक्षा के साथ-साथ पशुधन की सुरक्षा भी मिल सके।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान भरमौर विधान सभा चुनाव क्षेत्र की और भी दिलाना चाहता हूं।

जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र के 'एलमी वन बीट' में लगभग 1800 पेड़ काटे गए। इस प्रकरण में निर्दोषों को सजा मिली और जो असली दोषी थे उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। वे स्वतंत्र घूम रहे हैं। इस मामले में कृपया जांच हेतु कड़े आदेश दिए जाएं ताकि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। जिन निर्दोषों को फंसाया गया है उनको सजा मुक्त किया जाए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

15.03.2018/1800/RKS/ए.जी.-2

श्री जगत सिंह नेगीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदन का कोरम पूरा नहीं है। अतः सदन को स्थगित किया जाना चाहिए। सदन में कुल 15-16

सदस्य ही बैठे हैं। कुछ माननीय सदस्य अब आ रहे हैं लेकिन तब भी कोरम पूरा होने वाला नहीं है। तीन सदस्यों के आने से कॉरम पूरा नहीं होगा। They are not serious. This Government is not serious. ये अपने ही लोगों की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो हमारी क्या बात सुनेंगे? अभी भी गिन लीजिए अभी भी कॉरम पूरा नहीं है। (...व्यवधान...) नहीं-नहीं (...व्यवधान...) यह सदन नियमों के हिसाब से चलता है। (...व्यवधान...) फिर कॉरम क्यों रखा गया है। (...व्यवधान...) आप बैठना नहीं चाहते, सुनना नहीं

चाहते(...व्यवधान...) आप हमारी क्या सुनेंगे जो आप अपने विधायकों की बात ही नहीं सुनना चाहते। You are not serious. There is no quorum. (...व्यवधान...)

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय सदस्य, आप अपने बाकी सदस्यों से पूछ लीजिए इस तरह का प्रश्न कभी रेज नहीं किया जाता है। (...व्यवधान...) कभी नहीं रेज करते हैं। This is for the first time that you are raising such issue. यह कभी रेज नहीं हुआ है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी, कृपया आप बैठ जाइए।

संसदीय कार्य मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, जब चर्चा निरंतर होती है तो उसमें this happens. We had been there. ऐसा कभी नहीं हुआ है। (...व्यवधान...) आपने बाकी माननीय सदस्यों से कभी पूछा नहीं है। This is happening only because Shri Jagat Singh Negi is raising this issue otherwise it never happens. ऐसा कभी नहीं हुआ है। (...व्यवधान...) ।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट (...व्यवधान...) आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि (...व्यवधान...) ऐसा पहले भी हुआ है। (...व्यवधान...) यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। (...व्यवधान...) माननीय मुकेश जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

15.03.2018/1800/RKS/ए.जी.-3

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष जी, यह जिम्मेवारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की है कि वे पूरा कोरम रखवाएं। कॉरम पूरा करवाना रुलिंग का जिम्मा है। यह विपक्ष का जिम्मा नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की बात से सहमत हूं। मुख्य रूप से हमारी जिम्मेवारी है कि सदन का कॉरम पूरा रहे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि विपक्ष के सदस्य को सदन में बैठना जरूरी नहीं है। क्योंकि जो सारे-के-सारे सदस्य चुने कर आते हैं, उन सबकी जिम्मेवारी होती है कि जब सदन में चर्चा चलें, तो वे यहां पर बैठें। आमतौर पर परंपराओं के आधार पर लोकतंत्र चलता है, सदन चलता है। पांच वर्ष हम भी विपक्ष में रहे हैं; उससे पहले भी हम सत्तापक्ष में थे; मैं कोई नया आदमी नहीं हूं। आज तक यह इश्यू हम भी रेज कर सकते थे।

15-03-2018/1805/DT/AG/1

संसदीय कार्य मंत्री ..जारी...

और न ही हमने कभी ऐसा किया है। पहली बार ये रेज़ हो रहा है। अगर इसी प्रकार की बात चलती रहेगी तो हम इसका ध्यान रखेंगे और आइंदा से इस प्रकार नहीं होगा। लेकिन पहले कभी ऐसा रेज़ नहीं हुआ है। आपके यहां कोई व्यक्ति बैठता ही नहीं था।

उपाध्यक्षः चलो आइंदा से इसका ख्याल रखें। माननीय जिया लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जिया लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 567 करोड़ रुपये का बज़ट में प्रावधान करके जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए नींव का पत्थर रखा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गद्दी समुदाय की विरोधी रही है। गद्दी जाति का मान-सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज मैं विधान सभा सत्र में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि यहां चार गद्दी नेता जीत कर आये हैं। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से जिस कुर्सी पर माननीय

उपाध्यक्ष महोदय आप बैठे हैं, यहां पंडित तुलसी राम जी भी अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बैठे थे। आदरणीय किशन कपूर जी चार बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आदरणीय बिक्रम जरयाल जी भी गद्दी समुदाय से हैं और वे दूसरी बार विधायक बने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी गद्दी जाति से संबंध रखते हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य जिया लाल जी समय का ध्यान रखें।

श्री जिया लालः उपाध्यक्ष महोदय, केवल जनजातीय क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिये बल्कि भटियात, बैजनाथ, धर्मशाला और चम्बा गद्दी समुदाय के लोगों को टिकट दे करके मान-सम्मान बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी ने बार-बार मात्र एक ही व्यक्ति को टिकट दिया है, जोकि कांग्रेस पार्टी की मजबूरी भी है। क्योंकि ट्राईबल एरिया में एस0टी0 के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को

15-03-2018/1805/DT/AG/2

कांग्रेस वालों ने मंत्री बनाया था, उन्होंने अपने पांच साल नाचने और गाने में ही गंवा दिये। प्रदेश की ज़नता जानती है कि वे मंच पर जाते थे और नाचते थे तथा कई बार गिर भी पड़े हैं। इससे गद्दी जाति शर्मसार हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पांच साल में भरमौर में कई शिलान्यास किये हैं। लेकिन उनमें से कोई काम शुरू नहीं हुआ है। 40-40 पट्टिकायें इक्ट्ठी लगा कर और शिमला से बैठ करके शिलान्यास किये हैं। वहां पर जो विकास कार्य शुरू हुए हैं, उसमें बजट का प्रावधान पूर्व में रही धूमल जी की सरकार के समय में हुआ था और मेरे क्षेत्र में केवल वही कार्य हुए हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी कांग्रेस के युवा नेता कह रहे थे कि हज़ारों स्कूल और कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी भी खोली, अच्छा होता अगर ये स्टॉफ और भवन का प्रबन्ध भी कर जाते। मेरे भरमौर में जो स्कूल खुले हैं, उनमें से कोई पंचायत घर में चल रहा है, कोई प्राईवेट कमरे में चल रहा है। मेरे क्षेत्र छत्तराड़ी में जो आई0टी0आई0 खुली है, वह एक दुकान में चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, घोषणा करना तो आसान है लेकिन उसको पूरा करने के लिए बज़ट में प्रावधान भी करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो चम्बा के रहने वाले हैं। आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने जो बज़ट सदन मे प्रस्तुत किया है, मैं जोरशोर से इसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और घण्टी भी बजाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

15.03.2018/1810/SLS-DC-1

उपाध्यक्ष : अब मैं माननीय सदस्य श्री रविन्द्र कुमार जी को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री रविन्द्र कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 9 मार्च को वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट अनुमान पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह पहला बजट है और मेरा भी विधान सभा में बोलने का यह प्रथम अवसर है। अभी विधान सभा के तौर-तरीके सीखने हैं, इसलिए प्रारंभ में ही यह प्रार्थना है कि यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा करें।

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ है। इस पक्ष में जो हम लोग बैठे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के उस मूल मंत्र, उस मूल विचारधारा, जो कहती है कि 'सबका साथ सबका विकास', हम उस मूल धारा और मूल मंत्र के ध्वजावाहक बनकर यहां आए हैं। बजट के अवलोकन पर यह पाया गया कि आदरणीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत ये बजट इस मूल मंत्र को चरितार्थ करता है। इसके लिए मैं मन की गहराई से माननीय मुख्य मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वकांक्षी प्रावधान किए हैं। बजट में सुशासन, रोज़गार सृजन, प्रभावी कानून-व्यवस्था, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं, अधोसंरचना, सामाजिक सुरक्षा, कमज़ोर वर्ग का उद्धार, शिक्षा, बिजली, सड़क और गुणात्मक पेयजल व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने एक नई योजना 'मुख्य मंत्री लोक भवन' आरंभ करना प्रस्तावित की है जिसमें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 2 वर्षों में 30 लाख रुपये की लागत से एक सामुदायिक भवन पूर्ण किया जाएगा। विधान सभा सदस्य व माननीय सांसद अपनी निधि से इसे और बड़ा करवा सकते हैं। यदि माननीय

15.03.2018/1810/SLS-DC-2

सदस्य अपने क्षेत्र में एक या दो अतिरिक्त सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं तो उनकी निधि से 15 लाख रुपये दिए जाने पर सरकार द्वारा भी 15 लाख रुपया दिया जाएगा। यह बजट में एक बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार हम लोग, जो नए जीत कर आए हैं, इकट्ठा हुए। हम भी अपनी तरफ से मुख्य मंत्री महोदय को अपना यह एक विचार देना चाहते थे कि जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है और जो विधायक निधि है, उसमें बढ़ावा किया जाए। पता नहीं कैसे यह बात हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के कानों तक पहुंची, हमारे बिना उनसे बात किए ही उन्होंने हमारी यह बात सुनी और विधायक निधि को भी बढ़ाया। यदि यह मान लिया जाए कि सामुदायिक भवन बनाने के लिए जो 30 लाख रुपये की उन्होंने घोषणा की है, बजट में जो प्रावधान किया है, उसको मिलाकर लगभग डेढ़ करोड़ रुपया या 1.55 करोड़ रुपया इसमें एक विधायक को मिलेगा। साथ ही 7 लाख रुपये की डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी हमें मिलेगी।

महोदय, सरकार ने बजट में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 3 वित्तीय वर्षों में 17881 हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग 338 करोड़ रुपये की लागत से 111 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए एक नई इकाई मंजूर की है।

15/03/2018/1815/RG/DC/1
श्री रविन्द्र कुमार-----जारी

इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। प्रस्तावित बजट में 'मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना' को भी विशेष तरजीह दी गई है। इसमें तीन या उससे अधिक किसानों द्वारा सोलर

बाड़ लगवाने पर सरकार 85% अनुदान प्रदान करेगी और इसके लिए सरकार ने बजट में 35 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। यह योजना निश्चित रूप में जंगली जानवरों की समस्या से त्रस्त किसानों एवं बागवानों के लिए मददगार साबित होगी। मुझे आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह बात कहनी है कि यदि यह सोलर फैन्सिंग के लिए ही है, तो इसको कांटेदार तार के लिए भी इस राशि में 85% एवं 15% का जो प्रावधान किया गया है, उसको बढ़ाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोज़गार बढ़ाने हेतु पर्यटकों को अनुछुए क्षेत्रों में भेजने की योजना पर विशेष बल देने के लिए 'नई राहें, नई मंजिलें', योजना आरम्भ करना प्रस्तावित किया है। इससे इन क्षेत्रों में युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही। साथ ही पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं की संरचना का भी विकास होगा। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में भी दो क्षेत्र गांव अंद्रेटा और मॉ आशापुरी का मंदिर है। ये दो ऐसे स्थान हैं जहां इस योजना का लाभ आने वाले समय में हमें मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी क्षेत्र की सड़कें उस क्षेत्र के विकास को प्रदर्शित करने के लिए एक आईने के रूप में कार्य करती हैं। इनकी गुणवत्ता बनाए रखना एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। इस सदन में बार-बार सड़कों के काम की गुणवत्ता का प्रश्न उठाया जाता है। चाहे वह विपक्ष या सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया जाता रहा हो। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 'तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली' का आरम्भ करने की जो योजना बनाई गई है। मैं इस योजना के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1500 नए बस परमिट जारी करने का भी प्रस्ताव किया है। जिससे न केवल स्वरोजगार बढ़ेगा बल्कि परिवहन सुविधा में भी इज़ाफा होगा। मैं भी इस तरफ देखना चाहूंगा। हालांकि बैंच ऊपर लगभग खाली हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना' आरम्भ की है। आपातकालीन चिकित्सा राशि को 50,000/-रुपये से बढ़ाकर 2,50,000/-

15/03/2018/1815/RG/DC/2

रुपये कर दिया गया है और इसके लिए आय सीमा को हटा दिया गया है। मैं अपनी ओर से आदरणीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बधाई एवं धन्यवाद देना चाहूंगा।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ---(घण्टी)---मैं भी नया-नया हूं और सबको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इसलिए मेरा भी आपसे यह अनुरोध है कि मेरे खाते में भी ग्रेस मार्क्स दिए जाएं।

उपाध्यक्ष : ठीक है, कोई बात नहीं आप 11 मिनट तक आराम से समाप्त कर लें।

श्री रविन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक-दो बातें आपसे जरूर करनी हैं जिसके लिए मुझे आपसे दो मिनट का अतिरिक्त समय चाहिए। मैं पिछले चार दिनों से यह चर्चा सुन रहा था और मन में थोड़ा सा आक्रोश पैदा होना शुरू हुआ था। क्योंकि जब हम वहां से कोई बात सुनते थे, तो हमेशा कुछ-न-कुछ बुराई ही सुनने को मिलती थी। आज के दो घटनाक्रम ऐसे घटे। हालांकि वे अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य जी ने जब अपनी बात रखी, तो बड़ी शालीनता से उन्होंने अपनी बात रखी। जहां विरोध करना था, हालांकि विरोध की कोई बात नहीं थी

15/03/2018/1820/MS/HK/1

श्री रविन्द्र कुमार जारी-------

तब भी शब्दों का चयन बहुत सुन्दर था और जहां उनको अच्छा लगा, उन्होंने बधाई देने में भी कोई संकोच नहीं किया। दूसरा घटनाक्रम उपाध्यक्ष जी आप ही के बारे में है। आज आपने भी चर्चा में भाग लिया। आप आजकल सामने की सीट पर बैठ रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि कहीं आप पर भी सोहबत का असर न हो गया हो और आप भी इस बजट की बखियां उधेड़ने में ही न लग जाएं। लेकिन जिन शब्दों और समयावधि के साथ आपने चर्चा में भाग लिया, उसको देख-सुनकर मैं आज से आपका कायल हो गया हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, लिखने का शौक तो था लेकिन यहां पर जो शेरो-शायरी सुनने को मिली, उसमें एक शेर पर मुझे अपनी बात कहनी है और वह शेर इस बजट बुक में अपने आप समेकित है। पहले शेर में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने छालों का जिक्र किया है। पता नहीं

विपक्ष में इस बात को किस तरह से लिया गया लेकिन जितना मैंने मुख्य मंत्री जी को जानना शुरू किया है, संभवतः उन्होंने इन छालों का जिक्र इसलिए किया है कि जब वक्त ने किसी को तराशना होता है तो वह तरह-तरह के इम्तिहान लेता है। उन इम्तिहानों को पार करते हुए जब वे इस कुर्सी पर आज विराजमान हैं तो संभवतः छालों का जिक्र उन्होंने अपनी राजनीतिक जिन्दगी की जो यात्रा है उसको मध्य-नज़र रखते हुए किया होगा। उपाध्यक्ष जी, इस प्रदेश को एक मुख्य मंत्री ऐसा मिला है जिन्होंने भूख की तपिश आदमी को कितना व्याकुल करती है उसका अहसास किया होगा। एक मनरेगा के मजदूर, एक जल-वाहक जो 1500-1800 रुपये की तनख्वाह महीने में कमाता है तो 100 रुपये के पुरूषार्थ में कितनी पावनता है उसको कभी उन्होंने कमाया होगा, तब इन गरीब मजदूरों का, इस गरीब वर्ग का उनके मन में ध्यान आया होगा। मुझे कुछ शब्द जो हल्की सी चुभन दे गए वे ये थे कि उस तरफ जो मेरे भाई बैठे हैं, पता नहीं इससे पूर्व क्या होता रहा क्या नहीं, क्योंकि मैं पहली बार यहां चुनकर आया हूं तो किसी को प्रोड्यूसर बोला गया और किसी को डायरेक्टर बोला गया। यहां तक कि मैं नाम नहीं लूंगा एक माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए "संकीर्ण सोच", मैं शब्दों को कोट कर रहा हूं ,ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया। मैं उस

15/03/2018/1820/MS/HK/2

बात के लिए थोड़ा आहत था। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ जो लोग बेठे हैं वे भी बहुत मेहनत और मशक्त करके यहां पर पहुंचे हैं। चलो, मान भी लिया जाए कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर समय के साथ-साथ बदलते चले जाएंगे लेकिन यकीन के साथ इस सदन में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विकास की गाथा का जो लेखक है, स्क्रिप्ट राइटर है वह आने वाले 15-20 सालों तक नहीं बदलेगा और वे हमारे मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर जी होंगे। उपाध्यक्ष जी, आप इशारा कर रहे हैं कि काफी हो गया। मैं पुनः मुख्य मंत्री महोदय को इस शानदार बजट को पेश करने के लिए बधाई देता हूं और बजट के समर्थन में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। जय हिमाचल।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, पहले सदन का कोरम पूरा कर लीजिए।

15.03.2018/1825/जेके/एचके/1

उपाध्यक्षः माननीय अग्निहोत्री जी, माननीय सदन का अर्थ है पूरा सदन। अब चर्चा के लिए श्री प्रकाश राणा जी को आमंत्रित करते हैं।

श्री प्रकाश राणाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर जो चर्चा चल रही है, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैंने इसको दो-तीन बार पढ़ा और मैं इसे राज्य के नव-निर्माण वाला बजट मानता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर वर्ग को देख कर इस बजट को बनाया है। मुझे नहीं लगता कि कोई वर्ग इसमें छूटा हो। मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

दूसरे, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार बिना भेद-भाव के काम करेगी। सबका साथ, सबका विकास। हम भी चाहते हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर काम करें ताकि इस राज्य का विकास हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोगिन्द्रनगर चुनाव क्षेत्र से जीतकर आया हूं और पहली बार इस विधान सभा में आया हूं। मैं अपने क्षेत्र की पूरी जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विधान सभा में भेजा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस वक्त जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं वहां पर न कोई पॉलिटैक्निकल इंन्स्टिट्यूट हैं, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, न कोई मैडिकल कॉलेज है, न कोई बस डिपो है, न कोई आई0पी0एच0 का डिविज़न है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हॉस्पिटल है तो वहां पर डॉक्टर नहीं है। तीन-तीन, चार-चार साल से डॉक्टर ही नहीं है, जबकि चार डॉक्टर होने चाहिए। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी रिक्वैस्ट की है और ये बन्दोबस्त कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। अगर स्कूल हैं तो वहां

पर टीचर्ज़ नहीं है। ऐसा नहीं है इस क्षेत्र से मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आज तक उसमें कुछ क्यों नहीं हुआ, जो कि बड़े दुख की बात है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी सदस्य यहां विधान सभा में चुन कर आए हैं।

15.03.2018/1825/जेके/एचके/2

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट के लिए बैठ जाएं, क्योंकि अभी 6.30 हुए हैं और अभी दो सदस्यों ने बोलना है इसलिए **इस माननीय सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए सांय 7 बजे तक बढ़ाया जाता है।**

श्री प्रकाश राणाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी अपने-अपने क्षेत्रों से चुन कर आए हैं और चुनाव जीतने के लिए हम लोगों ने रात-दिन मेहनत की है

15.03.2018/1830/SS-HK/1

श्री प्रकाश राणा क्रमागतः

और अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास हासिल किया। अब हम सब का एक ही मकसद है, एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है कि हम सब अपने क्षेत्रों का विकास चाहते हैं। अपने लोगों को रोजगार चाहते हैं। अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। हॉस्पिटल फैसिलिटी मिले। फिल्ट्रेशन वाटर मिले। अच्छे रोड मिलें। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सब तो तब होगा जब हम सब सदस्य मिल-जुलकर चलेंगे। अगर हम लोग इसी तरह ही एक-दूसरे पर दोष डालते रहेंगे तो प्रदेश और कर्जे में आ जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सब इस सदन के अंदर चल रहा है मैं काफी दिनों से देख रहा हूं। धर्मशाला में भी देखा, यहां पर भी देख रहा हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष का आपस में तालमेल न होना। सब कुछ पुराने सिस्टम से ही चल रहा है। हिमाचल ने काफी तरक्की की, ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं की लेकिन मुझे नहीं लगता कि सदन में कुछ बदलाव आया हो। मुझे लगता है कि हम उसी तरह चल रहे हैं जैसे 30-40 साल पहले चल रहे थे। सब कुछ बदला है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदला

लेकिन यह सिस्टम थोड़ा वही है। मेरा यह मानना है कि जब एक बार चुनाव हो गए, पांच साल की सरकार आ गई --(व्यवधान)--

उपाध्यक्षः कृपया बीच में न बोलें। राणा जी, आप बोलते रहें। राणा जी, पहली बार बोल रहे हैं सदस्यों से निवेदन है कि इनको बीच में न टोकें।

श्री प्रकाण राणाः मुझे थोड़ा बोलने का मौका दें। मैं यह चाहता हूं कि एक बार चुनाव तो खत्म हो गए और सब को पता है कि पांच साल की सरकार भी आ गई तो कम-से-कम हम चार साल मिल-जुलकर चलें ताकि हिमाचल का विकास हो। पांचवें साल हम फिर राजनीति करेंगे। स्वतंत्र देश है, अपनी-अपनी मर्जी है। छः महीने का टाइम ले लो, क्या आप नहीं चाहते कि यहां पर विकास हो? अगर हम लोग यह दृढ़ निश्चय कर लें कि हम मिल-जुलकर कुछ करेंगे तो हम हिमाचल को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्यों से निवेदन है कि ये पहली बार बोल रहे हैं, इन्हें बोलने दीजिए।

15.03.2018/1830/SS-HK/2

श्री प्रकाश राणाः हम इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते कि पीछे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो भी हुआ अच्छा हुआ। हिमाचल ने तरक्की की है, ऐसा नहीं है कि इसने तरीके नहीं की। लेकिन मुझे सदन की तरक्की वहीं-की-वहीं लग रही है। नैट का जमाना है। कम-से-कम चार साल मिल-जुलकर काम करें और साढ़े चार साल या पांचवें साल राजनीति करेंगे। अपनी मर्जी है जिसको जो करना है। क्या आप नहीं चाहते कि यहां का विकास हो? आज हमारा राज्य 46000 करोड़ के कर्जे पर है और 3500 करोड़ हम सिर्फ ब्याज भर रहे हैं। यह बहुत बड़ी राशि है, यह कोई कम राशि नहीं है। इससे हम तीन लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर 10 हजार की औसत से चलें, अगर एक व्यक्ति को 10 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं तो इस पैसे से हम तीन लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि इसको थोड़ा समझने की बात है। जब एक बार सरकार बन गई, होना कुछ नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ों पर डिस्कशन करना, वाक आउट कर देना, अरे विधान सभा एक ऐसा मंदिर है जिससे बड़ा मंदिर हिमाचल में कोई नहीं है। हमारे जितने लोग हैं जिन्होंने हमको चुनकर भेजा है उन्होंने हमारे पर बहुत उम्मीदें लगाई हैं। विधान सभा चल रही है पता नहीं हमारे लिए क्या-क्या लायेंगे, यहां पता चलता है कि

खाली हाथ जा रहे हैं। यहां तो झगड़ों में ज्यादा टाइम गया, सीखने को कम मिला। कम-से-कम हम इसमें कुछ बदलाव लाएं। जब एक बार सरकार बन गई तो क्यों नहीं हम मिल-जुलकर चलें ।

15.03.2018/1835/केएस/एजी/1

श्री प्रकाश राणा जारी----

एक साथ चल कर तो देखो। चार साल मिलजुल कर तो चलो। मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है कि मैं चाहता हूं कि हमारा यह प्रदेश ऋण मुक्त और नशा मुक्त बने लेकिन यह तब होगा जब हम सभी साथ चलेंगें। जब इलैक्शन का समय आएगा, तब इलैक्शन लड़ेंगें, इसमें क्या बात है? आप लोग बोलते हैं कि यहां पर बेरोजगारी की समस्या है। हिमाचल एक ऐसा राज्य है, मैंने भी दुनिया देखी है और मैं भी एक बिजनैस मैन हूं लेकिन जो नैचुरल ब्यूटी यहां पर है, वह कहीं पर भी नहीं है। यहां पर हर तरह का वैदर है और हम तो बड़े खुशनसीब है कि हमारा जन्म इस राज्य में हुआ है। यहां पर बहुत शांति है, बहुत कुछ है, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में है। सिर्फ एक साथ चलने की बात है। एक साथ चलकर हम यहां के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा, 41 हजार करोड़ रुपये बहुत होते हैं लेकिन अगर हम तरीके से चलें अपने हर क्षेत्र में अगर इसको सही यूज़ करें। इसका 25 प्रतिशत हिस्सा मैन पावर में यूज़ होता है। आज हमारे यहां पी.डब्ल्यू.डी. के कितने काम चले हैं, आई.पी.एच. के कितने काम चले हैं? स्कूल की बिल्डिंग्ज़ बन रही है, कॉलेज के कितने भवन बनरहे हैं परन्तु समस्या यह है कि यहां पर ठेकेदारों ने सारा काम खराब किया हुआ है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंड अप प्लीज़। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि राणा जी को अपनी बात बोलने दें। ये पहली बार बोल रहे हैं।

श्री प्रकाश राणाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन 25 परसेंट से क्यों न हम अपने लोगों को रोज़गार दें? हमारा सिस्टम खराब है और इसको सुधारने की जरूरत

है। अगर हम सभी अपने-अपने क्षेत्र के सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी लें, अगर हम सोचेंगें कि मंत्री जानें या मुख्य मंत्री जाने तो कैसे होगा? सभी को अपने-अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि चुन कर आ गए , डिपैंड है कि हर काम मंत्री जी करेंगें तो वे तभी करेंगें अगर हम लोग भी कोशिश करें। हमारा फर्ज है कि हम भी सोचें कि अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे

15.03.2018/1835/केएस/एजी/2

रोज़गार देना है। मैं कहता हूं कि अगर 25 प्रतिशत भी बजट का पकड़े तो हम दस लाख लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। आज क्या हो रहा है कि आप ठेकेदार को काम दे रहे हैं और काम कोई भी सही नहीं हो रहा है। जो रोड़ बनता है वह तीसरे महीने ही उखड़ जाता है तो कहां काम सही हो रहा है? बेरोज़गार भत्ता जो हमने चालू किया उससे अच्छा तो यह होता कि हम टैक्निकल ट्रेनिंग सैंटर्ज़ खोलते। आज कितने यू.पी. और बिहार के लोग हमारे यहां काम कर रहे हैं। आज हम घर बनाते हैं, कोई मिस्त्री नहीं है, कोई प्लम्बर नहीं है, टायल फिक्सर नहीं है, इलैक्ट्रिशियन नहीं है। अगर हम ऐसे ट्रेनिंग स्कूल खोलें और अपने लोगों को छः महीने की ट्रेनिंग देने के बाद काम दें तो क्यों काम नहीं होगा? 25 परसेंट से हम 10 लाख लोगों को रोज़गार दे सकते हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अब वाइंड अप कीजिए। आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं ये हम लिख कर ले लेंगें। कृपया अब वाइंड अप करें।

श्री प्रकाश राणाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम कम से कम चार साल मिलजुल कर चलकर तो देखें। यह बहुत बड़ा बजट है। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय की कमी है।

उपाध्यक्षः बजट पर आप क्या कर रहे हैं?

श्री प्रकाश राणाः उपाध्यक्ष महोदय, बजट का तो मैंने पहले ही समर्थन किया कि बजट बहुत अच्छा है। मैंने इसको दो-तीन बार पढ़ा इसमें कोई कमी नहीं है।

15.3.2018/1840/av/hk/1

श्री प्रकाश राणा----- जारी

मुझे बड़ा दुःख हुआ कि बन्दरों की जो डिसक्शन चली है यह कितने सालों से चली हुई है। मेरे ख्याल में यह कम-से-कम 15 सालों से चली हुई है। (---व्यवधान---) मुझे दो मिनट बंदरों के बारे में तो बोलने दीजिए जिन्होंने इतनी तबाही की हुई है। (---व्यवधान---) मैं इस पर उपाय बता रहा हूं। आप मेरा उपाय तो सुन लीजिए।(---व्यवधान---)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बंदरों पर और कभी बोल लेना। अभी आप बैठिए। (---व्यवधान---) आप बजट के बारे में बोलिए। मैं माननीय सदस्य श्री अरुण जी को चर्चा में भाग लेने के लिए बुला रहा हूं।

श्री प्रकाश राणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बंदरों के बारे में उपाय बता रहा हूं। यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा कि बंदरों ने कई वर्षों से तबाही मचाई हुई है। (---व्यवधान---)

उपाध्यक्ष : आप बोलने दीजिए (सत्ता पक्ष से कुछ सदस्यों द्वारा बोलने के लिए हामी भरने पर कहा।) लेकिन इस हाउस का समय बढ़ेगा। आप बोलो तो मैं हाउस का समय एक घंटा बढ़ा सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहां पर बैठना पड़ेगा।

श्री प्रकाश राणा : कहा जा रहा है कि बंदर हर साल करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान कर रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि यदि आपके पास नहीं है तो मैं कम्पनी खड़ी करता हूं। इसके लिए सौ करोड़ रुपये का बजट है और इतने बजट से बंदर सौ दिन में खत्म हो जायेंगे। (---व्यवधान---) बताओ, कैसे नहीं बंदर खत्म होंगे लेकिन यह काम करने से होगा। आप हमें बजट दो, हम कम्पनी खड़ी करते हैं। बंदर कैसे खत्म नहीं होते। (---व्यवधान---) हम इनको कहीं भी भेजें, इनको खत्म करें। (---व्यवधान---)

15.3.2018/1840/av/hk/2

उपाध्यक्ष : राणा जी, आप प्लीज बैठ जाइए। अभी दो और सदस्यों ने बोलना है। इसके लिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप इनका आइडिया लिखित रूप में ले लें।

श्री प्रकाशा राणा : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि आप इसके लिए टैंडर कीजिए। (---व्यवधान---)

उपाध्यक्ष : आप मुख्य मंत्री या माननीय मंत्री जी को इस बारे में अपने आइडिया लिखकर दें।

श्री प्रकाशा राणा : उपाध्यक्ष जी, मेरा मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से यह निवेदन है कि हम बंदरों की वजह से बहुत परेशान है। हमारे उधर भी (---व्यवधान---) हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे तो वहां पर हमसे लोग पूछेंगे कि बंदरों के बारे में क्या निर्णय हुआ तो हम क्या बोलेंगे?

अंत में, मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । मुझे यहां पर पहली बार बोलने का मौका मिला है इसलिए मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना। मैं इस बजट का तहदिल से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

15.3.2018/1840/av/hk/3

उपाध्यक्ष : अब मैं चर्चा में भाग लेने के लिए श्री अरुण कुमार को आमंत्रित करता हूं।

श्री अरुण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने जो यह अति-स्वावलम्बी बजट यहां पर प्रस्तुत किया है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं।

साथ में, मैं माननीय मुकेश अग्निहोत्री, राजेन्द्र राणा और पवन काजल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि ये लोग मुझे सुनने का बहुत शौक रखते हैं। मेरे विधान सभा चुनाव

जीतने की खुशी जितनी सत्ता पक्ष को है उतनी ही खुशी विपक्ष वालों को भी थी। आज अगर मैं यहां पर पहुंचा हूं तो उसमें माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का भी बहुत योगदान रहा है। पिछला चुनाव मैंने आजाद प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और मात्र 1150 वोटों से हारा था। मैं यहां विधान सभा में पहली बार पहुंचा हूं और मेरी तरह यहां पर 22-23 के करीब नये विधायक चुनकर आये हैं। आपने मुझे यहां पर बोलने के लिए समय दिया लेकिन यहां पर मुझे बहुत जूनियर समझा गया। आप एक बात सोचो कि जिसको मैंने पराजित किया है वह पिछली बार यहां चौथे नम्बर पर बैठे थे और हर बार पहली कुर्सी के लिए छीना-झपटी करते रहे। उस हिसाब से अगर मुझे बोलने के लिए पहले समय देते तो प्रैस गैलरी में भी ज्यादा लोग सुनते और पक्ष व विपक्ष में काफी सारे लोग सुनते। फिर भी, (---व्यवधान---) आदरणीय मुकेश जी, आपको मेरे बड़े भाई श्री जवाहर जी ने कहा कि अगर ये नहीं जीतते तो तब शायद आप उस कुर्सी पर न होते। इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं क्योंकि अगर मैं भी नहीं होता तो भी आपके लिए मुश्किलें पैदा होती। माननीय अग्निहोत्री हमारे विपक्ष के नेता है और मेरे लिए बड़े सम्माननीय है। ये मेरे अपोनैंट के साथ वहां अकसर आया करते थे। मैं उस समय से इनका बड़ा मान-सम्मान करता हूं। तब ये पत्रकार होते थे और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है।

15.3.2018/1845/TCV/YK-1

श्री अरुण कुमार..... जारी

डॉयरेक्टर, प्रोडयूसर के बारे में यहां पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन माननीय विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, यह बात सही है कि डायरेक्टर और प्रोडयूसर आपके समय में भी थे और अब भी हैं। परन्तु पुरानी फिल्मों के जो देव आनन्द जी थे, उनकी जगह इस बार नये अक्षय कुमार आ गये हैं। आपकी पिछली सरकार में कुर्सी के लिए छिन्ना-झपटी बहुत चलती रही, इसलिए अधिकारी भी परेशान ही रहे। इस बार प्रोडयूसर और डॉयरेक्टर नई फिल्म में, नये हीरो के साथ काम कर रहे हैं। मुझे तो पिछली बार कहा गया था कि इस बार गलती से इसको वोट पड़ गये, अगली बार देखेंगे, जमानत भी जब्त हो

जाएगी। मैं श्री विपिन परमार जी का बहुत धन्यवादी हूं। यही मुझे अंगुली पकड़ कर ठीक रास्ते पर ले गये और इस मुकाम पर पहुंचाया तथा मुझे एक अच्छा रास्ता मिला। मैं उस पार्टी का सम्मान करता हूं और सभी शीर्ष नेताओं का बहुत-बहुत धन्यवादी हूं, जिन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं आज इनकी ही बदौलत यहां हूं। बात यूं थीः

गर समुद्र ने ठान ली थी, ज़मीं बहा ले जाने की,
तो जिद्द हमें भी थी, वहीं आशियां बनाने की।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बजट चर्चा में भाग लेते हुए, मुख्य मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट में कुछ नया नहीं कह कर विरोध के लिए विरोध किया है। यह स्वाभाविक भी है, विरोध करना आपकी ड्यूटी बनती है, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी समझते कि जब माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने इस कुर्सी को संभाला तो खज़ाना खाली था। उसके बावजूद भी इतना बड़ा बजट पेश करना और उस बजट का एक-एक रुपया प्रस्तावित करना, हिमाचल प्रदेश को बहुत ऊंचाईयों तक ले जायेगा। यह उनकी नीयत और नीयती है। 84 पेज़ों का जो यह बज़ट है, इसमें सभी माननीय सदस्यों ने विस्तारपूर्वक चर्चा कर ली है। अब यह कहना कि हमारी सरकार के समय पिछली बार लॉ एण्ड आर्डर मैंटेन रहा। हमारी जो सरकार आज यहां पर बैठी है, इन्होंने 4 बिन्दुओं के ऊपर चुनाव लड़ा है- खन्न माफिया, भू- माफिया,

15.3.2018/1845/TCV/YK-2

नशा माफिया और भ्रष्टाचार। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सत्ता को संभाला, उसके बाद एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। ---(व्यवधान)--- वह करोड़ों रुपये का हिसाब आपसे लेना है, श्री पवन जी थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं, आपकी सरकार के समय में मेरे नगरोटा विधान सभा क्षेत्र के अंदर नशे के कई कारोबारी पकड़े गये। 75 व्यक्तियों के खिलाफ़ नशे के केस रजिस्टर्ड हुए और जो लोग पूर्व मंत्री के इर्द-गिर्द रहने वाले थे, उन लोगों के ऊपर केस दर्ज़ हुए। इसी के बदले में, श्री काजल जी आप वहां से बोल रहे हैं, आपने भी गांधी जी को

नहीं बदले के लिए एक हस्ताक्षर युक्त चिट्ठी मुख्य मंत्री जी को भेजी थी। उसके बावजूद संजीव गांधी ने उन लोगों को पकड़ा, वहां पर डॉ0 कॉर्लो को पकड़ा, जिसको 5 दुकानें पूर्व मंत्री ने एच0आर0टी0सी0 की दी थी, जहां पर नशे का कारोबार होता था। उनके जन्मदिन के दिन उनकी गाड़ी में 35 हजार कैप्सूल पकड़े गये और एक राजेश कुमार नाम का लड़का भी पकड़ा गया।

15-03-2018/1850/NS/HK/1

श्री अरूण कुमार------जारी।

पिछली सरकार के समय में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह बात सही है कि मेरे मायके भी आप हैं और मैं वहीं से यहां आया हूं। हम माननीय वीरभद्र सिंह जी के धन्यवादी हैं कि हम 8-9 व्यक्ति इनके द्वारा ही भेजे गये हैं। (घण्टी) मैं यहां पर किसी का नाम ले करके नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन आपके (विपक्ष) समय में कितना भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूं, जिन व्यक्तियों के पास एक समय में टेलीफोन का बिल देने के पैसे नहीं होते थे, जिन व्यक्तियों के पास बैंको का कर्ज़ चुकाने के पैसे नहीं होते थे, वे पिछले बीस वर्षों में सैंकड़ो-करोड़ों के मालिक बन गये हैं। हज़ारों-करोड़ों रुपये की बेनामी सम्पत्तियां, बड़े-बड़े आलीशान होटल और अस्पताल खड़े कर दिये गये हैं। हमारी पार्टी ने एक चार्ज़शीट जो गर्वनर साहब को सौंपी है, उसमें इन सभी बातों का ज़िक्र किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे इस बज़ट सैशन का समापन होता है, उसके बाद आप इस तरफ जाइये और राज्यपाल महोदय को जो चार्जशीट सौंपी थी, उस पर इन्कवायरी करवाईये। (***) यह तो इन्कवायरी ही बतायेगी, मैं किसी के बारे में क्या बोल सकता हूं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय के ऊपर न केवल हिमाचल प्रदेश की ज़नता का आर्शीवाद है बल्कि दैवीय शक्तियों का भी आर्शीवाद है। आज जिन परिस्थितयों से गुज़र कर मुख्य मंत्री जी इस कुर्सी तक पहुंचे हैं, यह इन पर उस मां की बहुत बड़ी कृपा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार विधायक बना, लेकिन मेरा 30 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। मैं विधायकों और मन्त्रियों के साथ रहा हूं। राजा वीरभद्र सिंह जी के बहुत करीबियों में रहा हूं। मैंने सब कुछ देखा है। लेकिन जितना समय ज़नता और अपने विधायकों के लिए माननीय जय राम जी देते हैं, उस हिसाब से मैं ईमानदारी के साथ कह

रहा हूं कि बारीयों वाला सिलसिला अब खत्म हो गया है। यह जो अब मुख्य मंत्री हैं, इनके पीछे इस तरफ जितने लोग बैठे हैं, वे इनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, इनके साथ थे और बिल्कुल साथ रहेंगे। आपके लिए (विपक्ष) थोड़ा चिन्ता का विषय है। राजा साहब की अब यह सातवीं पारी है, पता नहीं इसके बाद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हम इनके हितैषी है। लेकिन इनके बाद खींचातानी बहुत रहेगी।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

15-03-2018/1850/NS/HK/2

उपाध्यक्ष महोदय, यहां से सुक्खु भाई चले गये हैं, मेरा इनके साथ बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। जब ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो मैं भी इनके साथ था। वे यहां इस सदन में मौजूद नहीं हैं। राजा साहब जब मीटिंग में बैठते थे तो सुक्खु भाई जी पीछे बैठते थे और इनके साथ कोई नहीं बैठता था कि राजा साहब की नज़र उसके ऊपर न पड़ जाये। यह बात सही है कि राजा साहब जिससे दोस्ती रखते हैं, प्यार करते हैं, उसको ठीक जगह पहुंचा भी देते हैं और जिसके ऊपर गेड़ा रखते हैं, उसको चारों खाने चित्त भी कर देते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। मुझे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने का मौका मिला है। एक महीना नौ दिन के भीतर मुख्य मंत्री जी मंडी और कांगड़ा के प्रवास पर गये और वहां पर इन्होंने करोड़ों रुपये की जो भी विधायकों ने मांगे की, इन्होंने उन मांगों को माना और बज़ट में उनके लिए प्रावधान भी किया है। मैंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र में इनके दस कार्यक्रम करवाये। इन्होंने मुझे बिजली बोर्ड का एक डिवीज़न, पी0एच0सी0 को अपग्रेड करके सिविल अस्पताल और एक वेटरीनरी अस्पताल दिया तथा एक सब-हैल्थ सैंटर भी दिया है। मैंने जो कुछ मांगा, मुख्य मंत्री जी ने दिया है। इसके साथ-साथ कांगड़ा के जो निवासी हैं, ये मुख्य मंत्री जी के बहुत-बहुत आभारी हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत बड़ा सम्मान समारोह करवाऊंगा। मैं पहली बार जिला कांगड़ा में आलू चिप्स फैक्टरी के लिए एक पत्र लिख कर दे आया था और मुख्य मंत्री महोदय जी से बात भी की थी,

15.03.2018/1855/RKS/एच.के.-1

श्री अरुण कुमार...जारी

उन्होंने पहली बार कांगड़ा व कुल्लू के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। उसमें हमें एक उम्मीद जगी। हमारे किसान जो आलू की खेती करते हैं, वे 20 रुपये किलो बीज खरीदते हैं। लेकिन जब आलू बेचने की बारी आती हैं तो वे 5 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। उसके लिए हमें जगह आईडैंटिफाई करनी है और यह जगह हम कांगड़ा जिला के सभी माननीय सदस्य बैठकर आईडैंटिफाई करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिला कांगड़ा के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री अरुण कुमार जी, कृपया वाइंड-अप कीजिए।

श्री अरुण कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबसे अंत में बोलने की बारी आई है। अतः आप मुझे बोलने का समय दीजिए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अंतिम वक्ता तो श्री अर्जुन सिंह जी हैं।

श्री अरुण कुमारः उपाध्यक्ष जी, आपने इस माननीय सदन का दो-तीन बार समय एक्सटैंड किया है तो कृपया आप कम-से-कम 20 मिनट और समय एक्सटैंड कर दें।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, हम आपकी भावनाओं की बड़ी कद्र कर रहे हैं। लेकिन अब व्यवस्था ऐसी दी हुई है।

श्री अरुण कुमारः उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहूंगाः-

समय जिसका साथ देता है, बड़ों-बड़ों को वह मात देता है,
अमीर के घर पर बैठा कौआ सबको मोर लगता है और
गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है।
इन्सान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं,
इन्सान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं।
चर्चा जब उसकी बुराई पर हो तो गुंगे भी बोल पड़ते हैं।

15.03.2018/1855/RKS/एच.के.-2

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड-अप।

श्री अरुण कुमारः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जो हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं इन सबके साथ चलने से ही प्रदेश निरंतर तरक्की की तरफ जाएगा। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में चुनावों के दौरान आधी-अधूरी बिल्डिंग्स के उद्घाटन कर दिए गए। नगरोटा में नगरोटा सिविल अस्पताल की घोषण हुई थी लेकिन आज उसकी हालत देखें तो मैं आदरणीय परमार जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा की उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। भारत सरकार से एक एडवांस टैक्निकल इंस्टीट्यूशन्ज, गुसल की मंजूरी हुई। हमारे बीच हमारे बड़े भाई ठाकुर साहब बैठे हैं मैं उनसे भी इसके लिए गुजारिश करता हूं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप कीजिए।

श्री अरुण कुमारः उपाध्यक्ष जी, बड़ोग कॉलेज के लिए 6 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट था लेकिन उसमें एक लाख रुपये टोकन मनी है। हमारे बीच में हमारे माननीय मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी भी बैठे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बाते हैं और इनकी लिस्ट बहुत लम्बी है। समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा न बोलते हुए एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। गौ-सदन के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ा स्टैप लिया है। आपने भी इसके बारे में सोचा होगा लेकिन सोचने और करने में बहुत अंतर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में आवारा पशुओं के कारण तीन नौजवान व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। क्योंकि जब आवारा पशु सड़कों में चलते हैं तो जो लोग मोटरसाईकिल या स्कूटी में आते हैं, वे उन आवारा पशुओं से कई बार टकरा जाते हैं। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर लगभग 500 आवारा पशु हैं। मैं यह बात बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे 5 प्रतिशत वोट उस वजह से भी मिले हैं। क्योंकि मैंने कहा था जब मैं चुनाव जीतूंगा तो सबसे पहले गौ-सदन बनाऊंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए मंदिरों से चढ़ावे का 15% और शराब में 1 रुपया टैक्स लगाकर जो प्रावधान किया है उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं कोई ऐसे शब्द बोल गया हूं, जिससे किसी के मन को ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अपने उन शब्दों को वापिस लेना चाहता हूं। मैं इस बजट का भरपूर

समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

15.03.2018/1855/RKS/एच.के.-2

उपाध्यक्षः अभी एक वक्ता और है इसलिए माननीय सदन का समय सांय 7.20 बजे तक बढ़ाया जाता है।

माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राणा जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राणाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री अरुण कुमार जी ने कहा कि अगर इन्क्वायरी करवायेंगे तो (***) इस वाक्य को सदन की कार्यवाही से बाहर निकाला जाए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अगर इस तरह का कोई अनपार्लियामैंट शब्द होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा।

————————————————————————————————

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

15.03.2018/1900/DT/AG-1

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य अर्जुन सिंह को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री अर्जुन सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यावाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कि आपने मुझे समय दिया और समय भी इस ढंग से दिया कि अगर आप अल्फाबेटिकली चलते तो (ए) सबसे पहले आना था। दोनों (ए) सबसे लास्ट गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट 2018-2019 के लिए इस माननीय सदन में रखा है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पहली बार इस सदन में चुनकर आया हूं और ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आया हूं। जहां लगातार 37 वर्ष में अगर आप अढ़ाई-अढ़ाई वर्ष निकाल दें, तो कांग्रेस का शासन रहा, उनका प्रतिनिधि रहा इस विधान सभा क्षेत्र में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे समय मिला है। मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में कोई भी ऐसा वर्ग छुटा नहीं है, इस बजट में हर प्रकार के जिसमें अनुबंध कर्मचारी और मिड-डे-मील वर्करज़ एस0एम0सी0 और मजदूरों का यहां जिनको कोई पुछता नहीं उनके वेतन में बढ़ौतरी की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी0डी0सी0 का सदस्य रहा हूं। जब सबसे पहले बी0डी0सी0 हिमाचल में आई 1989-1990 में आई और मुझे पता है बी0डी0सी0 के सदस्य जब बन जाते थे और अगला चुनाव आता था और सोचते थे, हमे क्या मिलेगा, हम कैसे लोगों के पास जायेंगे । मैं उसके बाद 1995 में जब हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार जिला परिषद् आई तब मैं उसका सदस्य चुना गया। हमे कुछ नहीं मिलता था, जिस मिटिंग के लिए जाते थे, शायद 200 या 250 रुपये मिलते थे। आज 13वें वित आयोग के तहत जब हमारी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में तो भी काफी पैसा जिला परिषद् और बी0डी0सी0 में जाता था। पिछली जो सरकार रही और 14वें वित आयोग में जिला परिषद् और बी0डी0सी0 के सदस्यों को खाली हाथ बिठा दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से

15.03.2018/1900/DT/AG-2

धन्यावाद करता हूं। मैं इस सत्र में आने से पहले एक बैठक में गया था, जहां जिला परिषद्, बी0डी0सी0 और चुने हुए प्रतिनिधि एक ब्लॉक में आये थे । तो सब जिला परिषद् और बी0डी0सी0 सदस्यों का कहना था कि अब इससे तो अच्छा होता कि हमारा चुनाव ही बंद कर दिया जाता। मैं आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी को दिल से बहुत-बहुत धन्यावाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इन्होंने जिला परिषद्, बी0डी0सी0 और दूसरे जो लोग चुने गए प्रतिनिधि है वार्ड पंचायत तक उनका मानदेय बढ़ाया है। जिला परिषद् और बी0डी0सी0 के लिए विकास के लिए बहुत सारे धन की व्यवस्था की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सनद में नया विधायक चुनकर आया हूं चार पांच दिन से बजट पर चर्चा चली थी और मैं देख रहा था कि मेरे मित्र सामने वाले पहली-पहली बार बोलने के लिए

थोड़ा डर रहे थे कि बोलना क्या है, सीनीयरज है। सीनीयर-जुनीयर का बड़ा सिस्टम है। मैने देखा जो गुड़िया कांड हुआ हमारी सरकार दो महीने में बनी और गुड़िया कांड का आज तक पता नहीं लग सका कि किसने किया। वो कांग्रेस के शासन में हुआ और जो वहां आज फर्क देखिए हमारी सरकार में श्री जय राम ठाकुर की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में अंतर देखिए। कांग्रेस की सरकार में कितना बड़ा कांड हो गया और आज तक वो मुजरिम पकड़े नहीं गए। हालांकि उस समय के जो पुलिस अधिकारी हैं वो आज जेल में है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में ज्वाली विधान सभा क्षेत्र के जोली में एक कांड हुआ । लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। दुराचार हो रहे हैं। वहां जो कांड हुआ गुड़िया के साथ 24 घंटे के अन्दर ही अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देशों के अनुसार उस हत्यारे को जेल में डाल दिया।

मैं कहना चाहता हूं जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मनरेगा के लिए जहां आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी ने 100 दिन का समय दिया था वहां हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने इसको बढ़ा कर 120 दिन कर दिया है।

15.03.2018/1905/SLS-AG-1

श्री अर्जुन सिंह...जारी

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य को लेकर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे स्वास्थ्य संस्थान हैं परंतु उनमें डॉक्टर नाम की कोई चीज़ इस चुनाव रिजल्ट से पहले नहीं थी। मैं आदरणीय विपिन सिंह परमार जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वहां पर डॉक्टर्ज़ की भर्ती की। अब वहां लगभग हर अस्पताल में डॉक्टर्ज़ भेजे गए हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने आदरणीय विधायकों का इतना मान-सम्मान बढ़ाया है। विधायक निधि बढ़ाई, एच्छिक निधि बढ़ाई और हर विधान

सभा क्षेत्र के लिए एक सबसे बढ़िया फ़ैसला यह लिया कि 30-30 लाख रुपये का एक भवन हमें दिया गया है। अगर किसी विधान सभा क्षेत्र में कोई और इतना बड़ा भवन बनाना चाहता है तो विधायक निधि से विधायक अपना पैसा डाले और उसे 50 प्रतिशत पैसा प्रदेश सरकार देगी। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

अभी यहां चुनाव की बात की गई। मैंने भी 2012 में चुनाव लड़ा था। बहुत कम वोटों से मैं हार गया था। मेरे जो अपने युवा मित्र थे और परिवार के लोग थे वह भी इस लालच में कांग्रेस की तरफ चले गए कि हमें बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। आज एक मित्र बोल रहे थे कि 23000 लोगों को बेरोज़गारी भत्ता दिया गया था और वह भी तो हिमाचल प्रदेश के थे। मैं जानना चाहता हूं, क्या हिमाचल प्रदेश में 23000 लोग ही बेरोज़गार थे? वह भी किस समय दिया? जब पता लगा कि चुनाव आने वाला है। अब कांग्रेस के प्रत्यासी जहां-जहां जाते थे, नौजवान लोग पूछते थे कि आप दोबारा आ गए, बेरोज़गारी भत्ता तो हमें मिला नहीं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। एक सदस्य उधर से बोल रहे थे कि अब युवाओं को खोखा खोलने के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे शर्म भी आती है और मैं सोचता भी हूं कि ये जो चिट्टा, मिट्ठा, खट्टा आज प्रदेश में बिक रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता परंतु वह किसकी जिम्मेवारी है और किसके द्वारा शुरू किया गया है?

15.03.2018/1905/SLS-AG-2

इसलिए अगर कोई युवा ईमानदारी के साथ, सरकार की मदद के साथ अपनी रोजी-रोटी कमाता है, इसमें कोई जुर्म वाली बात नहीं है। मैं आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी को इसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने कम-से-कम स्वावलंबन की बात तो कही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इतना बढ़िया बजट है, जिसमें कोई वर्ग छूटा नहीं है, मैं इसका प्रशंसा करता हूं।

इसके साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा अचंभा लगता है, वोट के लिए भी हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बड़े संघर्ष के बाद यहां पहुंचे हैं। मैं यहां पर स्पष्ट कहना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गऊ माता की पूजा न करता हो। मुझसे पहले यहां जो विधायक रहा, वह गऊ माता को व्हटस ऐप पर क्यों अश्लील बातें लिखता था? मैं तो इस सदन में आकर समझा जहां और मित्र भी गऊ माता की चर्चा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जब हम सूत्र करते हैं तो क्या गऊ माता का मूत्र या गूंत्र पिलाते हैं या नहीं पिलाते हैं? हमारे हिंदु सनातन धर्म में चाहे जीना हो, चाहे मरना हो; गऊ माता के गूंत्र से ही हम लोग अपने आपको पवित्र करते हैं, अपने घर को पवित्र करते हैं। जो नहीं करता, वह बता दे। इसलिए मैं कहता हूं कि सदन में भी गऊ माता की पूजा की बात हो। हम कहते हैं कि अवारा पशु हैं लेकिन उन्हें छोड़ता कौन है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और इस सदन से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप चाहे 100 गौशालाएं खोल दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए मूल में जाना पड़ेगा। गऊ को छोड़ता कौन है? जब तक वह दूध देती है तब तक गऊ को लोग पकड़े रखते हैं या गौशाला में रखते हैं। लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम उसको छोड़ देते है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि गऊ माता जिसके घर में है, वहां उनकी संख्या गिनी जाए और इसके लिए कोई नियम बनाया जाए।

15/03/2018/1910/RG/DC/1

श्री अर्जुन सिंह-----जारी

इसलिए मैं माननीय सदन से कहना चाहूंगा कि वह नियम सर्वसम्मति से पास होना चाहिए और गऊ माता के लिए अशलील भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अचम्भे की बात है कि यहां लोग आर.एस.एस. की बहुत आलोचना करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। इसके सैंकड़ों विकल्प हैं और इसके सैंकड़ों प्रकल्प चलते हैं जो गरीबों की और समाज

की सेवा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समाजवादी एवं हिन्दूवादी विचाराधारा का एक संगठन है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। हममें से अधिकांश लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सिपाही हैं और हम उस संगठन से निकले हैं जो मातृभक्ति एवं देशभक्ति हमें सिखाता है। इसलिए संघ के खिलाफ बोलना सबसे बड़ा जुर्म और एक अपराध है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री अर्जुन सिह : मेरे से पूर्व जो यहां मेरे यहां से प्रतिनिधि रहे। आप अन्दाजा लगाइए कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में पूरे प्रदेश को पानी देने वाला वहां का प्रतिनिधि रहा। परन्तु आज भी 16-17 पंचायतों में पीने-का-पानी लोगों को नहीं मिलता। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक सिधाता नहर बनी। उसमें 107 करोड़, 98 लाख रुपये खर्च हुआ। लेकिन किसानों के खेतों में पानी नहीं जा रहा। यह कांग्रेस के शासन में हुआ। इसमें एक और बहुत खास बात है कि इस नहर को कम्पलीट करके इसका उद्घाटन वर्ष 2015 में कर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें जो त्रुटियां रही हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। वैसे तो सरकार ने पहले ही इसके लिए एक इन्क्वायरी मार्क की है। मैं इसके अतिरिक्त और भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जहां भी सिंचाई का काम हो, ईमानदारी से हो। --(घण्टी)---मेरे चुनाव क्षेत्र में एक सूखाहार नहर है जो नगरोटासूरयां में पड़ती है। मुझसे पहले जो कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे, वे लोगों को उसका सब्जबाग दिखाते रहे, लेकिन आज तक वह नहर नहीं बनी। इस नहर के लिए 153 करोड़ रुपये के बजट का अन्दाजा है। इससे 2186 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होनी है। मैं माननीय मंत्री जी

15/03/2018/1910/RG/DC/2

से प्रार्थना करुंगा कि इस नहर की तरफ ध्यान दिया जाए और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि हमारे यहां वर्ष 1998 में लगभग बीस वर्ष पहले समलाना में ज्वाली विधान सभा क्षेत्र के पास एक शराब की फैक्ट्री खुली।

उसका नाम टैपशियल बेवरीज लिमिटेड रखा गया। मुझे नहीं पता कि किन कारणों से उस फैक्ट्री को खटाई में डाल दिया गया। हमारे क्षेत्र की बहुमूल्य 189 कनाल जमीन लीज पर दी गई, लेकिन आज तक उस फैक्ट्री में एक पैसे का काम नहीं हुआ। वहां केवल चारदीवारी की गई है। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ---(घण्टी)---

उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन सिंह : मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय एवं पूज्यनीय माननीय उद्योग मंत्री जी जो यहां बैठे हैं, इनसे भी इस बारे में प्रार्थना की है। मैं एक और बात यहां कहना चाहता हूं। जहां ज्वाली में उद्योग विभाग की जमीन है, बहुत अचम्भे की बात है कि मुझसे पहले यहां जिन्होंने 35-37 साल शासन किया, उन्होंने एक स्टील इण्डस्ट्री के नाम से वह जमीन अपने नाम करवा ली। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसकी इन्क्वायरी की जाए कि बात क्या है? वहां उन्होंने स्टील की इण्डस्ट्री लगाई है। चुनाव से थोड़े दिन पहले इस इण्डस्ट्री की जमीन में पहले एक आई.टी.आई चलती थी, उसके लिए 6-7 पार्ट बने थे। उन 6-7 पार्ट्स को कांग्रेस के कुछ लोगों को बिना किसी सूचना के

15/03/2018/1915/MS/HK/1

श्री अर्जुन सिंह जारी-------

नीलामी करके उनको दे दिया। आज तक उसमें कोई कारोबार नहीं चलता। इसके लिए भी माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसकी भी पूरी छानबीन होनी चाहिए। मेरा यह कहना चाहता हूं कि जिस स्थानीय पंचायत की जमीन है वहां के किसी बेरोज़गार को वह जमीन नहीं दी गई। एक मंत्री के बेटे के नाम पर पूरा पट्टा काट दिया गया और लीज पर जमीन दे दी गई। इसमें भी मेरी माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि इस पर कार्रवाई की जाए। उपाध्यक्ष जी, मेरी बोलने की बारी सबसे अंत में आई है और अंत में बोलने वाले को कोई नहीं सुनता है इसलिए आप तो सुन लें। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र पड़ता है,

उपाध्यक्षः आप दो मिनट में माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन सिंहः वह पौंग डैम आउस्टिज का क्षेत्र पड़ता है। सबसे ज्यादा पौंग डैम आउस्टिज मेरे विधान सभा क्षेत्र में रहते हैं। वर्ष 1972 में उन्हें विस्थापित कर दिया गया और आज तक उनको कोई ठिकाना नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इनके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए। जब चुनाव आता है तो कांग्रेस वाले भी पौंग बांध आउस्टिज के लिए हरे-हरे बाग दिखाने लग जाते हैं लेकिन 37 वर्षों में उनके लिए कुछ नहीं किया गया। उपाध्यक्ष जी, 37 वर्ष जिन्दगी के बहुत लम्बे होते हैं। वहां के लोगों को अर्जुन सिंह से बहुत उम्मीद है। उपाध्यक्ष जी, पौंग डैम आउस्टिज का मामला तो मैंने सदन के ध्यान में ला दिया लेकिन मेरी एक और बड़ी समस्या है। हमारे पौंग बांध में जहां मछुआरे हैं वे मछलियों का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय ध्वाला जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि जब हमारी सरकार प्रदेश में थी तो मछुआरों का बीमा होता था। मछुआरों को लगाने के लिए जाल मिलते थे। कांग्रेस ने पिछले वर्षों में एक नया कानून बना दिया कि वे सूर्य निकलने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद झील में नहीं जा सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस कार्य के लिए हमारी 15 फीशरीज सोसाइटीज हैं और

15/03/2018/1915/MS/HK/2

3200 से लेकर 3500 तक परिवार वहां इस कार्य में संलिप्त हैं। उनकी रोजी-रोटी और बच्चों की पढ़ाई इसी काम से चलती है। कृषि मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं। उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो नीतियां आदरणीय श्री ध्वाला जी ने बनाई थी, अब शायद वीरेन्द्र कंवर जी के पास यह मंत्रालय है तो जो ध्वाला जी ने अपने शासनकाल में नीति चलाई थी उसको लागू किया जाए।

उपाध्यक्ष जी, अंत में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मुझे सुबह बड़ा अचम्भा हुआ। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूं और इस सदन में बड़े-बड़े विद्वान बैठे हैं। मैं अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि 68 लोगों के बीच में मेरी गिनती है। माननीय उपाध्यक्ष जी, सुबह विपक्ष के भाई संस्थानों के नाम से सदन से बाहर चले गए कि स्कूल बन्द नहीं होने चाहिए।

मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि मेरा एक स्कूल गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल.., आगे नाम नहीं लूंगा। जहां है वह शिमला में है और जहां मेरा विधान सभा क्षेत्र है.., मैं ज्वाली की बात कर रहा हूं। मैं शिमला की बात नहीं कर रहा हूं केवल उदाहरण दे रहा हूं। वहां 500 मीटर के पास एक और स्कूल खोल दिया। स्कूल खोल दिया तो अच्छी बात है क्योंकि विकास होना चाहिए और संस्थान खुलने चाहिए लेकिन वह स्कूल जुलाई, 2017 में खोला गया। मुझे आज सुबह बड़ा अचम्भा हुआ जब मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि मुझे बताओ कि इसमें बच्चों की संख्या कितनी है। आप हैरान होंगे वहां छठी से लेकर दसवीं तक सिर्फ 69 बच्चे हैं। मैं हाई स्कूल की बात कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे अंत में बोलने का मौका मिला है इसलिए मुझ पर थोड़ी कृपा करें। आप देखिए, जहां जमा-दो का स्कूल है, वह स्कूल सितम्बर में चुनाव से एक महीना पहले खुला और वहां एक साल से स्टाफ बैठा है लेकिन कोई बच्चा उस स्कूल में नहीं है। अब आप ही बताइए कि इसके लिए क्या किया जाए? 500 मीटर पर एक और स्कूल है। अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी को जो हमारे मसीहा हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, मुझसे पहले

15/03/2018/1915/MS/HK/3

जो वहां से जन-प्रतिनिधि रहे हैं, वे मुख्य संसदीय सचिव (शिक्षा)रहे हैं लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि 37 साल राज करने के बाद भी ज्वाली विधान सभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं दे सके। मैं भाग्यशाली हूं कि मुख्य मंत्री पहली बार मेरे विधान सभा क्षेत्र में गए।

15.03.2018/1920/जेके/एचके/1

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप एक मिनट बैठिए। चूंकि जो 20 मिनट का समय बढ़ाया था वह हो गया है अब मान्य सदन का समय पांच मिनट और एक्सटैंड किया जाता है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नये हैं और हम पूरा सहयोग दे रहे हैं लेकिन आप भी सदन की अनुमति लिए बिना समय बढ़ाते जा रहे हैं ।

उपाध्यक्षः मुकेश जी, कोई बात नहीं । यहां पर भी नयापन है।

श्री अर्जुन सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो इस माननीय सदन में 37 वर्ष रहे वे ज्वाली के लिए जो कि इतना बड़ा विधान सभा क्षेत्र है और वहां पर बहुत गरीबी है, ये वहां के लिए एक कॉलेज तक नहीं दे सके। उपाध्यक्ष जी, जो मेरा घोषणा पत्र था, जिसके ऊपर मैंने चुनाव लड़ा , 45 दिन के अंदर-अंदर श्री जय राम ठाकुर जी अभी वहां पर दौरा करके, उसको पूरा करके आए हैं।

आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी यहां पर नहीं बैठे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता था। वह इसलिए कि उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला। मैं राजनीति में आया। मैं राम सिंह डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष रहा और माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने मुझे दो महीने के लिए जेल में डाल दिया था सरकारी कॉलेज करने के लिए । अगर वे यहां पर बैठे होते तो मुझे खुशी होती, मैं उनसे नहीं मिला हूं। उन्होंने मुझे जो जेल कटाई उसकी बदौलत मैं राजनीति में आया और आज इस माननीय सदन में पहुंचा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, कृपया मैं अन्त में एक छोटी सी बात और कर दूं।

उपाध्यक्षः माननीय अर्जुन सिंह जी, अब हो गया। कृपया वाइंड अप करिए।

श्री अर्जुन सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जो उद्घाटन की बात करते हैं, मैं तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा। हमारे नगरोटा सूरियां में 2 फरवरी, 2017 को एक तहसील खुली । एक तहसील कोटला में 2 फरवरी, 2016 को खुली। दोनों के फट्टे लग गए परन्तु आज तक वहां पर एक ईंट नहीं लगी। हमारे सभी दोस्त बोल रहे थे कि

15.03.2018/1920/जेके/एचके/2

हम 20 साल सत्ता में रहेंगें । मैं भी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार पूरे 20 साल इस प्रदेश में शासन करेगी और मैं विपक्ष को भी बोलना चाहता हूं कि हम झूठ नहीं बोलते। जिस धैर्य के साथ श्री जय राम ठाकुर जी लोगों को अपना समय देते हैं, मैंने कई बार देखा है कि मुख्य मंत्री के पास लोग फटकने तक नहीं देते। आज एम.एल.ए. अपने घर के सदस्य की तरह उनके पास जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं जैसे मेरे एक भाई ने कहा, श्री जय राम ठाकुर जी, जय आप रख लीजिए, राम तो श्री राम है और

ठाकुर श्री कृष्ण है। मैं एक और छोटी सी बात कह दूं कि विपक्ष वाले मित्र बोलते हैं कि एक भाई आज 20 वर्ष की गोली दे गया। अगर गोली इतनी कड़वी है तो बार-बार बोलना क्यो? अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने जो जोरदार बजट इस विधान सभा में पेश किया, मैं उसका दिल से, दिल की गहराइयों से और समस्त जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीराम।

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार 16 मार्च, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 15 मार्च, 2018 **सचिव।**

******